



One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly

CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

50 years of Kesavananda Bharati case.

Brain economy.

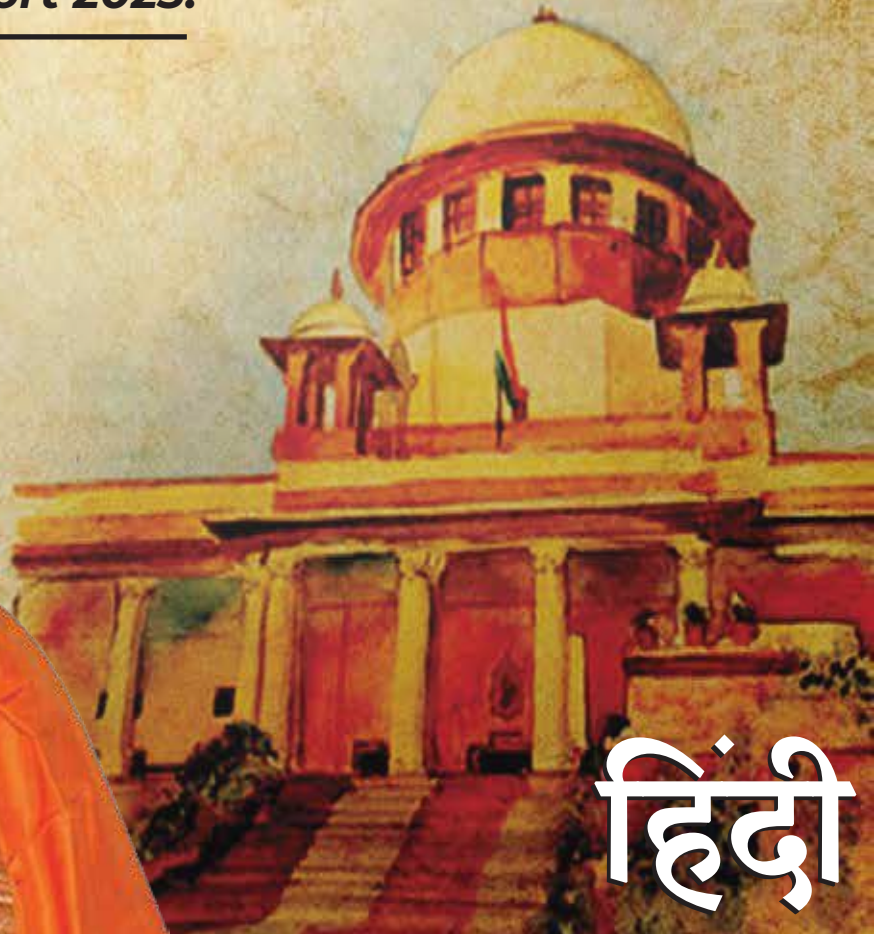
Glacial Retreat: Causes and Impact.

Genome Sequencing and the Genome India Project.

Global Food Policy Report 2023.

Earth4All Initiative.

PSLV-C55 mission.



हिंदी

IAS BABA



baba's gurukul



Under The Guidance Of
Mohan Sir
(Founder, IASbaba)

The Guru-shishya Parampara Continues....

Under The Guidance Of **Mohan Sir (Founder, IASbaba)**

78 Prelims Tests

95 Mains Tests

Weekly Assignments
Monitored by Mentor

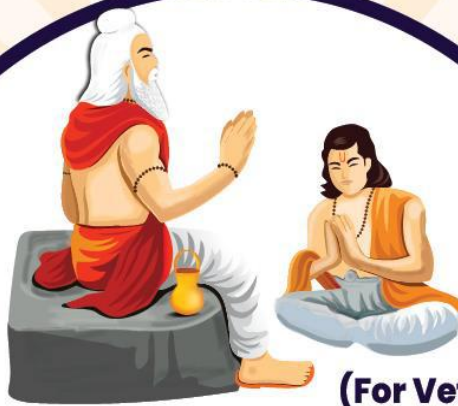
Performance Tracker

Module Wise
Classes of Choice

Current Affairs
Classes

Live solving of
Prelims PYQ'S by
Prelims Experts

Enhanced Peer
Group Activities



(For Veterans)

GURUKUL ADVANCED 2024

A Rigorous, Intensive Tests & Mentorship Based Programme

📍 **Bangalore** 🌐 **Online**

ADMISSION OPEN Start's from 26th June

Scan Here



to Know More



www.iasbaba.com



support@iasbaba.com



91691 91888



GSAT-7B satellite

PRELIMS	5	क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) कानून में बाजार	21
राजव्यवस्था और शासन	5	सीमित प्रयोजन समाशोधन निगम (LPCC)	22
प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMNF)	5	सूचनाओं का स्वचालित आदान-प्रदान (AEOI) फ्रेमवर्क	23
महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना	5	अंतरराष्ट्रीय संबंध	24
गिग वर्कर्स	6	संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष	24
नौवीं अनुसूची	6	गुड फ्राइडे समझौता	24
प्राकृतिक न्याय	7	शिकागो कन्वेंशन	25
दया याचिका	8	वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023	25
भारत में जल निकायों की पहली जनगणना	9	केरेबियन समुदाय और आम बाजार (CARICOM)	26
विश्व जनसंख्या की स्थिति (SOWP)	10	इतिहास, कला और संस्कृति	28
न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग	11	बाबू जगजीवन राम	28
प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का सिद्धांत	12	कौशांबी महोत्सव-2023	28
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (एसईईआई) 2021-22	12	बिदरी शिल्प	29
मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 5(4)	13	हक्की पिक्की	29
अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली (Inter-Operable Criminal Justice System)	13	थिरुनेली मंदिर	30
फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स 2022	14	तुगलकाबाद फोर्ट	30
परमाणु दायित्व कानून	15	उत्तरामेरुर शिलालेख	31
CGTMSE (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट)	16	रामकृष्ण मिशन	31
अर्थव्यवस्था	18	महाड़ सत्याग्रह	32
CPTPP - ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता	18	कामाख्या मंदिर कॉरिडोर	33
एसबीए (ASBA), ब्लॉकड राशि द्वारा समर्थित आवेदन	18	भूगोल	34
किसान उत्पादक संगठन (FPO)	19	सी-माउंट	34
REITs और InvITs इंडेक्स	20	इंदिरा गांधी नहर	34
डब्बा ट्रेडिंग (Dabba Trading)	20	नागरी दुबराज चावल	35
मिशन50K-EV4ECO	21	Earth4All पहल	36
		ताड़वान जलडमरूमध्य	37
		जोजिला सुरंग	37



Tughlaqabad Fort

जीरो शैडो डे	37	मेग्नेटोरिसिस्टेस	53
कामचटका प्रायद्वीप	38	हार्पून मिसाइल	53
आइंस्टीन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत	38	ओल्किलुओटो 3 रिएक्टर	54
ELVES (विद्युत चुम्बकीय पल्स स्रोतों के कारण प्रकाश का उत्सर्जन और बहुत कम आवृत्ति गड़बड़ी)	39	ज्यूपिटर आइसी मूनस एक्सप्लोरर (जूस)	54
पर्यावरण	41	भारत का पहला 3डी-मुद्रित डाकघर	55
प्रोजेक्ट टाइगर	41	विस्तारित रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ER-ASR)	55
टाइगर सेंसस 2022	41	टेम्पो यानी ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट	56
दिबांग वन्यजीव अभयारण्य	42	रक्षा	57
एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान	42	SLINEX-23	57
विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट	43	विविध	57
सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य	43	डेडनेमिंग	57
कुद्रेमुख रेंज	44	डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	57
सुखना वन्यजीव अभयारण्य	44	सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार	58
उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन (PRET) पहल	45	MAINS	60
बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य	45	60	
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	47	राजव्यवस्था और शासन	60
कालाजार	47	भारत में न्यायिक पेंडेंसी	60
कैल्शियम कार्बाइड	47	केशवानंद भारती केस के 50 साल	61
PSLV-C55 मिशन	48	अर्थव्यवस्था	62
ब्लास्टोमाइकोसिस (Blastomycosis)	49	UPI लेनदेन शुल्क में परिवर्तन: आपके वॉलेट पर प्रभाव	62
अमोघा-III	49	ब्रेन इकोनॉमी	63
GSAT-7B उपग्रह	50	अंतरराष्ट्रीय संबंध	66
हीमोफीलिया	50	विदेश व्यापार नीति 2023	66
लॉकबिट रैसमवेयर	51	DM	68
डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत	51	आकस्मिक सूखा (Flash drought)	68
पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन (आरएलवी लेक्स)	52	पर्यावरण	71
सोडियम साइनाइड	52	ह्यूमन कम्पोस्टिंग: ए ग्रीनर वे टू डाई	71
		ग्लेशियल रिट्रीट: कारण और प्रभाव	72



इतिहास, कला और संस्कृति	75	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	79
वैकोम सत्याग्रह	75	जीनोम सीक्वेंसिंग और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट	79
सामाजिक मुद्दे	77	PRACTICE QUESTIONS	81
मानसिक बीमारी: भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय	77		

PRELIMS



राजव्यवस्था और शासन


प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMNF)

खबरों में क्यों: भारत सरकार ने रसायन मुक्त और जलवायु-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिये एक अलग तथा स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMNF) शुरू किया है।

इसके बारे में:-

- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) को बढ़ाकर 2023-24 से एक अलग और स्वतंत्र योजना के रूप में तैयार किया गया।
- यह योजना 2023 से 2026 तक लागू की जाएगी।

किसानों को लाभ:-

- किसानों को एकमुश्त कृषि खाद उत्पादन अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन:-
 - NMNF के तहत किसानों को ऑन-फार्म इनपुट उत्पादन बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये तीन वर्ष हेतु प्रतिवर्ष 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- चैंपियन किसानों और सीआरपी द्वारा किसानों का प्रशिक्षण
- प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन:
 - गंगा बेल्ट में 100 एफपीओ
 - देश भर में अन्य 400 एफपीओ
- किसान फील्ड स्कूल:-
 - इसमें जागरूकता पैदा करने के लिए गतिविधियां शामिल होंगी।

भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) के बारे में:-

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है।
- यह परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत एक उप-मिशन है, जो सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के दायरे में आता है।
- यह बायोमास मल्लिचंग पर प्रमुख तनाव के साथ खेत में बायोमास रीसाइक्लिंग पर ध्यान केंद्रित करता है
 - गाय के गोबर-यूरिन योगों का उपयोग और
 - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों का बहिष्करण।
- बीपीकेपी के तहत, विभिन्न राज्यों में 2000 हेक्टेयर के 600 प्रमुख ब्लॉकों में 12 लाख हेक्टेयर को कवर करने की दृष्टि से प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण और निरंतर सहयोग, प्रमाणन और अवशेष विश्लेषण के लिए 3 वर्ष के लिए 12200 / हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह योजना पीजीएस इंडिया कार्यक्रम के तहत पीजीएस-इंडिया प्रमाणन के अनुरूप है।
- आठ राज्यों- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और झारखंड ने इस योजना का चयन किया है।

अवश्य पढ़ें: नेचुरल फार्मिंग

महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना

संदर्भ: हाल ही में, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) 2023 को अधिसूचित किया गया है।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी) 2023 के बारे में:-

- यह स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए एकमुश्त लघु बचत योजना है।
- यह मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन होगा।
- दो वर्षों के लिए लघु बचत प्रमाणपत्र पर 7.5% की निश्चित ब्याज दर होगी।
- जमा महिला या बालिका के नाम पर किया जा सकता है।
- अधिकतम जमा राशि 2 लाख रुपए रखी गई है और योजना में आंशिक निकासी की सुविधा भी होगी।



पात्रता:-

- योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदन महिला अपने लिए या नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक द्वारा किया जा सकता है।

जमा सीमा:-

- एक महिला द्वारा या नाबालिग लड़की के नाम पर अभिभावक द्वारा कितने भी MSSC खाते खोले जा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये है।

ब्याज दर:- सरकार ने MSSC खाते में जमा राशि पर 7.5% ब्याज नोटिफाई किया है

परिपक्वता और भुगतान:- जमा की तारीख से दो साल पूरे होने पर जमा परिपक्व हो जाएगा।

आंशिक निकासी:-

- एक MSSC खाताधारक को खाता खोलने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले एक बार पात्र शेष राशि का अधिकतम 40% तक निकालने की अनुमति होगी।

अवश्य पढ़ें: महिलाओं के लिए समर्थ पहल

गिग वर्कर्स

संदर्भ: राजस्थान सरकार राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 लाने वाली है, जिसमें गलत एग्रीगेटर्स के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं, जिसमें उन्हें राज्य में संचालन से रोकना भी शामिल है।

गिग इकॉनमी के बारे में:

- गिग इकॉनमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें संगठन कम समय के लिए श्रमिकों को काम पर रखते हैं या अनुबंधित करते हैं।
- सीधे शब्दों में कहें तो पद अस्थायी होते हैं, जो कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक अनुबंध होते हैं।
- ओला, उबर, ज़ोमेटो और स्विगी जैसे स्टार्टअप ने खुद को भारत में गिग इकॉनमी के मुख्य स्रोत के रूप में स्थापित किया है।

भारत और गिग इकॉनमी :

- वर्ष 2020 में, 77 लाख कर्मचारी गिग इकॉनमी से जुड़े थे।
- वर्ष 2029-30 तक गिग कार्यबल के 5 मिलियन कर्मचारियों तक बढ़ने की उम्मीद है।
- वर्तमान में लगभग 47% गिग कार्य मध्यम कुशल नौकरियों में, लगभग 22% उच्च कुशल नौकरियों में और लगभग 31% कम कुशल नौकरियों में हैं।

नौवीं अनुसूची

संदर्भ: हाल ही में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संविधान की नौवीं अनुसूची में दो संशोधन विधेयकों को शामिल करने की मांग की।

नौवीं अनुसूची के बारे में:-

- इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- ये न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित हैं।
- अनुसूची 1951 में संविधान का एक हिस्सा बन गई जब दस्तावेज में पहली बार संशोधन किया गया।
- यह नए अनुच्छेद 31B द्वारा बनाया गया था, जिसे 31A के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की

रक्षा करने और जर्मीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लाया गया था।

अनुच्छेद 31A

- यह कानूनों की 'श्रेणियों' को सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 31B

- यह विशिष्ट कानूनों या अधिनियमों की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 31B में एक पूर्वव्यापी संचालन भी है।

- जिसका अर्थ है कि यदि कानूनों को असंवैधानिक घोषित किये जाने के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, तो उन्हें उनके प्रारंभ के बाद से अनुसूची में शामिल माना जाता है और इस प्रकार वे कानून मान्य है।
- 0 हालाँकि अनुच्छेद 31B न्यायिक समीक्षा से बाहर है, सर्वोच्च न्यायालय ने अतीत में कहा है कि नौवीं अनुसूची के तहत भी कानून जाँच के लिये खुले होंगे यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट और आई. आर. कोएल्हो वनाम तमिलनाडु राज्य (2007):

- यह माना गया था कि प्रत्येक कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत परीक्षण किया जाना चाहिये यदि यह 24 अप्रैल, 1973 के बाद लागू हुआ है।
- इसके अलावा न्यायालय ने अपने पिछले फैसलों को बरकरार रखा और घोषित किया कि किसी भी अधिनियम को चुनौती दी जा सकती है और न्यायपालिका द्वारा जाँच के लिये खुला है यदि यह संविधान की मूल संरचना के अनुरूप नहीं है।
- साथ ही यह भी कहा गया कि यदि नौवीं अनुसूची के तहत किसी कानून की संवैधानिक वैधता को पहले बरकरार रखा गया है, तो भविष्य में इसे फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा विधेयक:-

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 76% कोटा का मार्ग प्रशस्त करने वाले दो संशोधन विधेयक पिछले दिसंबर में राज्य विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए थे।
- इसने ओबीसी के लिए आरक्षण को मौजूदा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया, जबकि अनुसूचित जाति समुदाय के लिए सार्वजनिक रोजगार और प्रवेश में 12% से 13% कर दिया।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32% आरक्षण अपरिवर्तित रखा गया था।
- इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 4% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया, जिससे आरक्षण की कुल सीमा 76% हो गई।
 - हालांकि, विधेयक राज्यपाल के पास सहमति के लिए लंबित हैं।

अवश्य पढ़ें: संवैधानिक (127वां) संशोधन बिल, 2021

प्राकृतिक न्याय

संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले ने प्राकृतिक न्याय और आनुपातिकता के मुद्दों पर प्रकाश डाला है।

इसके बारे में:-

- प्राकृतिक न्याय को सार्वभौमिक न्याय, पर्याप्त न्याय, या कार्रवाई में निष्पक्षता के रूप में भी जाना जाता है।
- यह ईश्वरीय कानून की एक आवश्यक अवधारणा है, जो समानता के कानून पर आधारित है।

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत :-

नैसर्गिक न्याय के मुख्य सिद्धांत इन दो कानूनी सूक्तियों पर आधारित हैं:

- नीमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ (Nemo Judex in Causa Sua) - इसका मतलब है कि कोई भी अपने मामले में जज नहीं होगा।
- 'ऑडी अल्टेरम पारेरम' (Audi Alteram partem) जिसका अर्थ है - दूसरे पक्ष को सुनो, कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

नैसर्गिक न्याय की पूर्वापेक्षाएँ:-

- पूर्वाग्रह, रुचि या पूर्वाग्रह का अभाव: न्यायाधीश को तटस्थ, निष्पक्ष और पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, यह प्राकृतिक न्याय की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है।
- पूर्वाग्रह के प्रकार:

- आर्थिक पक्षपात - यह विषय वस्तु में वित्तीय हित से संबंधित है।
- व्यक्तिगत पूर्वाग्रह - एक न्यायाधीश किसी पार्टी का रिश्तेदार, दोस्त या सहयोगी हो सकता है।
- आधिकारिक पूर्वाग्रह - जब किसी न्यायाधीश की विषय वस्तु में सामान्य रुचि होती है।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978

- इस मामले में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि भले ही कोई विशिष्ट कानून या किसी कानून में प्रावधान या की गई कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने के लिए नियम बनाए गए हों, जो किसी भी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित करता है, सुनवाई का उचित अवसर देने का कर्तव्य प्रकृति से निहित होगा।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल सभी अदालतों बल्कि न्यायिक निकायों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों पर भी बाध्यकारी हैं।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अपवाद:-

- जहां कोई कानून या अधिनियम स्पष्ट रूप से बाहर करता है या इसका कोई विशेष प्रावधान नियम की प्रयोज्यता को बाहर करता है।
- जहां कार्रवाई प्रकृति में विधायी है।
- जहां आवश्यकता का सिद्धांत लागू होता है।
 - आवश्यकता का सिद्धांत लागू होना: यदि कोई निर्णय अल्प सूचना पर तत्काल किया जाना है, तो नियम को बाहर रखा जा सकता है।
- जहां तथ्यों को स्वीकार किया जाता है या निर्विवाद किया जाता है, वहां स्वीकार किए गए तथ्यों को फिर से स्वीकार करने के लिए पार्टी को फिर से बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अदालत किए गए दाखिलों के साथ आगे बढ़ सकती है।
- जहां जांच गोपनीय होती है, वहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी हो सकती है।
- जहां निवारक कार्रवाई की जानी है।
 - उदाहरण के लिए धारा 144 CrPC, जहां तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, और दूसरे पक्ष को कोई उचित या नियत समय नहीं दिया जा सकता है।
- जहां सरकार के नीतिगत निर्णय के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो।

आनुपातिकता का सिद्धांत :-

- सिद्धांत की आवश्यकता है कि निर्णय या कार्रवाई उस उद्देश्य के अनुपात में होनी चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है।
- इसका अर्थ है कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया जाना चाहिए, इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए, और प्राप्त लाभ के संबंध में निर्णय या कार्रवाई से होने वाली हानि अत्यधिक नहीं होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के विचारों की भागीदारी के दावे की वैधता का मूल्यांकन इस परीक्षण पर किया जाना चाहिए कि क्या यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री है कि सूचना का गैर-प्रकटीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है।
- न्यायालय ने कहा कि न्यायालय "संरचित आनुपातिकता मानक" के आधार पर जनहित प्रतिरक्षा दावों की वैधता का आकलन कर सकते हैं।

अवश्य पढ़ें: जलवायु न्याय का अधिकार

दया याचिका

संदर्भ: हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों से कहा कि वे मौत की सजा पाए दोषियों की दया याचिकाओं पर फैसले में देरी न करें।

दया याचिकाओं के बारे में:-

- एक दोषी द्वारा अपनी सजा (विशेष रूप से मृत्युदंड) को कम सजा में बदलने के लिए दया याचिका दायर की जाती है।
- इसे क्षमादान याचिका/दलील या कार्यकारी क्षमादान भी कहा जाता है।
- राज्य के रिपब्लिकन प्रमुख से दया की मांग करना अपराधी का मूल अधिकार है।
 - भारत में, वह राष्ट्रपति होता है।
- सभी कानूनी उपायों के समाप्त हो जाने के बाद इसका प्रयोग किया जा सकता है।

- राष्ट्रपति (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत) या राज्यपाल (संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत) के पास याचिका दायर की जा सकती है।
- मौत की सजा के तहत एक दोषी दया याचिका दायर करने का पात्र है।
- लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी अपील को खारिज करने और पुलिस अधीक्षक (एसपी) द्वारा दोषी को सूचित करने के बाद सात दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

दया याचिका की प्रक्रिया :-

- मौत की सजा के तहत एक दोषी को सात दिनों की अवधि के भीतर दया याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है, जिस तारीख को जेल अधीक्षक ने उसे अपील खारिज करने या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति के बारे में सूचित किया हो।
- याचिकाओं को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
 - राष्ट्रपति कार्यालय कैबिनेट सलाह चाहता है।
 - गृह मंत्रालय द्वारा अपील की जांच की जाती है और मंत्रालय राष्ट्रपति को सिफारिशें देने से पहले संबंधित राज्य का विचार लेता है।
- दया याचिका से निपटने के लिए कोई लिखित प्रक्रिया नहीं है।
- राष्ट्रपति की क्षमा/अस्वीकृति/विलंब भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है।
- हालांकि, अगर न्यायालय को पता चलता है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय की प्रक्रिया मनमाना या अनुचित नहीं थी, तो निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

अवश्य पढ़ें: भारत में मौत की सजा

भारत में जल निकायों की पहली जनगणना

संदर्भ: हाल ही में, भारत में जल निकायों की पहली जनगणना हुई।
भारत में जल निकायों पर पहली जनगणना के बारे में:-

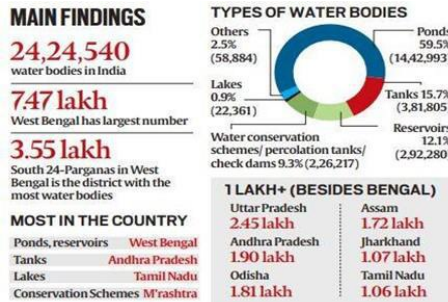


IMAGE SOURCE: India's first water body census: How was it done, what does the report say |

Explained News, The Indian Express

- देश भर में पहली बार जल निकायों की गणना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई।
- जनगणना भारत के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची प्रदान करती है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकाय जैसे तालाब, टैंक, झील, और बहुत कुछ शामिल है, और यह जल निकायों के अतिक्रमण पर डेटा एकत्र करती है।
- जनगणना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताओं और अतिक्रमण के विभिन्न स्तरों पर भी प्रकाश डाला और देश के जल संसाधनों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का खुलासा किया।
- सभी जल निकायों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस रखने के लिए छठी लघु सिंचाई जनगणना के अभिसरण में केंद्रीय प्रायोजित योजना, "सिंचाई जनगणना" के तहत जनगणना शुरू की गई थी।
- जनगणना में सिंचाई, उद्योग, मत्स्य पालन, घरेलू/पेय, मनोरंजन, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण आदि जैसे जल निकायों के सभी प्रकार के उपयोगों को भी ध्यान में रखा गया है।

मुख्य निष्कर्ष:-

- देश में 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई है, जिनमें से 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और केवल 2.9% शहरी क्षेत्रों में हैं।
- जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम हैं जो देश के कुल जल निकायों का लगभग 63% हैं।

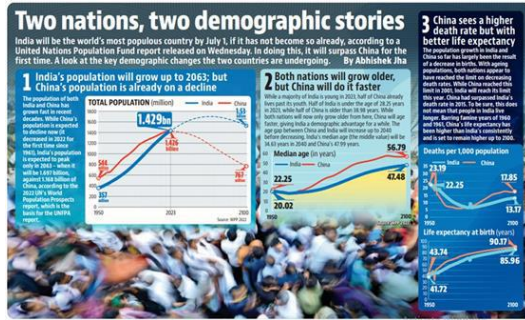
- शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शीर्ष 5 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम हैं।
- शीर्ष 5 राज्य जिनमें जल निकायों का प्रमुख उपयोग सिंचाई में होता है, ये झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात हैं।
- 78% जल निकाय मानव निर्मित जल निकाय हैं जबकि 22% प्राकृतिक जल निकाय हैं।
- सभी गणना किए गए जल निकायों में से 1.6% (38,496) जल निकायों पर अतिक्रमण होने की सूचना है, जिनमें से 95.4% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और शेष 4.6% शहरी क्षेत्रों में हैं।
- 23,37,638 जलाशयों के जल विस्तार क्षेत्र की जानकारी दी गई।
- इन जल निकायों में से 72.4% का जल विस्तार क्षेत्र 0.5 हेक्टेयर से कम है, 13.4% का जल विस्तार क्षेत्र 0.5-1 हेक्टेयर के बीच है, 11.1% का जल विस्तार क्षेत्र 1-5 हेक्टेयर के बीच है और शेष 3.1% जल निकायों का जल विस्तार क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक है।

अवश्य पढ़ें: भारत में जल संकट

विश्व जनसंख्या की स्थिति (SOWP)

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट- स्टेट ऑफ़ वर्ल्ड पॉपुलेशन (SOWP) जारी की है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

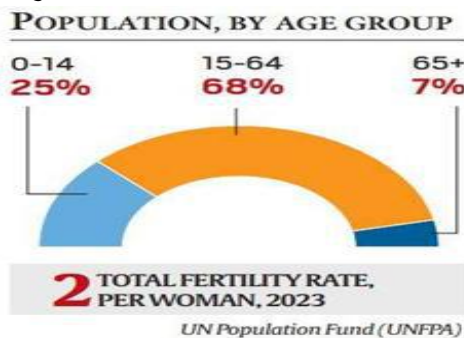


Source: Hindustan Times

- विश्व की जनसंख्या 8,045 मिलियन है।
- जनसंख्या में सबसे बड़ी हिस्सेदारी 15-64 वर्ष (65%) के बीच है, इसके बाद 10-24 वर्ष (24%) और 65 वर्ष से अधिक आयु (10%) है।
- वर्ष 2022 में चीन और भारत में एशिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, प्रत्येक की जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक है।
- भारत अब चीन की आबादी को पीछेकर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है।
- वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की दर गिर गई है और 2020 से 1% से भी कम है।

भारत की जनसांख्यिकी:

आयु वर्ग:



Source: Indian Express

- 68 फीसदी 15-64 वर्ष के हैं और 26 फीसदी 10-24 वर्ष के हैं।
- **परिणाम:** भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जिसकी 50 फीसदी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है।

- भारत में प्रजनन दर लगातार गिर रही है और प्रति महिला 2.1 बच्चों से कम है।
- **गिरावट के कारण:** गर्भनिरोधक विधियों का उपयोग, गर्भधारण में अंतराल, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, परिवार नियोजन को प्रोत्साहन, धन और शिक्षा में वृद्धि।
- पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए यह 74 वर्ष से कम है।

मुख्य अनुमान:

- वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन तक बढ़ सकती है।
- वर्ष 2050 तक अधिकतम वृद्धि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया जैसे देशों में केंद्रित होगी।
- यदि भारत की जनसंख्या वर्तमान गति से बढ़ती रही, तो यह अगले 75 वर्षों में वर्तमान मूल्य से दोगुनी हो जाएगी।

जनसंख्या वृद्धि के लिए आउटलुक

- नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की दर गिर गई है, और 2020 से 1 प्रतिशत से भी कम रही है।
- यह काफी हद तक घटती प्रजनन क्षमता के कारण है।
- लगभग दो तिहाई लोग किसी देश या क्षेत्र में प्रति महिला 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर के साथ रहते हैं (इसे "प्रतिस्थापन प्रजनन दर" या "शून्य-विकास प्रजनन दर" दर भी कहा जाता है)।
- 1950 में वैश्विक प्रजनन दर 5 थी।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वैश्विक आबादी के 60% ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। वर्ष 1990 में 40% ऐसे क्षेत्रों में रहते थे जहाँ प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे थी।

विकास के चालक के रूप में प्रवासन:

- यह अंतरराष्ट्रीय प्रवास है जो अब कई देशों में विकास का चालक है, इसे हम वर्ष 2020 में 281 मिलियन लोगों के अपने जन्म के देश के बाहर रहने के रूप में देख सकते हैं।
- युद्ध, अकाल और अन्य आपदाओं के कारण भी पलायन हुआ है।
- दक्षिण एशिया में प्रवासी के उच्चतम रुझान देखे जा सकते हैं, भारत में 2010 और 2021 के बीच 3.5 मिलियन का अनुमानित नेट ऑउटफ्लो देखा जा सकता है।
- इसी अवधि के दौरान पाकिस्तान में सबसे अधिक 16.5 मिलियन प्रवासी आए।

जन्म दर:

- प्रति महिला जन्म की औसत संख्या में निरंतर गिरावट के बावजूद, 1980 के दशक के अंत से जन्म की कुल वार्षिक संख्या लगभग 140 मिलियन पर स्थिर रही है।
- यह वैश्विक जनसंख्या के युवा आयु वितरण के कारण है।
- वर्ष 2021 में, दुनिया भर में 13.4 करोड़ बच्चे पैदा हुए।
- भविष्य में, प्रति महिला जन्म की औसत संख्या में लगातार गिरावट के बावजूद, 2040 और 2045 के बीच नवजात शिशुओं की संख्या सालाना 138 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।
- वर्ष 2021 में, दुनिया भर में सबसे अधिक जन्म दो सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र—एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में हुए।

जीवन प्रत्याशा:

- UNFPA द्वारा विश्व स्तर पर जनसंख्या वृद्धि के कारणों में से एक कारण जीवन प्रत्याशा में वृद्धि है।
- स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच और जीवन स्तर में सुधार के साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रजनन दर और मृत्यु दर गिर रही है।
- पुरुषों में जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष है जबकि महिलाओं में यह 76 वर्ष है।
- विश्व स्तर पर, जीवन प्रत्याशा वर्ष 2019 में 72.8 वर्ष तक पहुंच गई, 1990 के बाद से लगभग 9 वर्षों की वृद्धि हुई है।

न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग

संदर्भ: हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार को न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट की "पुनः जांच" करने की आवश्यकता हो सकती है।

न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग के बारे में:-

	<ul style="list-style-type: none"> • रंगनाथ मिश्रा आयोग को राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग भी कहा जाता है। • इसका गठन भारत सरकार द्वारा 2004 में किया गया था। • उद्देश्य: भारत में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देना। • महत्वपूर्ण सुझाव:- <ul style="list-style-type: none"> ○ अनुसूचित जाति आरक्षण कोटा के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले दलितों को अनुमति देना। • वर्तमान स्थिति:- <ul style="list-style-type: none"> ○ मिश्रा की रिपोर्ट को खारिज करते हुए, सरकार ने हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक नया आयोग गठित किया था। ○ "ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों से संबंधित लेकिन हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हुए लोगों" को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के सवाल पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो साल का समय दिया गया है। <p>अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग</p>
<p>प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि सरकार को अग्निपथ योजना को लागू करने के बजाय पुरानी प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए और प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत का हवाला दिया।</p> <p>प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत इक्विटी, निष्पक्षता और नैतिक विवेक के सिद्धांत पर काम करता है। • प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत का अर्थ है कि जब एक व्यक्ति कानूनी संबंध बनाने के इरादे से किसी अन्य व्यक्ति से एक स्पष्ट वादा करता है और बाद वाला व्यक्ति उस पर कार्य करता है, तो वह वादा उस व्यक्ति के लिए एक दायित्व बन जाता है जिसने वादा किया था। <ul style="list-style-type: none"> ○ इसलिए, फिर अपने शब्दों से पीछे हटना ठीक नहीं है। • विधि आयोग ने इस सिद्धांत के लिए 108वीं रिपोर्ट में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25A के रूप में एक नई धारा बनाने के लिए सुझावों की सिफारिश की। • ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस सिद्धांत के तहत राहत की उपलब्धता सुनिश्चित करते हों। • साथ ही, इसे पीड़ित पक्ष की रक्षा के लिए इक्विटी के आधार पर लागू किया जा सकता है। • भारत में एस्टोपेल का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 115 में शामिल साक्ष्य का एक नियम है। • प्रॉमिसरी एस्टोपेल का आवेदन अनुच्छेद 299 के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक प्रावधान को अमान्य कर सकता है, जो वादा करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत जवाबदेही के खिलाफ दी गई प्रतिरक्षा के बारे में बात करता है। <p>अवश्य पढ़ें: आवश्यकता का सिद्धांत (Doctrine of necessity)</p>
<p>राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (एसईईआई) 2021-22</p>	<p>संदर्भ: केंद्रीय ऊर्जा और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2021-22 की रिपोर्ट जारी की।</p> <p>इसके बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स (SEEI) 2021-22 को एनर्जी-एफिशिएंट इकोनॉमी (AEEE) के लिए एलायंस के सहयोग से एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो (BEE) द्वारा विकसित किया गया है। • इसमें 7 क्षेत्रों (भवन, उद्योग, नगरपालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, डिस्कॉम और क्रॉस-सेक्टर) में फैले 50 संकेतक (सामान्य और कार्यक्रम-विशिष्ट) शामिल हैं। • यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता पहलों को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उपकरण है। • यह विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। • इंडेक्स में चार श्रेणियां हैं यानी फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेडर और एस्पिरेंट। • फ्रंट रनर श्रेणी (>60 अंक) - इसमें 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना हैं। • अचीवर श्रेणी (50-60 अंक): इसमें असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब हैं। <p>ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था के लिए गठबंधन (AEEE):-</p> <ul style="list-style-type: none"> • इसका गठन 2008 में एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में किया गया था। • यह भारत में अग्रणी संगठनों में से एक है जो एक संसाधन के रूप में ऊर्जा दक्षता के बारे में जागरूकता पैदा करने

	<p>का काम करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● USAID/ECO-III प्रोजेक्ट पार्टनर्स, इंटरनेशनल रिसोर्सेज ग्रुप, एलायंस टू सेव एनर्जी के समर्थन से AEEE के विजन और मिशन को विकसित करने और लागू करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया। ● यह नीति कार्यान्वयन का समर्थन करता है और गैर-लाभ उद्देश्य के साथ एक ऊर्जा दक्षता बाजार प्रवर्तक है। ● यह डेटा-संचालित और साक्ष्य-आधारित ऊर्जा दक्षता नीतियों और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। ● रिपोर्ट: स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020, कोल्ड चैन एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडिया, और इनेबलिंग कोल्ड चैन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। <p>अवश्य पढ़ें: अक्षय ऊर्जा संक्रमण</p>
<p>मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 5(4)</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 5 (4) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है।</p> <p>मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 5(4) के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1961 के मूल कानून में गोद लेने वाली माताओं के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं थे, और इन्हें मातृत्व लाभ अधिनियम में 2017 के संशोधन के साथ जोड़ा गया था। ● ये प्रावधान उन महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ के लिए हैं जो गोद लेती हैं या कमीशनिंग मदर के रूप में काम करती हैं। ● तीन महीने से कम उम्र के बच्चों की गोद लेने वाली माताएं 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। ● तीन महीने से बड़े बच्चे को गोद लेने वाली महिला मातृत्व लाभ की पात्र नहीं है। <p>मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मातृत्व लाभ अधिनियम मूल रूप से 12 दिसंबर, 1961 को संसद द्वारा पारित किया गया था। उन्हें प्रसव से पहले और बाद की अवधि के लिए "कुछ प्रतिष्ठानों" में महिलाओं के रोजगार को विनियमित करने और मातृत्व लाभ और कुछ अन्य लाभ प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। ● यह मूल रूप से कारखानों, खानों, वृक्षारोपण पर लागू होता था और बाद में 1973 में सरकार के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों और प्रदर्शनियों के प्रतिष्ठानों के लिए लागू हुआ। ● अधिनियम की धारा 4 ने प्रसव या गर्भपात के तुरंत बाद छह सप्ताह के दौरान महिलाओं के रोजगार या काम पर रोक लगा दी। ● यदि महिला ने पिछले 12 महीनों में कम से कम 160 दिन काम किया हो तो धारा 5 के तहत 12 सप्ताह तक का मैटर्निटी लीव (maternity leave) दिया जाता है। ● उल्लंघन के परिणामस्वरूप जुर्माने के साथ या बिना तीन महीने की सजा हो सकती है। <p>2017 के संशोधन में मुख्य परिवर्तन:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जैविक माताओं के लिए बच्चे के जन्म के बाद 26 सप्ताह के सवैतनिक अवकाश की अनुमति देने के लिए इसने धारा 5 में संशोधन किया। ● इसने दत्तक या सरोगेट माताओं को बच्चे को सौंपे जाने की तारीख से 12 सप्ताह के मातृत्व लाभ की अवधि की अनुमति देने के लिए धारा 5(4) को शामिल किया। ● इसने मातृत्व लाभ प्राप्त करने के बाद पारस्परिक रूप से सहमत होने पर घर से काम करने की अनुमति देने के लिए धारा 5(5) को शामिल किया। ● इसने 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए एक क्रेच सुविधा की उपलब्धता को अनिवार्य करने के लिए धारा 11 को शामिल किया, जिसमें माताओं के लिए एक दिन में चार बार आने और आराम के अंतराल प्रदान किए गए। ● यह असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, जो संशोधन का एक आलोचनात्मक पहलू रहा है। <p>अवश्य पढ़ें: केंद्रीय बजट: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अंब्रेला योजनाएं</p>
<p>अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली (Inter-Operable)</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, गृह मंत्रालय ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) नामक आपराधिक मामलों के समय पर निपटान के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया।</p> <p>इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) आपराधिक न्याय प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने

Criminal Justice System)

वाली मुख्य आईटी प्रणाली के एकीकरण को सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है।

- यह देश में पाँच स्तंभों द्वारा संचालित होता है:-
 - पुलिस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग एवं नेटवर्क प्रणाली)
 - फॉरेंसिक लैब के लिये ई-फॉरेंसिक
 - न्यायालयों के लिये ई-कोर्ट
 - लोक अभियोजकों के लिये ई-अभियोजन
 - जेलों के लिये ई-जेल
- गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) की सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) परियोजना के तहत निवेश किया गया है।
 - ICJS देश भर में सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस, जेलों और अदालतों के डेटाबेस पर राष्ट्रव्यापी खोज को सक्षम बनाता है।
 - यह भविष्य में अपराधों के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण के लिए क्षेत्र-वार, श्रेणी-वार रिपोर्ट किए गए अपराधों में पूर्वानुमान/भविष्यवाणी प्रवृत्तियों के लिए डेटा विश्लेषण और अन्य मापदंडों के आधार पर भी प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
- परियोजना को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
- ICJS परियोजना के चरण-I (2018-2022) में, अलग-अलग आईटी प्रणालियों को लागू और स्थिर किया गया है; इन प्रणालियों पर अभिलेखों की खोज भी सक्षम की गई है।
- चरण- II (2022-26) के तहत, प्रणाली को 'एक डेटा एक प्रविष्टि' के सिद्धांत पर बनाया जा रहा है, जिसके तहत एक स्तंभ में केवल एक बार डेटा दर्ज किया जाता है और फिर प्रत्येक स्तंभ में डेटा को फिर से दर्ज करने की आवश्यकता के बिना अन्य सभी स्तंभों में उपलब्ध होता है।
- मंत्रालय देश भर में यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच को हर दो महीने में अपने एनालिटिक्स टूल, यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से भी ट्रैक करता है।
- यह प्रणाली फरवरी 2018 में लॉन्च की गई थी।
- वर्ष 2018 में अनुपालन दर (compliance rate) 43% से बढ़कर 2023 में 60% हो गई।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने दो महीने के भीतर बलात्कार के मामलों में जांच पूरी करने का प्रावधान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में संशोधन किया।

अवश्य पढ़ें: फॉरेंसिक लैब्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम

फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स 2022

संदर्भ: हाल ही में, फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स 2022 ने देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि संकट की जानकारी दी।

इसके बारे में:-

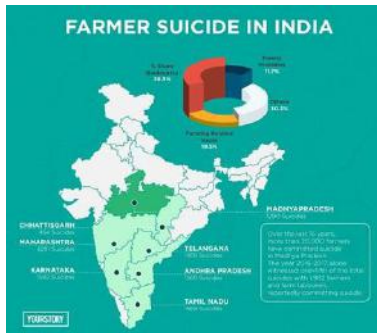


IMAGE SOURCE: farmer-suicide-info.jpg (800×729) (yourstory.com)

- फार्म डिस्ट्रेस इंडेक्स सेंटरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर (CRIDA) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है जो 21-प्रश्नों के सर्वेक्षण पर आधारित है जो कमजोर क्षेत्रों में किसानों की वित्तीय, आर्थिक और भावनात्मक स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाता है।
- यह सूचकांक अपनी वास्तविक घटना से कम से कम 3-4 महीने पहले आने वाले संकट को महसूस कर सकता है।

- **महत्व:** इस सूचकांक का उपयोग नीति निर्माताओं और सरकार द्वारा संकटग्रस्त किसानों की सहायता के लिए समयबद्ध और लक्षित पद्धति की योजना बनाने और डिजाइन करने के लिए किया जा सकता है।
- देश के विभिन्न हिस्सों से कृषि संकट की खबरें आ रही हैं।
- अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह संकट किसानों द्वारा आत्महत्या का कारण बन सकता है।

CRIDA:-

- यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन एक संस्थान है।
- इसकी स्थापना 1985 में हुई थी।
- मुख्यालय: हैदराबाद
- यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का एक घटक संगठन है, जो कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है।
- यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वित्तपोषित 'किसान संकट और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)' पर आधारित परियोजना का हिस्सा है।

अवश्य पढ़ें: कृषि सुधार

परमाणु दायित्व कानून

संदर्भ: भारत के परमाणु दायित्व कानून से संबंधित मुद्दे महाराष्ट्र के जैतापुर में छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने की योजना में बाधा बने हुए हैं।

परमाणु दायित्व कानून के बारे में:-

असैन्य परमाणु दायित्व पर कानून यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु घटना या आपदा के कारण पीड़ितों को हुई क्षति के लिये मुआवजा उपलब्ध कराया जाए और यह भी निर्धारित करता है कि उस क्षति के लिये कौन उत्तरदायी होगा।

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु दायित्व व्यवस्था में कई संधियाँ शामिल हैं और 1986 के चर्नोबिल परमाणु दुर्घटना के बाद इसे मजबूत किया गया था।
- **पूरक मुआवजे पर सम्मेलन (सीएससी):** यह 1997 में अपनाया गया एक व्यापक सम्मेलन है।
 - **उद्देश्य:** न्यूनतम राष्ट्रीय मुआवजा राशि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में पूरक मुआवजा पर व्यापक अभिसमय (CSC) को अपनाया गया था।
 - भारत ने वर्ष 2016 में CSC की पुष्टि की है।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरूप रखने के लिए, भारत ने 2010 में परमाणु क्षति अधिनियम (CLNDA) के लिए नागरिक दायित्व अधिनियमित किया, ताकि परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों के लिए एक त्वरित मुआवजा तंत्र स्थापित किया जा सके। (UPSC CSE: अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन)।
 - CLNDA परमाणु संयंत्र के संचालक पर सख्त और बिना किसी गलती के दायित्व का प्रावधान करता है, जहां उसे अपनी ओर से किसी भी गलती के बावजूद क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
 - यह परमाणु नुकसान के साथ-साथ परमाणु आपदाओं के पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजे के लिए कानूनी दायित्व स्थापित करता है।
 - यह उन विशेषज्ञों को निर्दिष्ट करता है जो परमाणु चोट के दावों का आकलन करेंगे, मुआवजे की मंजूरी देंगे और वित्तीय आश्वासन प्रदान करेंगे।
 - यह उस राशि को भी निर्दिष्ट करता है जो ऑपरेटर को किसी दुर्घटना के कारण हुई क्षति के मामले में चुकानी पड़ी हो और ऑपरेटर को बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से देयता को कवर करने की आवश्यकता होती है।
 - अधिनियम की धारा 6(2) के तहत ऑपरेटर की अधिकतम देनदारी 1500 करोड़ रुपये है।
 - क्षति के दावों के 1,500 करोड़ रुपये से अधिक होने की स्थिति में, CLNDA उम्मीद करता है कि सरकार CLND अधिनियम की धारा 7(1)(a) के अनुसार कदम उठाएगी।
 - हालाँकि, इसने सरकारी देयता राशि को 300 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) के बराबर रुपये या लगभग 2,100 रुपये से 2,300 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया है।
 - यह राशि और समय की सीमाओं को निर्दिष्ट करता है जब ऑपरेटर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई की जाती है।

- सीएलएनडी अधिनियम की धारा 7 (2) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार ऑपरेटर्स से लेवी की ऐसी राशि वसूल कर "परमाणु देयता निधि" स्थापित करती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- अधिनियम की शर्तों के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया जा सकता है।
- वर्तमान में भारत में 22 परमाणु रिएक्टर हैं (UPSC CSE: भारत की परमाणु ऊर्जा को समझना)।
- सभी मौजूदा रिएक्टर सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा संचालित किए जाते हैं।
 - न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
 - यह परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।
 - कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
 - उद्देश्य: परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत भारत सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुसरण में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन और बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करना।
 - NPCIL परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग और संचालन के लिए जिम्मेदार है।

जरूर पढ़ें: ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र

CGTMSE (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट)

संदर्भ: हाल ही में, MSME के केंद्रीय मंत्री ने संशोधित CGTMSE योजना शुरू की।

संशोधित सीजीटीएमएसई योजना के बारे में:-

- CGTMSE की स्थापना 2000 में हुई थी।
- यह संयुक्त रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा स्थापित किया गया है।
- उद्देश्य: सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को उत्प्रेरित करना। (UPSC CSE: एमएसएमई क्षेत्र की वित्त संबंधी समस्याओं को समझना)
- CGTMSE व्यवहार्य सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित करने के लिए अग्रणी क्रेडिट एक्सेस को सक्षम करने की गारंटी प्रदान करके मदद का हाथ बढ़ाता है।
- यह उन्हें नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वालों में बदलने में मदद करता है और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देता है। (UPSC CSE: एमएसएमई को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना)
- CGTMSE प्रदान करने में सहायक रहा है:
 - संपार्श्विक और/या तृतीय-पक्ष गारंटी मुक्त ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी कवर।
- ऋणदाता को स्वीकृत होते ही पात्र ऋण सुविधाओं को कवर कर देना चाहिए। गारंटी शुल्क के भुगतान की तारीख से शुरू होगी और सावधि ऋण/समग्र ऋण के मामले में और 5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि ऋण की सहमत अवधि तक चलेगी।
 - केवल कार्यशील पूंजी की सुविधा उधारकर्ताओं को दी जाती है, या ऐसी अवधि के लिए जो इस ओर से गारंटी ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।
- CGTMSE ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एक लाख करोड़ रुपये की गारंटी को मंजूरी देने के मील के पत्थर के आंकड़े को छूकर एक नया मील का पत्थर बनाया है।

योजना के लिए प्रस्तुत किया गया एक नया उपाय: -

- CGTMSE को वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कॉर्पस समर्थन प्रदान किया गया है ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान करने के लिए अपनी योजना में सुधार किया जा सके।
- अन्य संशोधनों में न्यूनतम गारंटी शुल्क को केवल 0.37% प्रति वर्ष के स्तर पर लाते हुए 1 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए गारंटी शुल्क में 50% की कमी शामिल है।
- एक और बड़े बदलाव की घोषणा गारंटी के लिए सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करना और कानूनी कार्रवाई शुरू किए बिना दावा निपटान की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना था।

अवश्य पढ़ें: MSME सस्टेनेबल (ZED) सर्टिफिकेशन स्कीम



अर्थव्यवस्था



CPTPP - ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता

संदर्भ: हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (UK) ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी समझौते (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership- CPTPP) पर हस्ताक्षर किये। इसके बारे में:-



IMAGE SOURCE: The Trade File – Cosmetics Alliance Canada

- CPTPP एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है जिस पर 2018 में 11 देशों के बीच सहमति बनी थी।
 - इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं।
- इसमें यूरोपीय संघ की तरह वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक ही बाजार नहीं है।
- मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा और निवेशक-राज्य विवाद निपटान से संबंधित कई प्रावधानों के अपवाद के साथ, CPTPP ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) समझौते के प्रावधानों को शामिल करता है, जिसका आवेदन CPTPP के लागू होने के बाद निलंबित कर दिया जाएगा।
- ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) समझौता:
 - यह मूल रूप से 12 देशों द्वारा संपन्न किया गया था। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं।
 - इस पर 2016 में सभी 12 पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
 - जनवरी 2017 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने TPP के हस्ताक्षरकर्ताओं को TPP की पुष्टि नहीं करने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया, प्रभावी रूप से TPP से हट गया।

अवश्य पढ़ें: क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी)

एसबीए (ASBA), ब्लॉकड राशि द्वारा समर्थित आवेदन

संदर्भ: हाल ही में सेबी ने द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए एसबीए (ASBA), ब्लॉकड राशि द्वारा समर्थित आवेदन के लिए एक रूपरेखा को मंजूरी दी।

इसके बारे में:-

- एसबीए (ASBA), ब्लॉकड राशि द्वारा समर्थित आवेदन, या एसबीए, सेबी द्वारा विकसित आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश) आवेदन प्रक्रिया है।
- इसका उद्देश्य बाजार में एक सुचारु परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना है, इस ढांचे को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
- यह आईपीओ इश्यू की सदस्यता लेने के लिए बैंक खाते में पैसे ब्लॉक करने के लिए प्राधिकरण प्रदान करने वाली प्रक्रिया है।
- एक निवेशक के रूप में एसबीए के माध्यम से आवेदन करने पर बैंक खाते से पैसा तभी काटा जा सकता है जब आपका आवेदन आवंटन के लिए चुना जाता है।
- यह अवरोधन स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी) द्वारा किया जाता है।
 - स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी): यह सेबी द्वारा अधिकृत बैंक हैं जो आवेदन स्वीकार करने के

लिए सेबी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप हैं, आवेदन की आवश्यकता के अनुसार राशि को सत्यापित और अवरुद्ध करते हैं, वेब पर विवरण अपलोड करते हैं और शेयर आवंटित होने तक प्रक्रिया के साथ अपडेट रहते हैं।

- **पात्रता:** ASBA का लाभ उठाने के लिए निवेशक का भारतीय निवासी होना आवश्यक है।
- यदि पैसा ब्याज वाले एएसबीए खाते में ब्लॉक कर दिया गया है तो शेयर का आवंटन प्राप्त करने में लगने वाले समय के दौरान राशि पर ब्याज अर्जित करना जारी रहेगा।
- यह सुविधा निवेशकों और स्टॉक ब्रोकरों के लिए वैकल्पिक होगी।

अवश्य पढ़ें: सेबी

किसान उत्पादक संगठन (FPO)

संदर्भ: हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि किसान उत्पादक कंपनियों पर अधिकार रखने वाले बड़े निगम अपने उद्देश्य को कमजोर कर रहे हैं।

किसान उत्पादक संगठनों के बारे में:-

- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एक सामान्य नाम है, जो कंपनी अधिनियम के भाग IXA के तहत या संबंधित राज्यों के सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत शामिल/पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन को संदर्भित करता है।
- किसान उत्पादक संगठनों के पीछे अवधारणा यह है कि किसान, जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं, समूह बना सकते हैं।
- इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) को किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन में राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए अधिकृत किया गया था।

एफपीओ से मिलने वाले लाभ:-

- एफपीओ सामूहिक खेती में किसानों को शामिल कर सकते हैं और छोटे आकार के खेतों से पैदा होने वाली उत्पादकता की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
- खेती की सघनता में वृद्धि के कारण अतिरिक्त रोजगार सृजन प्रदान करना।
- कॉर्पोरेट्स के साथ चर्चा: एफपीओ किसानों को सौदेबाजी में बड़े कॉर्पोरेट उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह सदस्यों को एक समूह के रूप में बातचीत करने की अनुमति देता है और इनपुट और आउटपुट दोनों बाजारों में छोटे किसानों की मदद कर सकता है।
- **एकत्रीकरण का अर्थशास्त्र:** एफपीओ सदस्य किसानों को कम लागत और गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्रदान कर सकता है।
- **सामाजिक प्रभाव:** सामाजिक पूंजी एफपीओ के रूप में विकसित होगी, क्योंकि इससे एफपीओ में महिला किसानों के लिंग संबंधों और निर्णय लेने में सुधार हो सकता है।

10,000 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन :-

- इसे 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- **उद्देश्य:** एफपीसी को हैंड-होल्डिंग सहायता प्रदान करना और 2024 तक 10,000 एफपीओ बनाने के लक्ष्य को पूरा करना। 2020-21 में एफपीओ के गठन के लिए 2200 से अधिक एफपीओ उत्पादन क्लस्टर आवंटित किए गए हैं।
- कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) ने क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) को 5 साल की अवधि के लिए प्रत्येक एफपीओ को एकत्र करने, पंजीकृत करने और पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया है।
 - **CBBOs:** सीबीबीओ एफपीओ प्रचार से संबंधित सभी मुद्दों के लिए संपूर्ण ज्ञान का मंच होगा।
- **योजना के तहत वित्तीय सहायता:**
 - 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18.00 लाख रुपये तक।
 - प्रति एफपीओ 15.00 लाख रुपये की सीमा के साथ एफपीओ के प्रति किसान सदस्य 2,000 रुपये तक के इक्विटी अनुदान के मिलान का भी प्रावधान किया गया था।
 - एफपीओ के लिए संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋणदाता संस्था से प्रति एफपीओ परियोजना ऋण के लिए 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी सुविधा का प्रावधान।

अवश्य पढ़ें: किसानों की आय दोगुनी करना- एक मिथक या रियलिटी

**REITs और
InvITs इंडेक्स**

संदर्भ: हाल ही में, NSE ने भारत का पहला REITs और InvITs इंडेक्स लॉन्च किया।

REITs और InvITs इंडेक्स के बारे में:-

- REITs और InvITs सूचकांक NSE पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और कारोबार किए गए REITs और InvITs के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं।
- इन सूचकांकों के लिए आधार वर्ष '1 जुलाई 2019' रखा गया है।
 - इसकी समीक्षा की जानी है और प्रत्येक तिमाही में इसे फिर से संतुलित किया जाना चाहिए है।

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी):-

- REIT मोटे तौर पर म्यूचुअल फंड की तरह है जो रियल एस्टेट में निवेश करता है।
- आरईआईटी पर मूल सौदा यह है कि जब कोई संपत्ति का एक हिस्सा रखता है, और व्यय का उचित हिस्सा घटाकर आय का एक उचित हिस्सा उनके पास आ जाता है।
- मुख्य रूप से, यह लोगों के एक समूह की तरह है जो अपने धन को एक साथ जमा करते हैं और अचल संपत्ति खरीदते हैं, सिवाय इसके कि यह बड़े पैमाने पर है और विनियमित है।
- आरईआईटी कंपनियाँ आय पैदा करने वाली अचल संपत्ति का स्वामित्व, संचालन या वित्तपोषण करती हैं।
- इसमें शेयरों की तरह सार्वजनिक रूप से कारोबार किया जाता है, उन्हें अत्यधिक तरल बनाता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvIT):-

- InvITs को REITs के संशोधित संस्करण के रूप में माना जा सकता है जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है।
- ये आरईआईटी के समान होते हैं लेकिन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सड़कों या राजमार्गों में निवेश करते हैं जो स्थिर नकदी प्रवाह उत्पन्न करने में कुछ समय लेते हैं।
- ये एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित हैं और सेबी के साथ पंजीकृत हैं।

अवश्य पढ़ें: FPI और InvITs

**डब्बा ट्रेडिंग
(Dabba
Trading)**

संदर्भ: हाल ही में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 'डब्बा ट्रेडिंग' में शामिल संस्थाओं के नाम पर कई नोटिस जारी किए।

डब्बा ट्रेडिंग के बारे में:-

- डब्बा (बॉक्स) ट्रेडिंग एक प्रकार की अनौपचारिक ट्रेडिंग है, जो स्टॉक एक्सचेंजों के दायरे से बाहर होती है।
- व्यापारी किसी विशेष स्टॉक का भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेन-देन किए बिना स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर दांव लगाते हैं, जैसा कि एक्सचेंज में किया जाता है।
- सरल शब्दों में, यह स्टॉक की कीमतों के उतार-चढ़ाव पर केंद्रित जुआ है।
 - उदाहरण के लिए, एक निवेशक किसी स्टॉक पर मूल्य बिंदु पर दांव लगाता है, मान लीजिए 1,000 रुपया है।
 - यदि मूल्य बिंदु बढ़कर ₹1,500 हो जाता है, तो उसे ₹500 का लाभ होगा।
 - हालांकि, यदि मूल्य बिंदु 900 रुपए तक गिर जाता है, तो निवेशक को डब्बा ब्रोकर को अंतर का भुगतान करना होगा।
 - इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ब्रोकर का लाभ निवेशक के नुकसान के बराबर है और इसके विपरीत।
- ऐसे व्यापारों का प्राथमिक उद्देश्य नियामक तंत्र के दायरे से बाहर रहना है।
- इसलिए लेन-देन को नकद का उपयोग करके सुगम बनाया जाता है और तंत्र को गैर-मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर टर्मिनलों का उपयोग करके संचालित किया जाता है।
 - व्यापार के प्रमाण के रूप में अनौपचारिक या कच्चा (रफ) रिकॉर्ड, सौदा (लेन-देन) बही, चालान, डीडी रसीदें, बिलों/अनुबंध नोटों के साथ नकद रसीदों का उपयोग करके भी इसे सुगम बनाया जा सकता है।

समस्याएँ:-

- चूंकि आय या लाभ का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है, यह डब्बा व्यापारियों को कराधान से बचने में मदद करता है।
- इन्हें अपने लेनदेन पर कमोडिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स (सीटीटी) या सिक्योरिटीज ट्रांज़ैक्शन टैक्स (एसटीटी) का भुगतान नहीं करना होगा।
- नकदी के उपयोग का अर्थ यह भी है कि वे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे से बाहर हैं।

	<ul style="list-style-type: none"> • इससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है। • 'डब्ला ट्रेडिंग' में, प्राथमिक जोखिम में यह संभावना होती है कि ब्रोकर निवेशक को भुगतान करने में डिफॉल्ट करता है या राशि दिवालिया हो जाती है। • विनियामक दायरे से बाहर होने का अर्थ है कि निवेशकों के पास निवेशक संरक्षण, विवाद समाधान तंत्र और शिकायत निवारण तंत्र के औपचारिक प्रावधान नहीं हैं जो एक्सचेंज के भीतर उपलब्ध हैं। • चूंकि सभी गतिविधियों को नकदी का उपयोग करके और बिना किसी ऑडिट योग्य रिकॉर्ड के सुविधा प्रदान की जाती है, यह एक समानांतर अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के साथ-साथ 'काले धन' के विकास को संभावित रूप से प्रोत्साहित कर सकता है। • यह संभावित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक गतिविधियों के जोखिमों में परिवर्तित हो सकता है। <p>अवश्य पढ़ें: सोशल स्टॉक एक्सचेंज</p>
मिशन50K-EV4ECO	<p>संदर्भ: हाल ही में, SIDBI ने 'मिशन 50K-EV4ECO' योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन स्थान के लिए एक नया वित्तपोषण समाधान लॉन्च किया।</p> <p>इसके बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • उद्देश्य: भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की मूल्य श्रृंखला की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। • इससे ईवी अपनाने को बढ़ावा मिलने और देश में संबद्ध बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की उम्मीद है। • परियोजना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से 2-पहिया, 3-पहिया और 4-पहिया ईवी के उत्थान को प्राथमिकता देती है। • इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किफायती वित्तपोषण तक पहुंच प्रदान करना और बैटरी स्वैपिंग सहित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। • यह योजना सिडबी-विश्व बैंक द्वारा EVOLVE योजना की पूर्वगामी है। • यह भारत में ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए बेहतर वित्तपोषण शर्तें और अन्य समाधान प्रदान करता है। <p>भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी):-</p> <ul style="list-style-type: none"> • सिडबी की स्थापना 1990 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। • मुख्यालय: लखनऊ (उत्तर प्रदेश) भारत • अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: श्री शिवसुब्रमण्यम रमन • यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के साथ-साथ समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। • सिडबी के शेयर भारत सरकार और 22 अन्य संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों के पास हैं जिनका स्वामित्व या नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। • मिशन: MSME के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना और मजबूत करना और एमएसएमई ईको-सिस्टम में वित्तीय और विकासात्मक दोनों अंतरालों को चिन्हित करना। • सिडबी अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यूके के माध्यम से यूके एड द्वारा वित्तपोषित पीएसआईजी कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। • सिडबी "सबसे गरीब राज्यों का समावेशी विकास (PSIG) कार्यक्रम" लागू कर रहा है। • यह अप्रैल 2012 से यूके सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (DFID), यूके के माध्यम से वित्त पोषित है। • इस कार्यक्रम का उद्देश्य चार सबसे गरीब राज्य बिहार, एमपी, ओडिशा और यूपी में गरीबों, विशेषकर महिलाओं की आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है, ताकि लक्ष्य समूह को व्यापक आर्थिक अवसरों और विकास में भाग लेने और लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके। <p>अवश्य पढ़ें: ईवी बैटरियों के निर्माण के लिए गहरे समुद्र में खनन</p>
क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) कानून में बाजार	<p>संदर्भ: हाल ही में, यूरोपीय संघ ने क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों के लिए दुनिया के व्यापक नियमों 'द मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) कानून' के पहले सेट को मंजूरी दी।</p> <p>क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) कानून में बाजारों के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) कानून में बाजार, पहली बार पूरी तरह से क्रिप्टोक्यूरेंसी को विनियमित करेगा। • वैश्विक स्तर पर क्रिप्टोक्यूरेंसी के नियमन के लिए नए मानक स्थापित करने की उम्मीद है।

- MiCA क्रिप्टो संपत्तियों के जारीकर्ताओं पर अनुपालन लागू करेगा, जिन्हें "कानूनी व्यक्ति जो जनता को किसी भी प्रकार की क्रिप्टो-संपत्ति प्रदान करता है" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह क्रिप्टो-एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (CASPs) पर लागू होगा, जो इनमें से एक या अधिक सेवाएं प्रदान करता है, कॉइनबेस जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का संचालन, तीसरे पक्ष (ग्राहकों) की ओर से क्रिप्टो एसेट्स का प्रबंधन, क्रिप्टो एसेट्स का आदान-प्रदान धन/अन्य क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लिए, क्रिप्टो संपत्तियों के लिए ऑर्डर का निष्पादन, क्रिप्टो संपत्तियों को रखना, क्रिप्टो संपत्तियों के लिए तृतीय पक्षों को स्थानांतरण सेवाएं प्रदान करना, क्रिप्टो संपत्तियों और क्रिप्टो-पोर्टफोलियो प्रबंधन पर सलाह प्रदान करना।

अवश्य पढ़ें : क्रिप्टोकुरेंसी विनियमन

सीमित प्रयोजन समाशोधन निगम (LPCC)

संदर्भ: हाल ही में, सेबी ने एलपीसीसी के सेटलमेंट गारंटी फंड के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

सीमित प्रयोजन समाशोधन निगम (एलपीसीसी) के बारे में:-

- एलपीसीसी सेबी द्वारा स्थापित एक इकाई है।
- यह रेपो दर लेनदेन के समाशोधन और निपटान की गतिविधि करेगा।
- नया ढांचा 1 मई से लागू होगा।
- ढांचे के तहत, ऋण प्रतिभूतियों की परिपक्वता के आधार पर प्रति वर्ष ऋण प्रतिभूतियों के जारी मूल्य के 0.5 आधार अंक की राशि स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा एकत्र की जाएगी और ऋण प्रतिभूतियों के आवंटन से पहले एस्क्रो खाते में रखी जाएगी।
 - यह राशि सार्वजनिक निर्गम या ऋण प्रतिभूतियों के निजी नियोजन पर लागू होती है।
- स्टॉक एक्सचेंज राशि प्राप्त होने के एक कार्य दिवस के भीतर इस प्रकार एकत्रित राशि को एलपीसीसी के बैंक खाते में स्थानांतरित करेंगे और इसका विवरण एलपीसीसी को सूचित करेंगे।
- इस प्रकार एकत्र की गई राशि का विवरण स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अपनी वेबसाइट पर भी दर्शाया जाएगा।
- एलपीसीसी पात्र जारीकर्ताओं द्वारा योगदान की जाने वाली राशियों की गणना का एक उदाहरण प्रदान करेगा।
- एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (एआरसीएल) को सेबी द्वारा एलपीसीसी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

ARCL:-

- इसे अप्रैल 2021 में शामिल किया गया था।
- इसे स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम (SECC) विनियम, 2018 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा सैद्धांतिक रूप से मान्यता प्राप्त है।
- एआरसीएल एक सेंट्रल काउंटर पार्टी (सीसीपी) है जो गारंटी तंत्र के साथ मजबूत जोखिम प्रबंधन के साथ कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में त्रिपक्षीय रेपो के तहत एनएसई और बीएसई पर निष्पादित सभी ट्रेडों को समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करती है।
- **निपटाने के लिए तंत्र का उपयोग किया जाएगा:-**
 - समाशोधन सदस्यों के बीच विवाद
 - समाशोधन सदस्यों और उनके ग्राहकों के बीच विवाद
 - एलपीसीसी और इसके वेंडरों के बीच अंतर
 - समाशोधन सदस्यों या इसके ग्राहकों और एलपीसीसी के बीच विवाद
 - एलपीसीसी के समाशोधन सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा सुलह और/या एक मध्यस्थता पैनल द्वारा किया जाएगा जिसमें तीन समाशोधन सदस्य शामिल होंगे, समाशोधन सदस्यों के अलावा जो विवाद के पक्षकार हैं।
- मध्यस्थता पैनल का निर्णय अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा।
- यदि कोई समाशोधन सदस्य या एलपीसीसी संतुष्ट नहीं है तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत विवादों का समाधान किया जाएगा।

महत्व:

- अच्छी तरह से काम कर रहा रेपो बाजार अंतर्निहित ऋण प्रतिभूतियों की तरलता को बढ़ाकर ऋण प्रतिभूति बाजार के विकास में योगदान देता है और बाजार सहभागियों को अंतर्निहित को बेचे बिना अपनी ऋण धारिता का मुद्रीकरण करने की अनुमति देता है, इस प्रकार धन की उनकी अस्थायी आवश्यकता को पूरा करता है।

<p>सूचनाओं का स्वचालित आदान-प्रदान (AEOI) फ्रेमवर्क</p>	<p>अवश्य पढ़ें: लॉन्ग-टर्म</p> <p>संदर्भ: हाल ही में, भारत ने मौजूदा OECD के सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (AEOI) ढांचे में सामान्य रिपोर्टिंग मानक (CRS) के दायरे को व्यापक बनाने पर जोर दिया।</p> <p>सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (ईओआई) ढांचे के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह कर अधिकारियों के बीच सूचनाओं के पूर्वनिर्धारित सेट के स्वतः आदान-प्रदान का प्रावधान करता है। • AEOI मानक को पूर्व-निर्धारित प्रारूप में अनिवासी व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा आयोजित वित्तीय खातों पर जानकारी के वार्षिक आदान-प्रदान की आवश्यकता होती है। • आदान-प्रदान की गई जानकारी में वित्तीय खाते के बारे में विवरण और खाता धारक के बारे में विवरण शामिल हैं। • ईओआई ढांचे के तहत, हस्ताक्षरकर्ता देश एक सीआरएस का पालन करते हैं और अपने वित्तीय संस्थानों से जानकारी प्राप्त करते हैं और स्वचालित रूप से वार्षिक आधार पर अन्य न्यायालयों के साथ उस जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं। • ईओआई मानक विदेशों में वित्तीय संपत्तियां रखने के माध्यम से ऑफशोर • टैक्स चोरी को रोकने और पहचानने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। • भारतीय परिदृश्य: भारत में वर्तमान में वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के लिए 108 अधिकार क्षेत्रों के साथ ईओआई है और स्वचालित रूप से सूचना भेजने के लिए 79 अधिकार क्षेत्र हैं। • अगस्त 2022 में, OECD ने क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF) को भी मंजूरी दी। <p>क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF) के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह स्वचालित रूप से इस तरह की जानकारी का आदान-प्रदान करने की दृष्टि से क्रिप्टो संपत्ति में लेनदेन पर कर जानकारी की रिपोर्टिंग के लिए प्रदान करता है। • CARF का उद्देश्य हर साल मानकीकृत तरीके से करदाताओं के आवासों के अधिकार क्षेत्र के साथ क्रिप्टो संपत्ति पर सूचना के संग्रह और स्वचालित आदान-प्रदान को सुनिश्चित करना है। • ढांचा क्रिप्टो संपत्ति को किसी भी संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है जो पारंपरिक वित्तीय मध्यस्थों की भागीदारी के बिना विकेंद्रीकृत तरीके से आयोजित और स्थानांतरित की जाती है। <ul style="list-style-type: none"> ○ ये परिसंपत्तियां क्रिप्टो डेरिवेटिव, स्थिर मुद्रा, या कुछ अपूरणीय टोकन के रूप में जारी की जाती हैं। ○ इस परिभाषा में ऐसी संस्थाएं शामिल नहीं हैं जो केवल रिकॉर्ड रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती हैं और उनके पास स्वामित्व अधिकार नहीं हैं। ○ इसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी शामिल नहीं है, जिसकी अलग-अलग रिपोर्टिंग आवश्यकताएं हैं। • दलालों और एटीएम ऑपरेटर्स जैसे क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के विनिमय और हस्तांतरण को सक्षम करने वाले मध्यस्थ और अन्य सेवा प्रदाता इस ढांचे के दायरे में शामिल हैं। • CARF उस डेटा को भी रेखांकित करता है जिसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। • ढांचा अनिवार्य करता है कि क्रिप्टो संपत्ति फर्मों को उस देश को रिपोर्ट करना चाहिए जिसमें वे काम करते हैं। • उन्हें प्रासंगिक क्रिप्टो संपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, और एक या अधिक प्रकार की क्रिप्टो संपत्तियों के साथ-साथ खुदरा भुगतान लेनदेन सहित क्रिप्टो के अन्य हस्तांतरणों के बीच एक्सचेंजों के बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। • ढांचे के लिए व्यक्तिगत और इकाई ग्राहकों और व्यक्तियों को खुद की पहचान करने की आवश्यकता होती है। <p>जरूर पढ़ें: क्रिप्टोजैकिंग</p>
--	--



अंतरराष्ट्रीय संबंध



संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष

संदर्भ: हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष ने जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों के लिए समर्थन बढ़ाया, जो भारत में निगरानी सूची में हैं।

संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के बारे में:-

- UNDEF की स्थापना 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत प्रत्येक के 10 मिलियन डॉलर के प्रारंभिक योगदान के साथ की गई थी।
- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 2005 में, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यूएस-इंडिया ग्लोबल डेमोक्रेसी इनिशिएटिव की घोषणा की, जिसमें यूएनडीईएफ के लिए समर्थन शामिल था।
- इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी ए. अन्नान द्वारा 2005 में दुनिया भर में लोकतंत्रीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनरल ट्रस्ट फंड के रूप में बनाया गया था।

उद्देश्य: नागरिक समाज की आवाज और भागीदारी को मजबूत करने वाली परियोजनाओं का समर्थन करना, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं के विकास को प्रोत्साहित करना।

फंडिंग: यह पूरी तरह से सदस्य राज्यों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित है और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 16 सदस्यों से बने एक सलाहकार बोर्ड द्वारा शासित है।

संघटन:-

- महासचिव द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड में विविध भौगोलिक प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए आठ सबसे बड़े सदस्य राज्य योगदानकर्ता और छह अन्य राज्य शामिल हैं।
- भारत शुरू से ही बोर्ड का सदस्य रहा है।

अवश्य पढ़ें: अफगानिस्तान में 'पीपुल्स इकोनॉमी' के लिए यूएन फंड

गुड फ्राइडे समझौता

संदर्भ: हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति, जो बिडेन ने गुड फ्राइडे समझौते के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बेलफास्ट का दौरा किया।

गुड फ्राइडे समझौते के बारे में:-

- गुड फ्राइडे समझौता, जिसे बेलफास्ट समझौते के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसने उत्तरी आयरलैंड में सांप्रदायिक हिंसा को समाप्त किया।
- इस पर 10 अप्रैल, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे।
- इस पर उत्तरी आयरलैंड के गुटों और ब्रिटेन तथा आयरलैंड की सरकारों के बीच हस्ताक्षर किए गए।
- **उद्देश्य:** उत्तरी आयरलैंड में उन लोगों के बीच दशकों से चली आ रही हिंसा को समाप्त करना जो यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ रहना चाहते थे और जो आयरलैंड में शामिल होना चाहते थे।
- वार्ताकारों में तत्कालीन-ब्रिटिश प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर, तत्कालीन-आयरिश प्रधान मंत्री बर्टी अहर्न, जॉर्ज मिशेल, एक पूर्व डेमोक्रेटिक सीनेटर, जिन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दूत के रूप में कार्य किया, और उत्तरी आयरलैंड के आठ दल शामिल थे।
- समझौते का उद्देश्य सत्ता साझा करने वाली सरकार की स्थापना करना था।
- **अनुमति:-**
 - गुड फ्राइडे समझौते पर 22 मई, 1998 को जनमत संग्रह कराया गया।
 - इसने आयरलैंड में 94% मतदाताओं और उत्तरी आयरलैंड में 71% का अनुमोदन प्राप्त किया।

समझौते की वर्तमान स्थिति :-

- गुड फ्राइडे समझौता अभी भी बना हुआ है, लेकिन ब्रेक्सिट और उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के कारण मुद्दे सामने आए हैं।
- **उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल:** बाकि यूके से उत्तरी आयरलैंड में आने वाले सामानों की जांच करने के लिए यूके और यूरोपीय संघ द्वारा सहमत एक योजना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करते हैं।

<p>शिकागो कन्वेंशन</p>	<p>अवश्य पढ़ें: भारत और ब्रिटेन - मुक्त व्यापार समझौता वार्ता</p> <p>संदर्भ: हाल ही में, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने DGCA को सूचित किया कि भारत शिकागो कन्वेंशन के विमानन सुरक्षा निरीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है और FAA अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन (IASA) श्रेणी-1 की स्थिति को बरकरार रखता है।</p> <p>शिकागो कन्वेंशन के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर 'शिकागो कन्वेंशन' के रूप में जाना जाता है, 1944 में तैयार किया गया था। • इस सम्मेलन ने हवाई मार्ग से अंतरराष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले मूल सिद्धांतों की स्थापना की। • इसने विशेष एजेंसी के निर्माण का भी नेतृत्व किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के बाद से सम्मेलन की देखरेख की है। • यह कन्वेंशन हवाई यात्रा के लिए 9 स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) द्वारा केवल पहले पांच स्वतंत्रताओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। <p>अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO):-</p> <ul style="list-style-type: none"> • आईसीएओ एक संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की विशेष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। • इसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिए मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी। • शिकागो में 7 दिसंबर 1944 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। • भारत इसके 193 सदस्यों में से है। • मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा • इसने हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले मूल सिद्धांतों की स्थापना की, और आईसीएओ के निर्माण का भी नेतृत्व किया। • इसका एक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सके। <p>अवश्य पढ़ें: संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि</p>
<p>वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट, 2023 प्रकाशित की, जिसमें कहा गया है कि जीवन, आजीविका और धन को बचाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में निवेश करना आवश्यक है।</p> <p>रिपोर्ट की मुख्य बातें:</p> <ul style="list-style-type: none"> • रिपोर्ट में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ खाद्य प्रणाली के झटकों के लिए अधिक सक्रिय प्रतिक्रिया का आह्वान किया गया है: <ul style="list-style-type: none"> ○ संकट की भविष्यवाणी और तैयारी ○ संकट से पहले और उसके दौरान लचीलापन बनाना ○ महिलाओं, मजबूर प्रवासियों और अन्य कमजोर समूहों के लिए संकट प्रतिक्रिया को सहायक और समावेशी बनाना। • इसने संकट के दौरान आजीविका और खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने की वकालत की। • इसने सरकारों को एक कारोबारी माहौल बनाए रखने की सलाह दी जो लचीलेपन और तकनीकी और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देता है। • खाद्य और कृषि संगठन की खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में, दुनिया भर में लगभग 768 मिलियन लोग कुपोषित थे। <ul style="list-style-type: none"> ○ यह 2014 में रिपोर्ट किए गए 572 मिलियन से काफी ऊपर था। • वर्ष 2022 में, रूस-यूक्रेन युद्ध और खाद्य और उर्वरक की कीमतों में संबंधित स्पाइक्स द्वारा खाद्य असुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। • वास्तव में, मई 2020 और 2022 के अंत के बीच उर्वरक की कीमतों में 199 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने कहा।

- इसके परिणामस्वरूप, खाद्य असुरक्षा, भूख और कुपोषण के कारण जोखिम में लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2022 में, 45 देशों में कम से कम 205 मिलियन लोगों ने संकट-स्तर की तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया या इससे भी बदतर, 2016 की संख्या से लगभग दोगुना, जैसा कि IFPRI की रिपोर्ट में बताया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI):

- यह 1975 में स्थापित किया गया था और विकासशील देशों में गरीबी को स्थायी रूप से कम करने और भूख तथा कुपोषण को समाप्त करने के लिए अनुसंधान-आधारित नीति समाधान प्रदान करता है।
- **मुख्यालय:** वाशिंगटन, डी.सी
- यह CGIAR का अनुसंधान केंद्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कृषि नवाचार नेटवर्क है।
- इसका अनुसंधान पांच सामरिक अनुसंधान क्षेत्रों पर केंद्रित है:
 - जलवायु-लचीले और सतत खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देना
 - AI के लिए स्वस्थ आहार और पोषण को बढ़ावा देना
 - समावेशी और कुशल बाजार, व्यापार प्रणाली और खाद्य उद्योग का निर्माण
 - कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बदलना
 - संस्थानों और शासन को मजबूत बनाना

कैरेबियन समुदाय और आम बाजार (CARICOM)

संदर्भ: हाल ही में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने जमैका समकक्ष के साथ चौथी भारत-कैरिबिआन मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की।

कैरिबिआन के बारे में:-

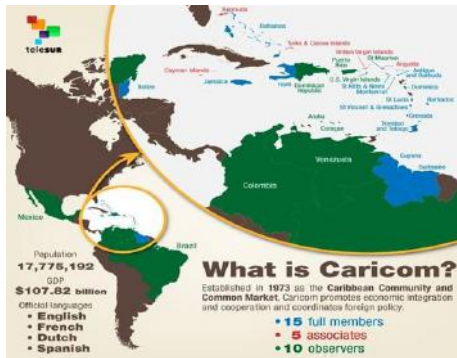


IMAGE SOURCE: [What is Caricom? | Multimedia | teleSUR English](#)

- कैरेबियन समुदाय और आम बाजार (CARICOM या CC) एक अंतर सरकारी संगठन है जो पूरे अमेरिका और अटलांटिक महासागर में 15 सदस्य राज्यों (14 राष्ट्र-राज्य और एक निर्भरता) का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है।
- इसकी स्थापना 1973 में हुई थी।
- कैरिबिआन विकासशील दुनिया में सबसे पुराना जीवित एकीकरण आंदोलन है।
- **उद्देश्य:** अपने सदस्यों के बीच आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि एकीकरण के लाभों को समान रूप से साझा किया जाता है, और विदेश नीति का समन्वय करना।
- CARICOM में एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गुयाना, हैती, जमैका, मोंटसेराट, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो सहित 15 सदस्य हैं।
- समुदाय की अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच हर छह महीने में बदली जाती है।
- CARICOM एकल बाजार और अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और बिक्री और निवेश को आकर्षित करने के अधिक और बेहतर अवसर प्रदान करके क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करना है।

भारत-कैरिबिआन :-

- भारत के प्रधान मंत्री ने 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर CARICOM देशों के समूह के 14 नेताओं के साथ बैठक की थी।
 - बैठक में लगातार मजबूत होते जा रहे संबंधों पर विचार-विमर्श किया गया।

- भारत ने इस क्षेत्र में तूफान डोरियन और बहामास के सबसे अधिक प्रभावित द्वीप में हुए विनाश से उबरने के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की।
- भारत ने CARICOM में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 14 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान और सौर, नवीकरणीय ऊर्जा जलवायु-परिवर्तन-संबंधी परियोजनाओं के लिए 150 मिलियन अन्य लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की।
- भारत सरकार ने 2005-2006 में CARICOM सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार अवसंरचना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सामुदायिक स्टूडियो में US \$ 1.166 मिलियन का वित्त पोषण किया।
- भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चौथी भारत-कैरिबियन मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की और व्यापार, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

अवश्य पढ़ें: क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)



इतिहास, कला और संस्कृति

बाबू जगजीवन राम

संदर्भ: हाल ही में बाबू जगजीवन राम की 116वीं जयंती मनाई गई।

बाबू जगजीवन राम के बारे में:-

- वे एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के योद्धा, दलित वर्गों के मसीहा और एक उत्कृष्ट सांसद थे।
- वर्ष 1925 में, जगजीवन राम विद्वान पंडित मदन मोहन मालवीय से मिले और उनसे बहुत प्रेरित हुए।
- मालवीय के निमंत्रण पर, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया।
- उन्होंने कलकत्ता (कोलकाता) के विभिन्न क्षेत्रों में कई रविदास सम्मेलनों का आयोजन किया और गुरु रविदास जयंती मनाई।
- 1931 में, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस पार्टी) के सदस्य बने।
- अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था।
 - अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग: 1934-35 में अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित एक संगठन है।
- वे सामाजिक समानता और दलित वर्गों के लिए समान अधिकारों के हिमायती थे।
- 1935 में, उन्होंने हिंदू महासभा के एक सत्र में प्रस्ताव रखा कि पीने के पानी के कुएं और मंदिर अछूतों के लिए खुले रहें।
- 1935 में, बाबूजी रांची में हैमोड आयोग (Hammond Commission) के सामने भी उपस्थित हुए और पहली बार दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की।
- ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें 1940 के दशक की शुरुआत में दो बार जेल भेजा गया था।
- जब जवाहरलाल नेहरू ने अस्थायी सरकार बनाई, तो जगजीवन राम इसके सबसे कम उम्र के मंत्री बने।
- आजादी के बाद उन्होंने 1952 तक श्रम विभाग संभाला।
- उन्होंने संचार मंत्री (1952-56), परिवहन और रेलवे (1956-62), और परिवहन और संचार (1962-63) के पदों पर नेहरू के मंत्रिमंडल में कार्य किया।
- उन्होंने खाद्य और कृषि मंत्री (1967-70) के रूप में कार्य किया।
- 1970 में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया।
- उन्होंने बाद में भारत के उप प्रधान मंत्री (1977-79) के रूप में कार्य किया।
- जगजीवन राम 1936 से 1986 (40 वर्ष) तक लगातार संसद सदस्य रहे और यह एक विश्व रिकॉर्ड है।
- उनके पास भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कैबिनेट मंत्री (30 वर्ष) होने का एक और रिकॉर्ड भी है।
- उनके श्मशान स्थल पर उनके स्मारक का नाम समता स्थल (समानता का स्थान) है।

अवश्य पढ़ें: महात्मा गांधी

कौशांबी महोत्सव-2023

संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने कौशांबी महोत्सव-2023 का उद्घाटन किया और दुर्गा भाभी को श्रद्धांजलि दी।

कौशांबी महोत्सव-2023 के बारे में:-

- कौशांबी महोत्सव-2023 एक खेल उत्सव है।
- इसका आयोजन सांसद द्वारा किया जाता है।
- ये खेल महोत्सव युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करते हैं।
- 'सांसद खेलकूद स्पर्धा' में भाग लेने के लिए लगभग 16000 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया।
 - सांसद खेलकूद स्पर्धा: संसद सदस्यों द्वारा शुरू किया गया।

दुर्गा भाभी के बारे में:-

- दुर्गा देवी कौशांबी की एक स्वतंत्रता सेनानी थीं।
- उन्हें प्यार से 'दुर्गा भाभी' कहा जाता था।
- उनका विवाह भगवती चरण वोहरा से हुआ था।

- उन्होंने अपने पति द्वारा दिए गए 5,000 रुपये की अपनी बचत क्रांतिकारी कार्यों पर और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय क्रांतिकारियों के समर्थन में खर्च की थी।
- वह एक क्रांतिकारी और जासूस महिला थीं।
- उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आश्रय दिया और बाद में उन्हें ब्रिटिश पुलिस से बचने हेतु खुद को भगत सिंह की पत्नी के रूप में प्रस्तुती देकर लाहौर से बाहर निकलना पड़ा।
- वह कई बंगाली क्रांतिकारियों से मिलीं और बम बनाना भी सीखा।
- वह नौजवान भारत सभा की सक्रिय सदस्या थीं।
- 8 अक्टूबर 1930 को, उन्होंने भागने से पहले दक्षिण बॉम्बे के लैमिंगटन रोड में पुलिस स्टेशन के पास एक ब्रिटिश हवलदार और उसकी पत्नी पर गोली चला दी।
 - यह गोली भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गई मौत की सजा का बदला लेने के लिए थी।
- आखिरकार सितंबर 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
- 1935 में, वह गाजियाबाद चली गईं और एक स्कूल में पढ़ाने लगीं।
- बाद में उन्होंने गरीब बच्चों के लिए लखनऊ में एक स्कूल खोला।
 - पंडित जवाहर लाल नेहरू एक बार स्कूल भी गए थे।

अवश्य पढ़ें: स्वामित्व योजना और पीएम स्वनिधि योजना

बिदरी शिल्प

संदर्भ: हाल ही में, कर्नाटक के वयोवृद्ध बिदरी शिल्प कलाकार, शाह रशीद अहमद कादरी ने व्यक्तिगत रूप से पद्म श्री से सम्मानित होने के बाद प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।

बिदरी शिल्प के बारे में:-



IMAGE SOURCE: [Bidri Art Research Work on Behance](#)

- बिदरी वेयर हस्तकला का एक पारंपरिक रूप है जिसकी उत्पत्ति बीदर, कर्नाटक में हुई थी।
- इसमें एक अनूठी तकनीक का उपयोग करके धातु के सामान की क्राफ्टिंग शामिल है।
- यह अपने जटिल डिजाइन और रूपांकनों के लिए जाना जाता है, जो अक्सर प्रकृति, इस्लामी कला और फारसी सुलेख से प्रेरित होते हैं।
- इसमें फूल, पत्ते और ज्यामितीय पैटर्न सहित सामान्य रूपांकन भी शामिल हैं।
- इसमें कई भागों में कुरान या अन्य इस्लामी ग्रंथों के छंद भी शामिल किया जाता है।
- बीदरी के बर्तनों को अपनी शिल्प कौशल और सांस्कृतिक महत्व के लिए कई पुरस्कार और पहचान मिली है।
- 2006 में, इसे भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत का दर्जा प्रदान किया गया, जो इसकी अनूठी उत्पत्ति और पारंपरिक क्राफ्टिंग तकनीकों को पहचानता है।
- बिदरी वेयर को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्यता दी गई है।

अवश्य पढ़ें: Etikoppaka वुडन टॉय क्राफ्ट

हक्की पिक्की

संदर्भ: कर्नाटक के हक्की पिक्की जनजाति समुदाय के 181 से अधिक सदस्य हिंसा प्रभावित सूडान में फँसे हुए हैं।

हक्की पिक्की के बारे में:

- कन्नड़ में हक्की का अर्थ है 'पक्षी' और पिक्की का अर्थ है 'पकड़ने वाला'।
- ये एक अर्ध-खानाबदोश जनजाति हैं, पारंपरिक रूप से पक्षी पकड़ने वाले और शिकारी हैं।
- ये चार कुलों में विभाजित हैं, जिन्हें गुजरातिया, पंवार, कालीवाला और मेवाड़ा कहा जाता है।

- कुलों के बीच एक पदानुक्रम था, जिसमें सबसे ऊपर गुजरातिया और सबसे नीचे मेवाड़ थे।
- ये आजीविका की तलाश में समूहों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
- माना जाता है कि हक्की पिक्की लोग मूल रूप से गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के रहने वाले हैं।
- ये आंध्र प्रदेश के रास्ते कर्नाटक पहुंचे, क्योंकि उन्हें अभी भी हैदराबाद के पास "जलापल्ली" नामक एक जगह उनके पैतृक घर के रूप में याद है, जहां उनके पूर्वज काफी समय तक रहे थे।
- ये अब पूरे दक्षिण भारत में फैले हुए हैं।
- कर्नाटक में इनकी जनसंख्या 11,892 है, और ये मुख्य रूप से दावणगेरे, मैसूर, कोलार, हासन और शिमोगा जिलों में रहते हैं।

थिरुनेली मंदिर

संदर्भ: हाल ही में, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) ने सरकार से थिरुनेली मंदिर के संरक्षण का आग्रह किया है।

थिरुनेली मंदिर के बारे में:-

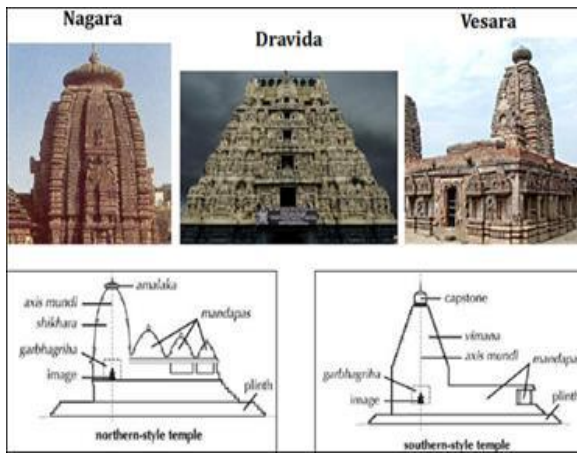


IMAGE SOURCE: [temple architecture types – Bing images](#)

- थिरुनेली महा विष्णु मंदिर वायनाड, केरल में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के पास एक प्रतिष्ठित मंदिर है।
- इसे "सहयामाला क्षेत्रम" और "दक्षिण की काशी" के रूप में भी जाना जाता है।
- थिरुनेली मंदिर शास्त्रीय, पारंपरिक केरल वास्तुकला का प्रतीक है।
- यह मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल, जो भगवान विष्णु को समर्पित है।
- इसे हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल माना जाता है।
- यह तीन नदियों के संगम पर स्थित है - पापनासिनी (पवित्र नदी, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें पापों को धोने की शक्ति है) कुदामुरुत्ती, और कूथपुड़ा है।
- मंदिर में ग्रेनाइट पत्थरों से बनी एक अनूठी गोलाकार संरचना है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने किया था।
 - मंदिर को 30 ग्रेनाइट स्तंभों के साथ ढाला गया है और जमीन को ग्रेनाइट के विशाल चौकोर टुकड़ों से पक्का किया गया है।
- इसमें सुंदर वास्तुकला और जटिल नक्काशी, भित्ति चित्र और मूर्तियां हैं।
- थिरुनेली मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भक्त जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद के जीवन से संबंधित सभी अनुष्ठान कर सकते हैं।
- मंदिर के पश्चिमी भाग में गुन्निका गुफा मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है।

अवश्य पढ़ें: श्रीशैलम मंदिर

तुगलकाबाद फोर्ट

संदर्भ: हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ASI को तुगलकाबाद किले के आसपास के अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा।

तुगलकाबाद किले के बारे में:-

- गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद का किला बनवाया था जो अब पूरी तरह से खंडहर हो चुका है।
 - गयासुद्दीन तुगलक : 1321 में तुगलक वंश का पहला सुल्तान।

- **मकबरे का अभिशाप:** एक किवदंती है कि गयासुद्दीन तुगलक एक शक्तिशाली किला चाहता था जो मंगोलों के हमले का सामना कर सके। इसलिए, सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद, उन्होंने बस्ती पर काम करना शुरू कर दिया और दिल्ली के सभी श्रमिकों के लिए किले पर काम करना अनिवार्य कर दिया।
- एक रक्षा तंत्र के रूप में चट्टानी इलाके पर किलेबंद शहर को चार साल में बनाया गया था।
- यह दो भागों में है, दक्षिणी दीवारों के साथ गढ़ और महल एक इकाई और दूसरी उत्तर में शहर बनाते हैं।
- दक्षिण से मुख्य प्रवेश द्वार के पार गयासुद्दीन (Ghiyathu'd-Din's tomb) का मकबरा स्थित है।
- इसका सामने का भाग लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसे संगमरमर से हटा दिया गया है, और बाहरी भाग पर बैटर है।
- यह एक अनियमित पंचभुज बनाने वाली ऊंची दीवारों के भीतर घिरा हुआ है।
- गयासुद्दीन के उत्तराधिकारी, मुहम्मद तुगलक (1325-51) ने तुगलकाबाद के दक्षिण में पहाड़ी पर 'आदिलाबाद' के छोटे किले को जोड़ा, जिसके साथ यह निर्माण की मुख्य विशेषताओं को साझा करता है।

अवश्य पढ़ें: रायगढ़ किला

उत्तरमेरुर शिलालेख

संदर्भ: हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में उत्तरमेरुर शिलालेख का उल्लेख किया।

उत्तरमेरुर शिलालेख के बारे में:-

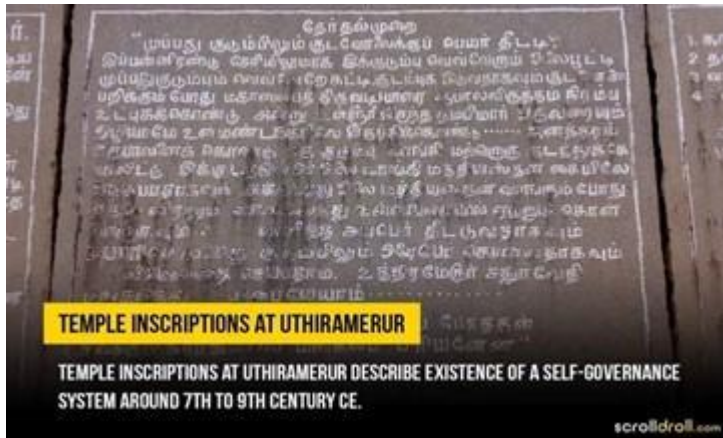


IMAGE SOURCE: [What are the less known facts about Tamil Nadu? – Quora](#)

- उत्तरमेरुर शिलालेख, परांतक चोल [907-955 A.D.] के शासनकाल में लगभग 920 A.D. का है।
 - उत्तरमेरुर: यह चेन्नई से लगभग 90 किमी दूर कांचीपुरम जिले में स्थित है।
 - पल्लव राजा नंदिवर्मन द्वितीय ने इसे लगभग 750 ईस्वी में स्थापित किया था।
- उत्तरमेरुर शिलालेख इस ऐतिहासिक तथ्य की गवाही देता है कि लगभग 1,100 साल पहले, एक गांव में एक विस्तृत और अत्यधिक परिष्कृत चुनावी प्रणाली थी और यहां तक कि चुनाव के तरीके को निर्धारित करने वाला एक लिखित संविधान भी था।
- निर्वाचित ग्राम लोकतंत्र की इस प्रणाली का विवरण ग्राम सभा (ग्राम सभा मंडप) की दीवारों पर अंकित है, जो ग्रेनाइट स्लैब से बनी एक आयताकार संरचना है।
- शिलालेख वार्डों के गठन, चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवारों की योग्यता, अयोग्यता मानदंड, चुनाव के तरीके, निर्वाचित सदस्यों के साथ समितियों के गठन, उन समितियों के कार्यों, गलत काम करने वाले को हटाने की शक्ति के बारे में आश्चर्यजनक विवरण देता है।
- ग्रामवासियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का भी अधिकार था यदि वे अपने कर्तव्य में विफल रहे।
- वास्तव में, तमिलनाडु के कई हिस्सों में मंदिरों की दीवारों पर शिलालेख ग्राम सभाओं का उल्लेख करते हैं।

अवश्य पढ़ें: सित्तनवासल जैन हेरिटेज साइट

रामकृष्ण मिशन

संदर्भ: हाल ही में, प्रधान मंत्री ने परोपकारी गतिविधियों के लिए रामकृष्ण मिशन की प्रशंसा की।

रामकृष्ण मिशन के बारे में:-

- रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी।

स्वामी विवेकानंद:-

- वे रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे।
 - रामकृष्ण परमहंस को भारत के महानतम आध्यात्मिक नेताओं में से एक माना जाता है।
 - वह देवी काली के भक्त थे और दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते और उनकी पूजा करते थे।
- अध्यात्मवाद के उनके संदेश ने न केवल हिंदू धर्म और समाज बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद को भी मजबूत करने में उल्लेखनीय योगदान दिया।
- वह सभी धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे।
- पहला मठ बाराणगर में स्थापित किया गया था।
- 1899 में, बेलूर में एक और 'मठ' शुरू किया गया, जो केंद्रीय 'मठ' बन गया।
 - यह पूरे भारत में और यहां तक कि इसके बाहर भी फैले सभी 'गणितों' के संगठन और कार्य की देखभाल करता है। यह रामकृष्ण मिशन के संतों का शैक्षिक केंद्र भी है।

रामकृष्ण मिशन का योगदान:-

- मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने, अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई और शिक्षा प्रणाली में कायापलट करने का काम किया।
- इसने हिंदू धर्म और संस्कृति की सर्वोच्चता पर बल दिया।
- यह सभी धर्मों की एकता और समानता में विश्वास करता था।
- आर्थिक दृष्टि से वे कृषि आधारित लघु उद्योगों के पक्षधर थे।
- इसने भारतीय राष्ट्रवाद और देशवासियों की जागृति में योगदान दिया।
- इससे सामान्य आध्यात्मिक विचारों पर आधारित नैतिक और शारीरिक शक्ति और एकता का विकास हुआ।
- इसने भारतीय युवाओं को जागरूक किया और जनता के बीच लालच और अज्ञानता को मिटाने के लिए काम किया।

अवश्य पढ़ें: दयानंद सरस्वती

महाड़ सत्याग्रह

संदर्भ: हाल ही में, अम्बेडकर द्वारा शुरू किए गए महाड़ सत्याग्रह और दलित आंदोलन की नींव घटना को याद किया गया।

महाड़ सत्याग्रह के बारे में :-

- महाड़ सत्याग्रह डॉ. भीम राव अम्बेडकर के नेतृत्व में अछूतों का पहला सामूहिक विरोध था।
- हर साल, 20 मार्च को भारत में महाड़ सत्याग्रह के उपलक्ष्य में सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि:-

- अछूतों को महाड़ तालाब के पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी।
- 1926 में, महाड़, महाराष्ट्र के नगरपालिका बोर्ड ने महाड़ शहर के प्रसिद्ध तालाब को सभी समुदायों के लिए खोलने का आदेश पारित किया।
- उच्च जाति के हिंदुओं ने नगर परिषद के इस आदेश का विरोध किया।
- जवाब में, अम्बेडकर ने म्यूनिसिपल बोर्ड के निर्णय का समर्थन करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया।
- अम्बेडकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ऊंच-नीच के विचारों को जड़ से उखाड़ने और आत्म-सहायता, आत्म-सम्मान और आत्म-ज्ञान के माध्यम से आत्म-उन्नति को मन में बैठाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- 1925 में महाड़ में एक सत्याग्रह सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें मांग की गई कि हिंदू समाज को समानता और जातिवाद के अभाव के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए।
- मनुस्मृति को जलाने का भी संकल्प लिया गया, क्योंकि अम्बेडकर के अनुसार, इसने अछूतों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक गुलामी को कायम रखा।

अवश्य पढ़ें: बी आर अम्बेडकर और महिला अधिकारिता

अम्बेडकर सर्किट

संदर्भ: हाल ही में, भारत सरकार ने अम्बेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन शुरू की।

अम्बेडकर सर्किट के बारे में:-

- अंबेडकर सर्किट 2016 में प्रस्तावित किया गया था।

- इसमें पांच प्रमुख स्थलों या "पंचतीर्थों" को शामिल किया गया है: -
 - महू: उनका जन्मस्थान
 - नागपुर: जहां उन्होंने अध्ययन किया
 - लंदन: जहां उन्होंने रहकर पढ़ाई की
 - दिल्ली: जहां उन्होंने अंतिम सांस ली
 - मुंबई: जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया

प्रासंगिकता के अन्य स्थल:-

- **रायगढ़, महाराष्ट्र:-**
 - डॉ. अम्बेडकर ने 1927 में महाड सत्याग्रह, दलितों के लिए स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक, महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किया।
- **पुणे, महाराष्ट्र:**
 - जहां उन्होंने यरवदा जेल में महात्मा गांधी के साथ पहली वार्ता की।
 - परिणाम दलित वर्गों की ओर से डॉ. अम्बेडकर द्वारा और उच्च जाति के हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षरित पूना पैक्ट था।
- **कोल्हापुर, महाराष्ट्र:**
 - मार्च 1920 में, एक अन्य प्रसिद्ध समाज सुधारक, छत्रपति शाहूजी महाराज ने डॉ. अम्बेडकर को भारत में उत्पीड़ित वर्गों का सच्चा नेता घोषित किया।
- **श्रीलंका:** जहां उन्होंने एक बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया।

अवश्य पढ़ें: नैतिक लोकतंत्र पर डॉ बी आर अम्बेडकर के विचार

कामाख्या मंदिर कॉरिडोर

संदर्भ: असम में सरकार वाराणसी के काशी-विश्वनाथ मंदिर गलियारे की तर्ज पर गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में एक गलियारे का निर्माण करने की योजना बना रही है।

कामाख्या मंदिर के बारे में:

- गुवाहाटी, असम में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है।
- इसे पूजा के सबसे पुराने और पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है।
- हर साल लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक मंदिर आते हैं, खासकर हर साल जून में आयोजित अम्बुबाची मेले के दौरान
 - अम्बुबाची मेला, देवी के वार्षिक मासिक धर्म को चिह्नित करने के लिए चार दिवसीय मेला है।
 - कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो शक्ति पंथ (Shakti cult) के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल है, प्रत्येक शक्तिपीठ, माता सती (भगवान शिव की पत्नी) के एक शरीर के अंग का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर के गर्भगृह में योनी (महिला जननांग) है, जो एक चट्टान का प्रतीक है।
 - मंदिर के पुजारियों ने कहा कि देवी काल का उत्सव मनाने वाला धार्मिक मेला भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में असम में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं के कम होने का एक कारण है।
 - असम में लड़कियों के नारीत्व की प्राप्ति को 'तुलोनी बिया' नामक एक रस्म के साथ मनाया जाता है, जिसका अर्थ है छोटी शादी।
 - भारत में तांत्रिक शक्तिवाद पंथ का एक केंद्रबिंदु
 - वास्तुकला की नीलाचल शैली: इसे दो अलग-अलग शैलियों के संयोजन से तैयार किया गया था, अर्थात्, पारंपरिक नगाड़ा या उत्तर भारतीय और सरसेनिक या मुगल।
 - मुख्य मंदिर दस महाविद्याओं को समर्पित अलग-अलग मंदिरों से घिरा हुआ है: काली, तारा, सोडाशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका।



भूगोल



सी-माउंट

संदर्भ: हाल ही में, वैज्ञानिकों ने 19,325 नए सीमाउंट खोजने की सूचना दी है।
सीमाउंट के बारे में:-

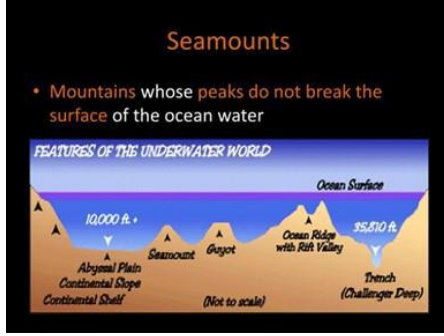


IMAGE SOURCE: [PPT – Features of the Ocean Floor PowerPoint Presentation, free download – ID:2365741 \(slideserve.com\)](https://www.slideserve.com/2365741)

- सीमाउंट समुद्र तल से उठने वाले जल के नीचे स्थित पहाड़ हैं।
- इनका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से होता है।
- ये समुद्री जीवन के लिए हॉटस्पॉट हैं।
- भूमि पर ज्वालामुखियों की तरह, सीमाउंट सक्रिय, विलुप्त या सुप्त ज्वालामुखी हो सकते हैं।
- अधिकांश सीमाउंट मध्य-महासागर की लकीरों के पास बनते हैं, जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो रही हैं, जिससे पिघली हुई चट्टानें समुद्र तल तक उठती हैं।
 - ग्रह के दो सबसे अधिक अध्ययन किए गए मध्य-महासागर रिज मध्य-अटलांटिक रिज और पूर्वी प्रशांत उदय हैं।
 - इंद्राप्लेट हॉटस्पॉट्स के पास कुछ सीमाउंट भी पाए गए हैं – जो एक प्लेट के भीतर भारी ज्वालामुखीय गतिविधि के क्षेत्र - और ज्वालामुखीय और भूकंपीय गतिविधि वाले समुद्री द्वीप श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें द्वीप आर्क्स कहा जाता है।
- सीमाउंट तब बनते हैं जब पिघली हुई चट्टान टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे से ऊपर आती है, वे मेंटल की संरचना और टेक्टोनिक प्लेट्स के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। **(यूपीएससी प्रारंभिक: प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना)**
- ये रहने के लिए अच्छे स्थान हैं क्योंकि वे स्थानीय महासागर के उत्थान का कारण बन सकते हैं। **(यूपीएससी मुख्य: अपवेलिंग और डाउनवेलिंग)**
 - **अपवेलिंग:** वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समुद्र के भीतर गहरे से पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह तक ऊपर जाता है।
- 2011 की एक जनगणना ने पहले ही दुनिया के महासागरों में 24,000 समुद्री पर्वतों की मैपिंग कर ली थी।
- 2011 के सीमाउंट सर्वेक्षण के बाद से, अल्टीमेट्री में सुधार हुआ है: -
 - यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रायोसैट-2 और एन्विसैट लॉन्च किया, और
 - नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से जेसन-1 जियोडेटिक मिशन लॉन्च किया।
- सरल (SARAL), एक उपग्रह जिसे भारत और फ्रांस ने मिलकर समुद्र संबंधी अध्ययन के लिए विकसित किया है, ने राडार शोर को और कम करके तथा सीमाउंट कैटलॉग के विस्तार को सक्षम करके एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। (यूपीएससी प्रीलिम्स: डीप-सी माइनिंग)

अवश्य पढ़ें: मिशन समुद्रयान

इंदिरा गांधी नहर

संदर्भ: हाल ही में, रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि मरम्मत के लिए इंदिरा गांधी नहर को बंद करने से राजस्थान के पीने के पानी

और सिंचाई की जरूरतों पर असर पड़ सकता है।

इंदिरा गांधी नहर के बारे में:-



IMAGE SOURCE: https://nwa.mah.nic.in/sdmc/irrigation/04_projects.htm

- इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबी है।
- इसका निर्माण 1952 से 2010 तक किया गया था।
- इसे मूल रूप से राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था।
- 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया।
- इस नहर का उद्गम पंजाब में हरिके बैराज से होता है।
- यह सतलुज और ब्यास नदियों पर बनी है।

नागरी दुबराज चावल

संदर्भ: हाल ही में, छत्तीसगढ़ की नागरी दुबराज चावल की किस्म, जम्मू की बसोहली पेंटिंग, बनारसी पान और लंगड़ा आम को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया।

नागरी दुबराज चावल के बारे में:-

- इसकी सुगंध के कारण इसे छत्तीसगढ़ का बासमती कहा जाता है।
- यह एक महिला स्वयं सहायता समूह "माँ दुर्गा स्वसहायता समूह" द्वारा निर्मित है।
- वाल्मीकि रामायण में अनाज का संदर्भ मिलता है।
- यह एक देशी किस्म है और इसके दाने छोटे होते हैं, पकाने के बाद खाने में बहुत नरम होती है।

बसोहली पेंटिंग के बारे में:-

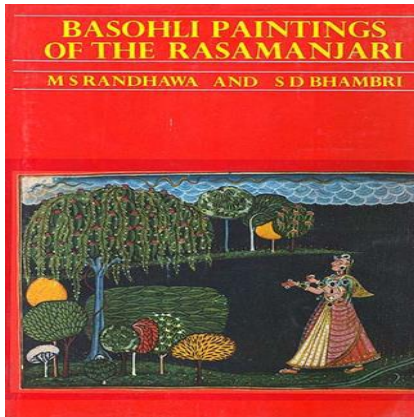


IMAGE SOURCE: [Basohli Paintings of the Rasamanjari | Exotic India Art](#)

- बसोहली पेंटिंग जम्मू के कठुआ जिले से संबंधित है।
- यह पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित है।
- इसमें लघु चित्रों की एक अनूठी शैली है जिसमें पौराणिक कथाओं और पारंपरिक लोक कला का मिश्रण है।
- इन चित्रों की विशिष्ट विशेषताएं सीमाओं में लाल, पीले और नीले जैसे चमकीले और बोल्ड रंगों के साथ-साथ आम तौर पर सपाट पृष्ठभूमि के लिए उपयोग थीं।
- अन्य विशिष्ट भाग जैसे प्रमुख नाक और कमल के आकार की आंखें चेहरे की विशेषताएं थीं।
- महिला आकृतियों को उनकी पोशाक के अनुसार तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

बनारसी पान के बारे में:-

- इसे बनारस, यूपी में बनाया जाता है।
- यह अपने स्वादिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है।
- इसे विशेष सामग्री का उपयोग करके अनोखे तरीके से बनाया जाता है।

- यह सुपारी, ताजे पान के कत्थे, तम्बाकू और बुझे हुए चूने का एक आकर्षक संयोजन है।
- इसमें अन्य सामग्री जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ (गुलकंद), सिल्वर फ्रॉइल (पोरेख) आदि मिलाई जाती हैं।

लंगड़ा आम के बारे में:-

- लंगड़ा आम की उत्पत्ति बनारस (अब वाराणसी) में हुई मानी जाती है।
- यह पकने के बाद अपने हरे रंग को बरकरार रखता है, जबकि अन्य आम पीले-लाल रंग में बदल जाते हैं।
- इस गूदेदार फल की खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान सहित राज्यों में मध्य मौसम में की जाती है।

जीआई टैग के बारे में:-

- इसका उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है या ऐसे गुण होते हैं जिन्हें विशेष रूप से क्षेत्र के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अनुसार जीआई टैग जारी किए जाते हैं।
- यह औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत आने वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक हिस्सा है।
- यह टैग 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध है जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

अवश्य पढ़ें: मिथिला मखाना को जीआई टैग
Earth4All पहल

संदर्भ: हाल ही में प्रकाशित Earth4All इनिशिएटिव ने दुनिया की मानव आबादी की भविष्यवाणी की।

Earth4All पहल के बारे में:-

- Earth4All प्रमुख आर्थिक विचारकों, वैज्ञानिकों और अधिवक्ताओं की एक सामूहिक पहल है।
- यह द क्लब ऑफ रोम, पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च, स्टॉकहोम रेजिलिएंस सेंटर और नॉर्वेजियन बिजनेस स्कूल द्वारा आयोजित किया जाता है।
- यह एक परिवर्तनकारी अर्थशास्त्र आयोग द्वारा निर्देशित है, जो नई आर्थिक सोच का पता लगाने और मॉडल परिणामों का परीक्षण करने के लिए दुनिया भर के आर्थिक विचारकों से बना है।
- इसके वैश्विक अभियान का उद्देश्य Earth4All विजन को वास्तविकता बनाना है, सरकारों को ऐसी नीतियों को अपनाने की वकालत करना है जो लचीले और स्वस्थ समाजों को सक्षम बनाएगी।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:-

- शोधकर्ता दो परिदृश्यों को आगे बढ़ाते हैं:
 - **टू लिटिल, टू लेट:** यह भविष्यवाणी करता है कि यदि आर्थिक विकास पिछले पांच दशकों में जारी रहा, तो दुनिया की आबादी 2050 में 8.6 बिलियन हो जाएगी, और 2100 तक घटकर 7 बिलियन हो जाएगी।
 - **द जाइंट लीप:** शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि जनसंख्या 2040 तक 8.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी, लेकिन फिर 2100 तक तेजी से घटकर लगभग 6 बिलियन हो जाएगी।
- यह गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य, असमानता में सुधार, और खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा में हमारे निवेश के कारण होगा।
- Earth4All रिपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र की 'वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022' रिपोर्ट का खंडन किया, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि वैश्विक जनसंख्या 2080 में लगातार बढ़कर 10.4 बिलियन हो जाएगी और फिर 2100 में उस संख्या के आसपास स्थिर हो जाएगी।

भारतीय परिदृश्य:-

- 2022 तक, दुनिया की आधी से अधिक आबादी एशिया में रहती है।
 - चीन और भारत दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के अनुसार, जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो रही है, यह अभी भी 0.7% की दर से बढ़ रही है, जनसंख्या को स्थिर करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम-
- नसबंदी स्वीकार करने वालों के लिए मिशन परिवार विकास मुआवजा योजना: इस योजना के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय लाभार्थी को मजदूरी के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करता है।
- क्लिनिकल आउटरीच टीम (सीओटी) योजना: यह मोबाइल टीमों के माध्यम से परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने

के लिए है।

- लाभार्थियों के घर पर आशा द्वारा गर्भ निरोधकों की होम डिलीवरी की योजना।
- परिवार नियोजन रसद प्रबंधन और सूचना प्रणाली (FP-LMIS): परिवार नियोजन राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (NFPIS) के सुचारू पूर्वानुमान, खरीद और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित सॉफ्टवेयर जिसके तहत ग्राहकों को नसबंदी के बाद मृत्यु, जटिलता और विफलता की स्थिति में बीमा किया जाता है।
- सभी राज्यों और जिलों में गुणवत्ता आश्वासन समितियों की स्थापना करके परिवार नियोजन सेवाओं में देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

अवश्य पढ़ें: विश्व जनसंख्या संभावनाएँ

ताइवान जलडमरूमध्य

संदर्भ: हाल ही में, चीन ने ताइवान जलडमरूमध्य में एक सैन्य अभ्यास किया।

ताइवान जलडमरूमध्य के बारे में:-



IMAGE SOURCE: [cover-taiwan \(cover man. be\)](https://www.cover-taiwan.com)

- ताइवान जलडमरूमध्य ताइवान और महाद्वीपीय एशिया (चीन विशिष्ट होने के लिये) के द्वीपों को अलग करने वाला 180 किलोमीटर चौड़ा जलडमरूमध्य है।
- इसे फॉर्मोसा जलडमरूमध्य के नाम से भी जाना जाता है।
- **जलडमरूमध्य:** समुद्र का एक संकरा टुकड़ा जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है।
- जलडमरूमध्य वर्तमान में दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है और उत्तर में पूर्वी चीन सागर से जुड़ता है।
- पूरा जलडमरूमध्य एशिया के महाद्वीपीय शेल्फ पर है।
- ऐतिहासिक रूप से चीन जनवादी गणराज्य (पीआरसी) और ताइवान दोनों ने एक-चीन नीति का समर्थन किया है।

- **वन-चाइना नीति:** जो एकल "चीन" के विशेष आर्थिक क्षेत्र के जलडमरूमध्य भाग पर विचार करती है।

अवश्य पढ़ें: चीन-ताइवान टसल (China- Taiwan Tussle)

जोजिला सुरंग

संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने निर्माणाधीन जोजिला सुरंग का निरीक्षण किया।

जोजिला सुरंग के बारे में:-

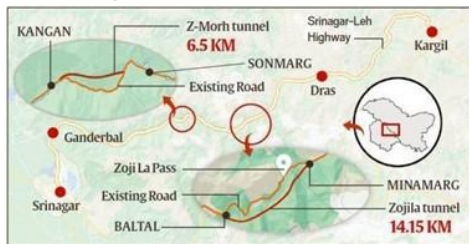


IMAGE SOURCE: [Why the Zojila tunnel promises to revolutionise connectivity to Ladakh – Kashmir.Report](https://www.kashmirreport.com)

- यह सुरंग NH-1 पर श्रीनगर घाटी और लेह के बीच सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी।
- यह जम्मू और कश्मीर का चौतरफा आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण लाएगा।
- वर्तमान में श्रीनगर और लद्दाख के बीच यात्रा करने में 3.5 घंटे लगते हैं।
- यह सुरंग यात्रा के समय को घटाकर 15 मिनट कर देगी।
- 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग होगी।

अवश्य पढ़ें: जोजिला टनल का काम

जीरो शैडो डे

संदर्भ: हाल ही में, बेंगलुरु ने जीरो शैडो डे मनाया।

जीरो शैडो डे के बारे में:-

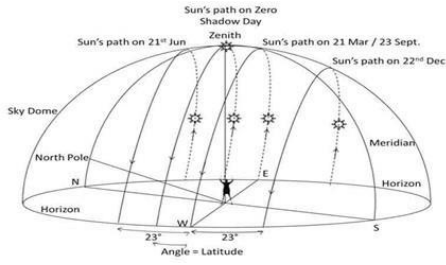


IMAGE SOURCE: [YOUTH TREND](#)

- 'जीरो शैडो डे' एक खगोलीय घटना है जो दुनिया के कुछ हिस्सों में विशिष्ट तिथियों पर वर्ष में दो बार घटित होती है।
- यह एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है।
- इस दौरान खंभे, पेड़ और इमारतों जैसी खड़ी वस्तुओं की छाया कुछ समय के लिए पूरी तरह से गायब हो जाती है।
- प्रत्येक वर्ष मई और जुलाई/अगस्त में दो जीरो शैडो डे होते हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित स्थानों में देखे जाते हैं।
 - पहला उत्तरायण के दौरान गिरता है (जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है)।
 - दूसरा दक्षिणायन के दौरान होता है (जब सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ता है)।
- यह एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से तक रहता है, लेकिन इसका असर एक मिनट से डेढ़ मिनट तक देखा जा सकता है।
- रामानुजन ने समझाया कि सूर्य की स्थिति पृथ्वी के भूमध्य रेखा के 23.5°N से 23.5°S तक चलती है और वापस आती है।
 - वे सभी स्थान जिनका अक्षांश उस दिन सूर्य के स्थान और भूमध्य रेखा के बीच के कोण के बराबर होता है, स्थानीय दोपहर में किसी वस्तु के नीचे छाया के साथ जीरो शैडो डे का अनुभव करते हैं।

अवश्य पढ़ें: आदित्य-एल1 मिशन

कामचटका प्रायद्वीप

संदर्भ: रूस के कामचटका प्रायद्वीप में रूस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी 'द शिवलुच ज्वालामुखी' हाल ही में फट गया।

कामचटका प्रायद्वीप के बारे में:-

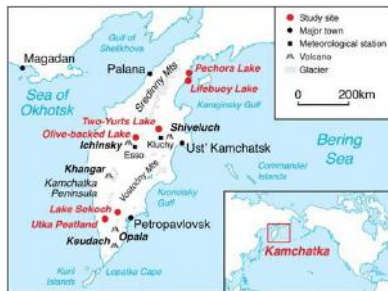


IMAGE SOURCE: [Location of the Kamchatka Peninsula showing the main volcanoes and...](#)

Download Scientific Diagram ([researchgate.net](#))

- कामचटका प्रायद्वीप रूसी सुदूर पूर्व में 1,250 किलोमीटर लंबा प्रायद्वीप है।
- प्रशांत महासागर और ओखोटस्क सागर क्रमशः प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी तट बनाते हैं।
- प्रायद्वीप के प्रशांत तट के साथ तुरंत अपतटीय 10,500 मीटर गहरी कुरील-कामचटका खाई चलती है।
- कामचटका प्रायद्वीप, कमांडर द्वीप और कारागिंस्की द्वीप रूसी संघ के कामचटका क्राय का गठन करते हैं।
- 322,079 निवासियों में से अधिकांश जातीय रूसी हैं, हालांकि लगभग 13,000 कोर्यक (2014) हैं।
- कामचटका प्रायद्वीप में कामचटका के ज्वालामुखी हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
- सबसे ऊंची चोटी यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, क्लाईचेव्स्काया सोपका (4750 मीटर) है।
- कामचटका के ऊंचे हिस्से 446 हिमनदों (सोलोमिना एवं अन्य, 2007) से आच्छादित लगभग 900 वर्ग किमी के क्षेत्र के साथ हिमाच्छादित हैं।

अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और भारत-रूस संबंध

आइंस्टीन का

संदर्भ: हाल ही में, डार्क मैटर का एक नया विस्तृत नक्शा आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से सहमत हुआ है।

गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत

आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में :-

- अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में सामान्य सापेक्षता के अपने पूर्ण सिद्धांत को प्रकाशित किया।
- इस सिद्धांत के अनुसार, कोई भी गति प्रकाश की गति से अधिक नहीं हो सकती है।
- सामान्य सापेक्षता (जीआर) में, द्रव्यमान और ऊर्जा की सांद्रता स्पेसटाइम की संरचना को वक्र करती है, जिससे प्रकाश सहित पास से गुजरने वाली किसी भी चीज की गति प्रभावित होती है।
- भौतिकविदों ने सामान्य सापेक्षता का उपयोग करते हुए कई विदेशी भविष्यवाणियां कीं।

सिद्धांत का महत्व :-

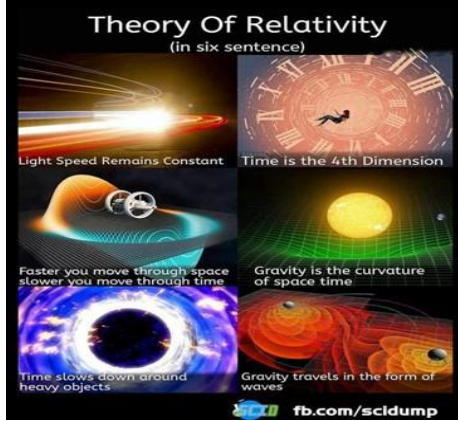


IMAGE SOURCE: [Space – SciDump](https://www.facebook.com/scidump)

- सिद्धांत ने बुध की विषम कक्षा की व्याख्या की।
- 1919 में जब आर्थर एडिंगटन और उनके सहयोगियों ने पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान तारों के प्रकाश पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को मापा।
- सूर्य के चारों ओर प्रकाश का झुकना छोटा है, लेकिन शोधकर्ताओं ने महसूस किया कि आकाशगंगाओं के लिए प्रभाव बहुत बड़ा होगा, जहां गुरुत्वाकर्षण अधिक दूर की वस्तुओं की छवियां बनाएगा।
 - इस घटना को अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है।
- सिद्धांत ने ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की
 - **ब्लैक होल:** गुरुत्वाकर्षण के साथ वस्तुएं इतनी तीव्र होती हैं कि कुछ भी बहुत करीब होने से फिर से बच नहीं सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं।
- सामान्य सापेक्षता ने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण की एक गति होती है, जो प्रकाश की गति के समान होती है। ब्लैक होल या न्यूट्रॉन सितारों के बीच टकराव जैसी भयावह घटनाएं गुरुत्वाकर्षण तरंगें पैदा करती हैं। शोधकर्ताओं ने आखिरकार 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी (LIGO) का उपयोग करके इन तरंगों का पता लगाया।
 - लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी (एलआईओ): एक संवेदनशील प्रयोगशाला जिसे विकसित होने में दशकों लग गए।

अवश्य पढ़ें: डार्क मैटर

ELVES (विद्युत चुम्बकीय पल्स स्रोतों के कारण प्रकाश का उत्सर्जन और बहुत कम आवृत्ति गड़बड़ी)

संदर्भ: हाल ही में, चमकदार प्रभामंडल का एक शॉट जिसे प्रकाश का उत्सर्जन कहा जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स स्रोतों, या ईएलवीई के कारण बहुत कम आवृत्ति गड़बड़ी इटली में दर्ज की गई थी।
इसके बारे में:-

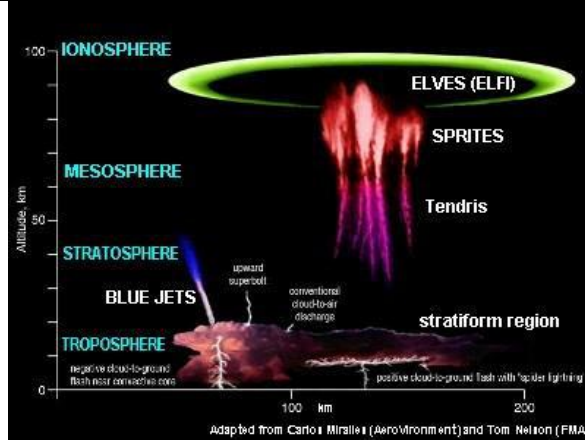
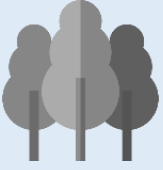


IMAGE SOURCES: [SkySentinel](#)

- ELVES (विद्युत चुम्बकीय स्पंद स्रोतों के कारण प्रकाश का उत्सर्जन और बहुत कम आवृत्ति गड़बड़ी) टीएलई के अस्पष्ट प्रकार हैं, जो 400 किमी व्यास तक बड़े फैलाव और विस्तारित अंगूठी के आकार की चमक पैदा करते हैं।
- ये आयनमंडल में धरातल से 100 किमी ऊपर गरज के साथ होते हैं।
- **जनरेशन:** इलेक्ट्रॉन टकराव के कारण नाइट्रोजन अणुओं के उत्तेजना से प्रकाश उत्पन्न होता है (इलेक्ट्रॉनों को संभावित रूप से एक अंतर्निहित तूफान से निर्वहन के कारण विद्युत चुम्बकीय पल्स द्वारा सक्रिय किया गया है)।
- वे इतने तेज (0.001 सेकेंड) होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखना असंभव है।
- **सुरक्षा चिंताएं:-**
 - यह संभव है कि स्प्राइट्स और जेट तूफान के ऊपर सीधे उड़ान भरने वाले विमान के उड़ान इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्युत चुम्बकीय स्पंदन पैदा कर सकते हैं लेकिन प्रमाण सीमित हैं।

अवश्य पढ़ें: बिजली 'आपदा



पर्यावरण



प्रोजेक्ट टाइगर

संदर्भ: हाल ही में, बांदीपुर ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 वर्ष पूरे किए।

प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में:-

- इंदिरा गांधी सरकार ने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था।
- बाघ विश्व स्तर पर लुप्तप्राय प्रजाति है। बीसवीं शताब्दी के अंत में भारत में बाघों की आबादी 20000 से 40000 के बीच थी।
- संरक्षणवादियों और शोधकर्ताओं के एक समूह ने 1970 के आसपास भारत सरकार पर निरंतर दबाव बनाया।
- परिणामस्वरूप, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया, जिसने भारत में सभी प्रकार के शिकार को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया और कानूनी रूप से व्यक्तिगत प्रजातियों की रक्षा की।
- वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था।
- डॉ. कैलाश सांखला को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का पहला निदेशक नामित किया गया था।

बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में:-

- इसकी स्थापना 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी।
- 1985 में, वेणुगोपाला वन्यजीव पार्क से सटे क्षेत्रों को शामिल करके, इसका विस्तार किया गया और इसका नाम बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया।
- यह कर्नाटक के दो निकटस्थ जिलों (मैसूर और चामराजनगर) में स्थित है।
- यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रि-जंक्शन क्षेत्र में स्थित है।
- यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है।
- यह देश के सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्रों में से एक में स्थित है।
- यह घिरा हुआ है-
 - दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व (तमिलनाडु),
 - वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल) दक्षिण-पश्चिम में और
- काबिनी जलाशय उत्तर-पश्चिम में बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व को अलग करता है।
- यह पार्क उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी के बीच स्थित है।
- नुगु नदी पार्क से होकर गुजरती है।
- पार्क का सबसे ऊंचा स्थान हिमवद गोपालस्वामी बेट्टा नामक पहाड़ी पर है।

अवश्य पढ़ें: बाघ का अनुमान

टाइगर सेंसस 2022

संदर्भ: हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान (2022) के पांचवें चक्र के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या 2022 में बढ़कर 3,167 हो गई है, जो 2018 में 2,967 थी (6.74% की वृद्धि)।

अखिल भारतीय बाघ अनुमान (2022) के प्रमुख निष्कर्ष:-

- भारत में बाघों की आबादी 2018 से 2022 तक 200 बढ़ी है।
- बाघों की आबादी शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के बाढ़ के मैदानों में सबसे अधिक बढ़ी है, इसके बाद मध्य भारत, उत्तरपूर्वी पहाड़ियों, ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदानों और सुंदरबन का स्थान आता है।

टाइगर सेंसस 2022 के बारे में:-

- राष्ट्रीय बाघ गणना हर चार साल में एक बार आयोजित की जाती है।
- राष्ट्रव्यापी बाघ गणना इससे पहले 2006, 2010, 2014 और 2018 में हुई थी।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) राज्य के वन विभागों, संरक्षण गैर सरकारी संगठनों और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के साथ साझेदारी में बाघों की गणना करता है।
- भारत जंगलों में रहने वाली वैश्विक बाघ आबादी का लगभग 75% हिस्सा है।

अवश्य पढ़ें: बाघ का अनुमान

दिबांग वन्यजीव अभयारण्य

संदर्भ: हाल की घोषणाओं के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

दिबांग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:-

- दिबांग वन्यजीव अभयारण्य अनीनी जिले, अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है।
- इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिबांग नदी के नाम पर रखा गया है।
- यह पूर्वी हिमालय के हिस्से में है।
- **वनस्पति:** वनस्पति की दो मुख्य श्रेणियां समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन और समशीतोष्ण शंकुवृक्ष वन (रोडोडेंड्रोन, बांस, ग्रेगरिया, त्सुगा आदि) हैं।
 - अल्पाइन वनस्पति जड़ी-बूटियों, छोटे पेड़ों और बौनी झाड़ियों के साथ अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है।
- **जीव-जंतु:** मिशमी ताकिन, एशियाई काला भालू, बाघ, गोंगशान मंटजेक, लाल पांडा, लाल गोरल और कस्तूरी मृगा।

इदु मिशिमस के बारे में:-

- यह अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी तिब्बत में बड़े मिशमी समूह की एक उप-जनजाति है।
- वे मुख्य रूप से तिब्बत की सीमा से लगी मिशमी पहाड़ियों में रहते हैं।
- ऐसा माना जाता है कि वे मंगोलायड जाति से आए थे।
 - **मंगोलायड जाति:** तिब्बती-बर्मन परिवार से संबंधित हैं।
- उनकी भाषा (जिसे इदु मिशमी भी कहा जाता है) को यूनेस्को द्वारा संकटग्रस्त माना जाता है।
- वे 'आईयू-एना' जैसे मिथकों और वर्जनाओं की एक सख्त विश्वास प्रणाली का पालन करते हैं।
 - **इयू-एना (Iyu-ena) :** उन्हें बाघों को मारने पर पूर्ण प्रतिबंध सहित कई जानवरों के शिकार से प्रतिबंधित करना।

अवश्य पढ़ें: अरुणाचल प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण

एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान

संदर्भ: हाल ही में, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को इसके परिसर के अंदर एक टेरायम मिलता है।

एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:-

- यह केरल के एराविकुलम और इडुक्की जिलों में स्थित है।
- यह उच्च श्रेणी (कन्नन देवन हिल्स) में स्थित है।
- यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी की मेजबानी करता है।
- यह नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है।
- एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की एक और विशेषता नीलकुर्रिंजी फूल है जो हर 12 साल में खिलता है।
- वर्ष 1975 में सरकार ने इस क्षेत्र को एराविकुलम वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया।
- वर्ष 1978 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- **वनस्पति:** घास के मैदान, झाड़ीदार भूमि, और शोला वन तीन प्रमुख पौधों की प्रजातियाँ मौजूद हैं।
- यह पूर्व की ओर बहने वाली नदियों (पम्बर की सहायक नदियाँ) और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों (पेरियार और चालाक्कुडी की सहायक नदियाँ) दोनों के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
- **जीव-जंतु:** राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले अन्य जानवर लायन-टेल्ड मकाक, भारतीय मंटजेक, गौर और सांभर हिरण हैं।
- **फ्लोरा:** पार्क में तीन प्रमुख प्रकार के पादप समुदाय हैं, जैसे घास के मैदान, झाड़ियाँ और जंगल।

फर्न्स के बारे में:-

- फर्न्स संवहनी पौधों के समूह का सदस्य है।
 - **संवहनी पौधे:** जाइलम और फ्लोएम वाले पौधे।
- वे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं।
- इनमें न तो बीज होते हैं और न ही फूल।
- उनके पास विशेष ऊतक होते हैं जो पानी और पोषक तत्वों का संचालन करते हैं और जीवन चक्र में स्पोरोफाइट प्रमुख चरण होता है।
- इनकी जटिल पत्तियाँ होती हैं जिन्हें मेगाफिल्स कहते हैं।

	<p>महत्व:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • इनका उपयोग भोजन, दवा और जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। • इनका उपयोग सजावटी पौधों के रूप में और दूषित मिट्टी को ठीक करने के लिए किया जाता है। • ये वातावरण से कुछ रासायनिक प्रदूषकों को हटाने की अपनी क्षमता के लिए शोध का विषय रहे हैं। • फ़र्न की कुछ प्रजातियाँ, जैसे ब्रेकेन (टेरिडियमक्विलिनम) और वॉटर फ़र्न (एज़ोलाफ़िलिकुलोइड्स) दुनिया भर में महत्वपूर्ण खरपतवार हैं। • फ़र्न के कुछ वंश, जैसे एजोला, नाइट्रोजन को ठीक कर सकते हैं और चावल के धान के नाइट्रोजन पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट बना सकते हैं। • ये लोककथाओं में भी कुछ भूमिकाएँ निभाते हैं। <p>अवश्य पढ़ें: साइलेंट वैली नेशनल पार्क</p>
<p>विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट</p>	<p>संदर्भ: हाल की रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन ने प्रगति की है लेकिन यह 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे से कम है।</p> <p>वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) द्वारा निकाला जाता है। • विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा परिदृश्य के संक्रमण के लिए एक दृष्टि की रूपरेखा तैयार करता है। • यह पूर्व-औद्योगिक स्तरों के 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और सदी के मध्य तक CO2 उत्सर्जन को शुद्ध शून्य पर लाने के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करता है। • यह आउटलुक पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप एक जलवायु-सुरक्षित भविष्य प्राप्त करने के लिए एक विकसित मार्ग को दर्शाता है। • इसका 1.5°C पाथवे नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन और टिकाऊ बायोमास द्वारा समर्थित परिवर्तन के प्रमुख चालकों के रूप में विद्युतीकरण और दक्षता की स्थिति बनाकर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को तेज करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है। • यह पूर्वावलोकन आगामी 2023 रिपोर्ट से उच्च-स्तरीय अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है, जो 1.5°C जलवायु लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में वैश्विक प्रगति को पकड़ने के लिए IRENA के दो प्रमुख परिदृश्यों नियोजित ऊर्जा परिदृश्य (PES) और 1.5°C परिदृश्य पर आधारित है। • अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA):- <ul style="list-style-type: none"> ○ यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। ○ इसे आधिकारिक तौर पर 2009 में बॉन, जर्मनी में स्थापित किया गया था। ○ इसके 167 सदस्य हैं और भारत IRENA का 77वां संस्थापक सदस्य है। ○ इसका मुख्यालय अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में है। <p>अवश्य पढ़ें: अक्षय ऊर्जा संक्रमण</p>
<p>सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य</p>	<p>सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। • यह नेपाल में महादेवपुरी के जंगल से जुड़ा हुआ है। • इसे 1988 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। • फ्लोरा: साल, शीशम, खैर, सागौन (सागौन), असना, जामुन, हल्दू, फलदू, धमीना, झिंगान और बहेड़ा के पेड़। • जीव-जंतु: तेंदुआ, बाघ, भालू, जंगली बिल्ली, जंगली सूअर और विभिन्न पक्षी। • सोहेलवा वन्य जीवन प्रभाग भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। • इस अभयारण्य क्षेत्र से सटे हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ हैं। <p>सांस्कृतिक पहलू: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • बलरामपुर-बहराइच मार्ग पर लगभग 15 किमी की दूरी पर स्थित श्रावस्ती, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है जिसे बौध दांत के नाम से जाना जाता है। • देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में स्थित है यह मंदिर मां दुर्गा का सिद्धपीठ है।

कुद्रेमुख रेंज

- बाबा विभूतिनाथ मंदिर, जो एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, पूर्वी सोहेलवा रेंज में स्थित है।

संदर्भ: हाल ही में, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (KIOCL) ने कुद्रेमुख रेंज में 700 एकड़ जंगल को समाहित करने के लिए कार्योंतर स्वीकृति मांगी है।

कुद्रेमुख श्रेणी के बारे में:-

- यह कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है।
- इसे इसका नाम इसकी मुख्य चोटी, कुद्रेमुख चोटी (1892 मीटर) से मिला है, जिसका चेहरा घोड़े के चेहरे जैसा दिखता है।
- कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट में दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र, इन श्रेणियों में स्थित है।
- ऐसा माना जाता है कि कुद्रेमुख ने 2000 से अधिक वर्षों तक पश्चिमी तट पर नाविकों के लिए एक मील का पत्थर के रूप में कार्य किया।

कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान :-

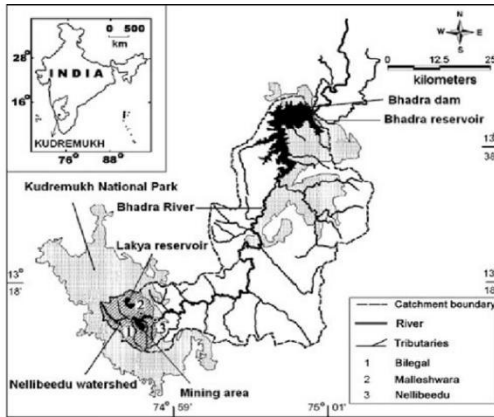


IMAGE SOURCE: [Map showing the location of the Kudremukh mining area and sampling sites.... | Download Scientific Diagram \(researchgate.net\)](#)

- कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में नरसिम्हा पर्वत से लेकर दक्षिण में जमालाबाद किले तक फैला हुआ है।
- कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में तीन जिलों अर्थात् दक्षिण कन्नड़, उडुपी और चिकमंगलूर के क्षेत्र शामिल हैं।
- इसे वर्ष 1916 में एक आरक्षित वन के रूप में स्थापित किया गया था।
- 1987 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
- तुंगा, भद्रा और नेत्रावती नदियाँ इस राष्ट्रीय उद्यान से निकलती हैं।
- प्रसिद्ध कदंबी जलप्रपात भी कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है।
- **मुख्य विशेषता:** यह दुनिया में शेर की पूंछ वाले मकाक (LTM) की सबसे बड़ी सन्निहित आबादी है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, शीर्ष तीन मांसाहारी (बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्ते)।
- **जीव-जंतु:** बाघ, जंगली कुत्ते, तेंदुआ, मालाबार विशाल गिलहरी, सुस्त भालू, कॉमन लंगूर, गौर, सांभर, भौंकने वाले हिरण, चित्तीदार हिरण।
 - पार्क में पाई जाने वाली 195 पक्षियों की प्रजातियों में मालाबार सीटी थ्रश, मालाबार ट्रोगोन, शाही कबूतर और ग्रेट पाइड हॉर्नबिल शामिल हैं।
- **वनस्पति:** इसमें सबसे कम विक्षुब्ध कम ऊंचाई वाले गीले सदाबहार वन और शोला-घास के मैदान बायोम हैं।
 - कुद्रेमुख दुनिया के प्रमुख आवासों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें उष्णकटिबंधीय जैविक समृद्धि है और इस प्रकार यह दुनिया के 34 जैविक हॉटस्पॉट में से एक है।

अवश्य पढ़े: इको-सेंसिटिव जोन (ESZ)

सुखना वन्यजीव अभयारण्य

संदर्भ: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने सुखना वन्यजीव अभयारण्य के मामले पर एक आदेश पारित किया।

सुखना वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:-

- सुखना वन्यजीव अभयारण्य चंडीगढ़ में है, और क्रमशः मोहाली और पंचकुला की तरफ से पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। (यूपीएससी सीएसई: वन्यजीव संरक्षण को समझना)
- इसमें 1.75 किमी तक का ESZ क्षेत्र है, और पक्षी अभयारण्य, सेक्टर 21 में लगभग 100 मीटर का ESZ है।
- यह सुखना झील के उत्तर-पूर्व में 1 कि.मी. पर स्थित है।

	<ul style="list-style-type: none"> • यह शिवालिक पहाड़ियों में पड़ने वाले सुखना झील जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है <ul style="list-style-type: none"> ○ शिवालिक पहाड़ियाँ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और भूगर्भीय रूप से अस्थिर हैं। ○ बारिश के दौरान वे मिट्टी के कटाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ○ शिवालिक में मिट्टी रेतीली है, जिसमें मिट्टी की परतें जमी हुई हैं, जो सतही अपवाह द्वारा अपरदन के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं। • सुखना झील का निर्माण 1958 में किया गया था और साठ तथा सत्तर के दशक की शुरुआत में, इसके जलग्रहण क्षेत्र से मिट्टी के कटाव की उच्च दर के कारण झील के गाद की दर बहुत अधिक थी। • पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2020 में सुखना झील (चंडीगढ़) को एक जीवित इकाई घोषित किया। • 1988 तक, झील की मूल जल धारण क्षमता का 66% गाद के कारण खो गया था। (यूपीएससी मेन्स: वाइल्डलाइफ डिप्लोमेसी) <p>अवश्य पढ़ें: कंबालाकोडा वन्यजीव अभयारण्य</p>
<p>उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन (PRET) पहल</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, WHO ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन (PRET) पहल शुरू किया।</p> <p>इसके बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह WHO की तैयारी और उभरते खतरों के लिए लचीलापन (PRET) पहल है। • यह रोग महामारी की तैयारी में सुधार के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण है। (यूपीएससी मेन्स: COVID-19 महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उभरते मुद्दे)। • पीआरईटी का पहला मॉड्यूल श्वसन रोगजनक महामारी की तैयारी पर केंद्रित है। <ul style="list-style-type: none"> ○ यह एक एकीकृत और कुशल श्वसन रोगजनक महामारी नियोजन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें नए रोगजनकों और महामारी क्षमता वाले ज्ञात दोनों को शामिल किया गया है। (यूपीएससी सीएसई: डब्ल्यूएचओ और पारंपरिक चिकित्सा)। ○ यह बेहतर तैयारी के लिए रोगजनक-अज्ञेयवादी और रोगजनक-विशिष्ट तत्वों को संबोधित करने में सुसंगतता को सक्षम बनाता है। ○ यह महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया अवधियों के बीच वृद्धि और डी-एस्केलेशन के लिए परिचालन चरणों और ट्रिगर सहित एक आयोजन ढांचा प्रदान करता है। ○ यह बहु-क्षेत्रीय सहयोग को गति प्रदान करने के लिए श्वसन रोगजनक महामारी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का वर्णन करता है। <p>अवश्य पढ़ें: H5N1 वायरस/बर्ड फ्लू</p>
<p>बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने चार उप-व्यस्क जंगली भैंसों को असम से छत्तीसगढ़ के बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया।</p> <p>बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। • बरनवापारा नाम गांव बार और नवापारा से गढ़ा गया। • बालमेढ़ी, जोंक और महानदी नदियाँ जीवनरेखा नदी हैं जो अभयारण्य के साथ-साथ चलती हैं। • बलमदेही नदी पश्चिमी सीमा बनाती है और जोंक नदी अभयारण्य की उत्तरपूर्वी सीमा बनाती है। • अभयारण्य के अंदर स्थित बलार जलाशय कई आर्द्रभूमि पक्षियों और मछलियों का आश्रय है। • वनस्पति: अभयारण्य में सागौन, साल और मिश्रित वन की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। • जीव: चीतल, सांभर, नीलगाय जंगली सूअर, सुस्त भालू और जंगली कुत्ते, आमतौर पर देखे जाते हैं। <p>भारतीय जंगली भैंस</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह छत्तीसगढ़ (भारत) का राजकीय पशु है। • पर्यावास: मुख्य रूप से जलोढ़ घास के मैदानों, दलदल, दलदल और नदी घाटियों में पाया जाता है। • भारत में, वे आम तौर पर पूर्वोत्तर भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस और डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यानों, लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य और बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश में डी'एरिंग मेमोरियल

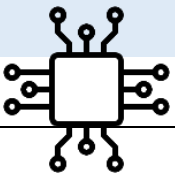
वन्यजीव अभयारण्य में केंद्रित हैं।

● संरक्षण की स्थिति:

○ आईयूसीएन: संकटग्रस्त

○ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची 1।

अवश्य पढ़ें: तुंगेश्वर वन्यजीव अभयारण्य



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

कालाजार

संदर्भ: हाल ही में, IACS के नए यौगिक को दवा प्रतिरोधी कालाजार संक्रमणों का इलाज करने के लिए पाया गया था।
कालाजार के बारे में:-

WHAT IS KALA-AZAR	
<ul style="list-style-type: none"> A slow progressing indigenous disease Caused by protozoan parasite of genus <i>Leishmania</i> In India, <i>Leishmania donovani</i> is the only parasite causing the disease The parasite primarily infects reticuloendothelial system 	Signs & Symptoms <ul style="list-style-type: none"> Recurrent fever Loss of appetite Weakness Spleen enlargement Anaemia
Transmission	
<ul style="list-style-type: none"> Sandfly of genus <i>Phlebotomus argentipes</i> only known vector of kala-azar in India 	<ul style="list-style-type: none"> Female sandflies pick up parasite while feeding on infected human host
<ul style="list-style-type: none"> Indian kala-azar has a unique epidemiological feature of being anthroponotic Development and multiplication in the gut of sandflies and move to mouthparts 	<ul style="list-style-type: none"> Parasite undergoes morphological change to become flagellate Healthy human hosts get infection when an infective sandfly vector bites them

IMAGE SOURCE: [Kala-Azar: Oral Nano Medicine \(10pointer.com\)](https://www.10pointer.com)

- यह प्रोटोजोआ परजीवी लीशमैनिया के कारण होता है।
- यह लीशमैनियासिस नामक रोग समूह की तीन स्थितियों में से एक है।
- यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है।
- यह दुनिया में मलेरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा परजीवी हत्यारा है।
- यह रक्त-चूसने वाले कीट सैंड फ्लाई द्वारा प्रसारित एक जूनोटिक संक्रमण है, जो नम (आर्द्र) मिट्टी और रेत में पाया जाता है और पशुओं का करीबी होता है।
 - परजीवी एक संक्रमित मादा फेलोबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से मनुष्यों में फैलता है।
- इस प्रकार का लीशमैनियासिस आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है, आमतौर पर प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा।
- परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलोएन्डोथेलियल सिस्टम (reticuloendothelial system) को संक्रमित करता है और अस्थि मज्जा, प्लीहा और यकृत में बहुतायत में पाया जा सकता है।

लक्षण:-

- कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं।
- दूसरों के लिए, लक्षणों में बुखार, वजन घटना और प्लीहा या यकृत में सूजन शामिल हो सकते हैं।

इलाज:-

- परजीवियों को मारने के लिए दवा मौजूद है।
- यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए, तो गंभीर मामले आमतौर पर घातक होते हैं।
- जिन रोगियों का सही ढंग से इलाज किया जाता है और ठीक किया जाता है, उनमें से 20% तक पोस्ट-काला-अजार डर्मल लीशमैनियासिस (पीकेडीएल) नामक त्वचा की स्थिति विकसित होती है, जो उपचार के महीनों से वर्षों के भीतर सामने आती है।
- इन रोगियों में उनकी त्वचा के घावों में बड़ी मात्रा में परजीवी हो सकते हैं, जो उन्हें संचरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं।

अवश्य पढ़ें: मारबर्ग वायरल रोग का प्रकोप

कैल्शियम कार्बाइड

संदर्भ: हाल ही में, FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के खाद्य आयुक्तों से फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।

कैल्शियम कार्बाइड के बारे में:-



IMAGE SOURCE: [Calcium Carbide Market | Global Industry Report, 2031 \(transparencymarketresearch.com\)](https://www.transparencymarketresearch.com)

- कैल्शियम कार्बाइड, जिसे कैल्शियम एसिटाइलाइड या 'मसाला' भी कहा जाता है।
- यह आमतौर पर खनन और धातु उद्योगों के साथ-साथ एसिटिलीन गैस के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है।
- यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील यौगिक है और एसिटिलीन गैस छोड़ता है जिसका उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है।

उपयोग:-

- कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग एसिटिलीन के रूप में पॉलीविनाइल क्लोराइड के उत्पादन में किया जाता है, जो कैल्शियम कार्बाइड का व्युत्पन्न है और पीवीसी उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है।
- कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग एसिटिलीन और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के उत्पादन में भी किया जाता है।
- इसका उपयोग लोहे से सल्फर को हटाने में किया जा सकता है।
- हम इसका उपयोग कैल्शियम साइनामाइड के उत्पादन के लिए कर सकते हैं।
- इस यौगिक का उपयोग एथिलीन जैसे पकने वाले एजेंट के रूप में भी किया जा सकता है।
- इसका उपयोग कार्बाइड लैंप में किया जा सकता है।
- इसका उपयोग डीऑक्सीडाइज़र के रूप में भी किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह इस्पात निर्माण के दौरान ऑक्सीजन हटाने में मदद करता है।
- इसका उपयोग बांस की तोपों (bamboo cannons) और बिग-बैंग तोपों में भी किया जाता है।

सेहत को नुकसान :-

- इसका प्रयोग स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम साबित हो सकता है।
- फलों में 'मसाला' का प्रयोग अत्यधिक विषैला होता है।
- यह सांस की समस्याओं और त्वचा में जलन सहित स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कैंसर हो सकता है।

अवश्य पढ़े: विनाइल क्लोराइड

PSLV-C55 मिशन

खबरों में क्यों : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C55 (PSLV-C55) मिशन को सिंगापुर के TeLEOS-2 के साथ प्राथमिक उपग्रह और ल्यूमलाइट-4 को सह-यात्री उपग्रह के रूप में लॉन्च करने वाला है।

- PSLV-C55 मिशन में पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (पीओईएम) है, जहां लॉन्च वाहन के खर्च किए गए पीएस4 को गैर-पृथक पेलोड के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए एक कक्षीय मंच के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- यह तीसरी बार है जब PS4 का उपयोग उपग्रह के अलग होने के बाद प्रयोगों के लिए एक मंच के रूप में किया जाएगा।

TeLEOS-2 उपग्रह

प्राथमिक उपग्रह

- सिंगापुर सरकार के अंदर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं का समर्थन करना।
- एक सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) पेलोड वहन करता है।
- पूरे मौसम में दिन और रात कवरेज प्रदान करना, और 1m पूर्ण-ध्रुवीयमितीय रिजॉल्यूशन पर इमेजिंग करने में सक्षम हों।

	<p>ल्यूमलाइट-4 उपग्रह</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह एक सह-यात्री उपग्रह है। • एक उन्नत 12U उपग्रह उच्च-प्रदर्शन अंतरिक्ष-जनित वीएचएफ डाटा एक्सचेंज सिस्टम (वीडीईएस) के तकनीकी प्रदर्शन के लिए विकसित किया गया। • सिंगापुर की ई-नेविगेशन समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने और वैश्विक शिपिंग समुदाय को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। <p>ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> • पीएसएलवी को इसरो के 'वर्कहॉर्स' के रूप में जाना जाता है। • यह भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। • यह एक चार चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग किया जाता है और दूसरे और चौथे चरण में तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है। • यह पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल है जो लिक्विड स्टेज से लैस है।
<p>ब्लास्टोमाइकोसिस (Blastomycosis)</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, मिशिगन पेपर मिल में कवक ब्लास्टोमाइसेस ने 1 को मार डाला और 100 को संक्रमित कर दिया।</p> <p>ब्लास्टोमाइकोसिस के बारे में: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • ब्लास्टोमाइकोसिस एक संक्रमण है जो ब्लास्टोमाइसेस नामक कवक के कारण होता है। • कवक वातावरण में रहते हैं, विशेष रूप से नम मिट्टी में और सड़ने वाले पदार्थ जैसे लकड़ी और पत्तियों में। • संयुक्त राज्य अमेरिका में, कवक मुख्य रूप से मध्य-पश्चिमी, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी राज्यों में रहता है, विशेष रूप से ओहियो और मिसिसिपी नदी घाटियों, महान झीलों और सेंट लॉरेंस नदी के आसपास के क्षेत्रों में। • हवा से सूक्ष्म कवक बीजाणुओं में सांस लेने के बाद लोगों को ब्लास्टोमाइकोसिस हो सकता है। <p>हालांकि अधिकांश लोग जो सांस के माध्यम से बीजाणुओं में सांस लेते हैं वे बीमार नहीं पड़ते हैं, कुछ लोगों में बुखार और खांसी जैसे लक्षण विकसित होंगे, और यदि इसका उपचार न किया जाए तो संक्रमण कभी-कभी गंभीर हो सकता है।</p> <p>लक्षण: बुखार, खांसी, रात को पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या जोड़ों में दर्द, वजन कम होना, सीने में दर्द, थकान (अत्यधिक थकान), त्वचा में घाव; जैसे उभरे हुए छाले, छाले आदि।</p> <p>इलाज:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • इट्राकोनाजोल एक प्रकार की एंटीफंगल दवा है जो आमतौर पर हल्के से मध्यम ब्लास्टोमाइकोसिस के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। • अम्फोटेरिसिन बी की सिफारिश आमतौर पर फेफड़ों में गंभीर ब्लास्टोमाइकोसिस या शरीर के अन्य भागों में फैलने वाले संक्रमण के लिए की जाती है। • संक्रमण की गंभीरता और व्यक्ति की प्रतिरक्षा स्थिति के आधार पर, उपचार की अवधि छह महीने से लेकर एक वर्ष तक हो सकती है। <p>अवश्य पढ़ें: म्यूकोर्मिकोसिस</p>
<p>अमोघा-III</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, स्वदेशी एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल, अमोघा-III का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।</p> <p>अमोघा-III के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • अमोघा-III एक स्वदेशी मिसाइल है। • इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP) के तहत विकसित किया गया है। • इसमें आग लगाओ और भूल जाओ की क्षमता है। <ul style="list-style-type: none"> ○ आग और भूल जाने की क्षमता: इसका अर्थ है कि लॉन्च के बाद इसे बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। • मिसाइल में 200 से 2500 मीटर की रेंज के साथ डुअल-मोड इमेजिंग इंफ्रारेड (IIR) सीकर सिस्टम है। • यह एक अग्रानुक्रम वारहेड दिखाता है, जिसमें दो अलग-अलग विस्फोटक आवेश होते हैं जो अनुक्रम में विस्फोटित होते हैं। • पहला आवेश, जिसे अग्रगामी आवेश के रूप में जाना जाता है, लक्ष्य के कवच में प्रवेश करता है, जिससे एक छेद बन जाता है। • दूसरा आवेश या मुख्य आवेश तब भीतर विस्फोटित होता है, जिससे लक्ष्य को अधिकतम क्षति पहुंचती है। • मिसाइल की अनूठी विशेषताओं में से एक यह है कि इसमें ऊपर और सीधे हमले के दोनों तरीके हैं।

<p>GSAT-7B उपग्रह</p>	<p>अवश्य पढ़ें: हेलिना मिसाइल</p> <p>संदर्भ: हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने GSAT-7B उपग्रह के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के साथ 3,000 करोड़ रूपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।</p> <p>GSAT-7B उपग्रह के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह एक संचार उपग्रह है। • यह जीसैट-7 श्रृंखला का एक हिस्सा है। • यह पांच टन श्रेणी में पहली बार है जिसे इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया जाएगा। • जीसैट 7 श्रृंखला के उपग्रह रक्षा सेवाओं की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित उन्नत संचार उपग्रह हैं। • GSAT 7B मुख्य रूप से भारतीय सेना की संचार जरूरतों को पूरा करेगा। • यह एक भूस्थैतिक उपग्रह है। • यह भारतीय सेना की संचार क्षमता में काफी वृद्धि करेगा। <p>अवश्य पढ़ें: वनवेब उपग्रह</p>
<p>हीमोफीलिया</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 2023 मनाया गया।</p> <p>हीमोफीलिया के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। • इसका उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। • फ्रैंक श्राबेल के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। <ul style="list-style-type: none"> ○ फ्रैंक श्राबेल: वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया (WHF) के संस्थापक है। • हीमोफीलिया एक चिकित्सा स्थिति है, जो ज्यादातर विरासत में मिलती है। • इसमें रक्त के थक्का जमने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिससे मामूली चोट लगने पर भी गंभीर रक्तस्राव हो सकता है। • यह एक जीन में उत्परिवर्तन या परिवर्तन के कारण होता है, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्लॉटिंग कारक प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश प्रदान करता है। <ul style="list-style-type: none"> ○ यह परिवर्तन या उत्परिवर्तन क्लॉटिंग प्रोटीन को ठीक से या बिल्कुल भी काम करने से रोक सकता है। ○ ये जीन X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। • महिलाओं की तुलना में पुरुष हीमोफीलिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। • यह काफी दुर्लभ बीमारी है, लगभग 10,000 में से 1 व्यक्ति इसके साथ पैदा होता है। <p>प्रकार:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • हीमोफीलिया A:- <ul style="list-style-type: none"> ○ यह हीमोफीलिया का सबसे आम प्रकार है जिसे हीमोफीलिया A कहा जाता है। ○ एक व्यक्ति के पास पर्याप्त क्लॉटिंग फैक्टर VIII (फैक्टर आठ) नहीं होता है। • हीमोफीलिया B:- <ul style="list-style-type: none"> ○ हीमोफीलिया B वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त कारक IX (कारक नौ) नहीं होता है। <p>लक्षण:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • बड़े घाव होना। • मांसपेशियों और जोड़ों में रक्तस्राव। • स्वतःस्फूर्त रक्तस्राव (बिना किसी स्पष्ट कारण के शरीर के अंदर अचानक रक्तस्राव होना)। • कट लगने, दांत निकालने या सर्जरी के बाद लंबे समय तक खून बहना। <p>इलाज:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • हीमोफीलिया का मुख्य इलाज रिप्लेसमेंट थेरेपी है। <p>रिप्लेसमेंट थेरेपी:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ क्लॉटिंग फैक्टर VIII (हीमोफीलिया ए के लिए) या क्लॉटिंग फैक्टर IX (हीमोफीलिया बी के लिए) के सांद्रण को धीरे-धीरे छोड़ा जाता है या नस में इंजेक्ट किया जाता है।

	<p>○ ये अंतःक्षेपण (infusions) क्लॉटिंग कारक को बदलने में मदद करते हैं जो गायब या कम है।</p> <p>अवश्य पढ़ें: मानव जीनोम परियोजना</p>
<p>लॉकबिट रैंसमवेयर</p>	<p>संदर्भ : हाल ही में, लॉकबिट रैंसमवेयर को Apple उपकरणों को लक्षित करते हुए पाया गया था।</p> <p>लॉकबिट रैंसमवेयर के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह पहली बार सितंबर 2019 में रिपोर्ट किया गया था और पीड़ितों की फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट करते समय उपयोग किए जाने वाले फ़ाइल एक्सटेंशन के कारण "abcd" वायरस करार दिया गया था। • लॉकबिट रैंसमवेयर पीड़ितों के सिस्टम में घुसपैठ करने और महत्वपूर्ण फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। • पीड़ित के डिवाइस पर फाइलों को डिक्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टोकॉर्सेसी में भुगतान के अनुरोध के कारण वायरस को "क्रिप्टोवायरस" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। • अतीत में, अमेरिका, चीन, भारत, यूक्रेन और इंडोनेशिया में उद्यमों और संगठनों को लक्षित करने के लिए लॉकबिट रैंसमवेयर का उपयोग किया गया है। • फ्रांस, जर्मनी और यू.के. सहित पूरे यूरोप में भी हमले दर्ज किए गए हैं। <p>कार्यरत:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह एक स्व-प्रसारित मैलवेयर के रूप में काम करता है, एक बार एक संगठनात्मक इंटरनेट तक पहुंच के साथ एक डिवाइस में सफलतापूर्वक घुसपैठ करने के बाद अतिरिक्त निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती है। • यह निष्पादन योग्य एन्क्रिप्शन फ़ाइलों को पीएनजी प्रारूप में छिपाने के लिए भी जाना जाता है, जिससे सिस्टम सुरक्षा द्वारा पता लगाने से बचा जा सकता है। • एक बार पहुंच प्राप्त करने के बाद, रैंसमवेयर सिस्टम को अपने एन्क्रिप्शन पेलोड को अधिक से अधिक डिवाइसों पर जारी करने के लिए तैयार करता है। • इसके बाद यह सुरक्षा कार्यक्रमों और अन्य बुनियादी ढांचे को निष्क्रिय कर देता है जो सिस्टम डेटा रिकवरी की अनुमति दे सकता है। • लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लॉकबिट गैंग की सहायता के बिना डेटा रिकवरी असंभव है। • एक बार यह सुनिश्चित हो जाने के बाद, रैंसमवेयर सभी सिस्टम फ़ाइलों पर एक एन्क्रिप्शन लॉक लगा देता है, जिसे केवल LockBit गैंग द्वारा बनाई गई कस्टम कुंजी के माध्यम से अनलॉक किया जा सकता है। • सिस्टम को पुनर्स्थापित करने के निर्देशों के साथ प्रक्रिया एक फिरौती के नोट को पीछे छोड़ देती है, और इसमें कथित तौर पर धमकी भरे ब्लैकमेल संदेश भी शामिल हैं। • पीड़ितों के पास लॉकबिट गैंग से संपर्क करने और डेटा के लिए भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा होता है। <p>अवश्य पढ़ें: भारत का साइबर इन्फ्रास्ट्रक्चर</p>
<p>डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, वैज्ञानिक समुदाय ने कक्षा 10वीं की सीबीएसई पाठ्यपुस्तकों से डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत को हटाने के एनसीईआरटी के फैसले के खिलाफ चिंता व्यक्त की।</p> <p>डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • विकासवाद के सिद्धांत की स्थापना में अपने योगदान के कारण चार्ल्स डार्विन को विकासवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। • डार्विन ने विकास की अपनी अवधारणा को अपनी पुस्तक "द ओरिजिन ऑफ़ स्पीशीज़" में प्रकाशित किया। <p>प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर डार्विन के विचार:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रजातियां समय के साथ बदलती या विकसित होती रहती हैं। • जैसे-जैसे पर्यावरण बदलता है, जीवों की आवश्यकताएं भी बदलती हैं और उन्हें अपने नए वातावरण के अनुकूल होने की आवश्यकता होती है। • प्राकृतिक आवश्यकताओं के अनुसार, समय की अवधि में परिवर्तन की घटना को अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। • डार्विन के सिद्धांत के अनुसार, केवल उच्च परिवर्तन स्वाभाविक रूप से चुने जाते हैं और निचले वाले स्वचालित रूप से समाप्त हो जाते हैं।

- यह प्रगतिशील विकास की ओर ले जाता है और सभी अनुकूलन योगदान करने में सक्षम नहीं होते हैं।
- डार्विन के अनुसार सभी जीवों का एक ही पूर्वज था और तब से यह अलग-अलग होता रहा।
- चार्ल्स डार्विन के अनुसार, विकास एक क्रमिक और धीमी प्रक्रिया है।
- **डार्विनवाद में पाँच सिद्धांत शामिल हैं जो हैं:**
- **अति-उत्पादन या अति-उत्पादन की विलक्षणता:** प्रत्येक पीढ़ी में कई और व्यक्ति पैदा होते हैं जो जीवित रहने और प्रजनन करने में सक्षम होंगे।
- **भिन्नता और आनुवंशिकता:** एक ही प्रजाति के व्यक्तियों में प्राकृतिक भिन्नता होती है। कई अनुकूल अनुकूलन वंशानुगत होते हैं और भविष्य की पीढ़ियों की संतानों को पारित किए जाते हैं।
- **अस्तित्व के लिए संघर्ष:** जैविक प्राणी एक ज्यामितीय अनुपात से बढ़ते हैं, जबकि खाद्य उत्पादन केवल एक अंकगणितीय अनुपात में बढ़ता है जैसे कि बहुत कम समय में, एक क्षेत्र किसी एक प्रजाति के साथ अधिक हो जाता है जब तक कि वृद्धि को रोकने के लिए कुछ नहीं होता। अस्तित्व के लिए यह संघर्ष तीन प्रकार का है जैसा कि नीचे दिया गया है:-
 - **अंतःजातीय संघर्ष:** एक ही प्रजाति के व्यष्टियों के बीच अंतःजातीय संघर्ष पाया जाता है।
 - **अन्तर्जातीय संघर्ष :-** यह एक साथ रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के जीवों में पाया जाता है।
 - **पर्यावरण के साथ संघर्ष:** जीवित जीव प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे बाढ़, शीत लहर, गर्मी की लहर और भूकंप आदि से संघर्ष करते हैं।
- **योग्यतम या प्राकृतिक चयन की उत्तरजीविता:** कुछ विशेषताओं वाले व्यक्तियों के पास कम अनुकूल विशेषताओं वाले अन्य लोगों की तुलना में जीवित रहने और प्रजनन करने का बेहतर मौका होता है।
- **प्रजातियों का संशोधन:** अतीत में होने वाली योगात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रजातियों का धीरे-धीरे संशोधन भूवैज्ञानिक समय की लंबी अवधि में उसी तरह से हो सकता है जैसे वे वर्तमान में हो रहे हैं।

अवश्य पढ़ें: सिंथेटिक बायोलॉजी

पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन (आरएलवी लेक्स)

संदर्भ: हाल ही में, ISRO ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसके बारे में:-

- RLV-LEX में एक मानवरहित, पंख वाले प्रोटोटाइप को एक हेलीकॉप्टर पर लगभग 2.3 किमी से 2.4 किमी की ऊंचाई तक ले जाना और उसे जमीन पर छोड़ना शामिल है।
- इसे स्वचालित रूप से दूरी तय करनी चाहिए, वेग प्राप्त करना चाहिए, नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और किसी सामान्य विमान की तरह आना चाहिए, पहले पीछे के पहियों से नीचे छूना चाहिए।
- प्रयोगात्मक उड़ानों की श्रृंखला में पहला हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग (HEX) है।
- इसके बाद लैंडिंग एक्सपेरिमेंट (LEX), रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट (REX) और स्क्रेमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट (SPEX) किया गया।
- पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रणाली एक प्रक्षेपण प्रणाली है जो कुछ या सभी घटक चरणों के पुनः उपयोग की अनुमति देती है।
 - यान एक मिशन के बाद यथावत पृथ्वी पर लौट आता है।

आरएलवी के लाभ:-

- अंतरिक्ष तक सस्ती पहुंच एक आरएलवी को आकर्षक बनाती है।

आरएलवी की चुनौतियां:-

- पुनः प्रयोज्य चरणों का वजन समतुल्य व्यय योग्य चरणों से अधिक होता है।
- लॉन्चर के लैंड करने के बाद, इसे अपनी अगली उड़ान के लिए तैयार करने के लिए इसके नवीनीकरण की आवश्यकता हो सकती है।
 - यह प्रक्रिया लंबी और महंगी हो सकती है।

अवश्य पढ़ें: नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV)

सोडियम साइनाइड

संदर्भ: हाल ही में, भारत ने चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से जहरीले रासायनिक सोडियम साइनाइड के आयात की एंटी-डॉपिंग जांच शुरू की है।

सोडियम साइनाइड के बारे में:-

	<ul style="list-style-type: none"> • यह सोडियम साल्ट सफेद रंग का होता है और पानी में घुलनशील होता है। • यह अत्यधिक विषैले लवणों में से एक है क्योंकि इसमें धातुओं के लिए उच्च आत्मीयता (अत्यधिक प्रतिक्रियाशील) है। • सोडियम साइनाइड भी एक मामूली मजबूत आधार होता है, और जब इसे एसिड (जैसे सल्फ्यूरिक एसिड) के साथ उपचारित किया जाता है। • यह हाइड्रोजन साइनाइड के रूप में जानी जाने वाली अत्यधिक जहरीली गैस बनाता है। <p>सोडियम सायनाइड के उपयोग :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • सोने का खनन: खनन उद्योग में सोडियम साइनाइड का अत्यधिक उपयोग होता है। • रासायनिक फीडस्टॉक: सोडियम साइनाइड कई व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों जैसे सायनोजेन क्लोराइड, कई प्रकार के नाइट्राइल और सायन्यूरिक क्लोराइड (cyanogen chloride) के उत्पादन में मदद करता है। • फार्मास्युटिकल उद्योग: नाइट्राइल कई रसायनों में मौजूद होते हैं जिनका उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। <p>अन्य उद्योग:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ इसका उपयोग धातुओं की सफाई के लिए किया जाता है। ○ डाई उद्योग में, रंगों का उत्पादन करने के लिए रसायन का उपयोग किया जाता है। ○ इस रसायन का उपयोग हाइड्रोसेनिक एसिड के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। ○ कई अन्य क्षेत्रों में, विद्युत लेपन समाधान के निर्माण के लिए रसायन का उपयोग किया जाता है। ○ इसका उपयोग एक कृषि रसायन के रूप में भी किया जाता है और किसान इसे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मारने के लिए कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। <p>अवश्य पढ़ें: भारतीय रासायनिक उद्योग की कमियां: TIFAC और एंटी-डॉपिंग ड्यूटी</p>
<p>मैग्नेटोरेसिस्टेंस</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, यूके में शोधकर्ताओं ने पाया है कि ग्राफीन कमरे के तापमान पर एक विषम विशाल मैग्नेटोरेसिस्टेंस (जीएमआर) प्रदर्शित करता है।</p> <p>इसके बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • मैग्नेटोरेसिस्टेंस एक घटना है जहां एक कंडक्टर का विद्युत प्रतिरोध आसन्न सामग्रियों में चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। • जब सामग्री को एक ही दिशा में चुंबकित किया जाता है, तो कंडक्टर में विद्युत प्रतिरोध कम होता है। • जब दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। • ग्रेफीन-आधारित डिवाइस में देखा गया मैग्नेटोरेसिस्टेंस "इस चुंबकीय क्षेत्र रेंज में अन्य ज्ञात सेमीमेटल्स की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक पाया गया।" <p>उपयोग:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • इसका उपयोग कंप्यूटर, बायोसेंसर, ऑटोमोटिव सेंसर, माइक्रोइलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और मेडिकल इमेजर्स में हार्ड डिस्क ड्राइव और मैग्नेटोरेसिस्टिव रैम में किया जाता है। • जीएमआर-आधारित उपकरणों का विशेष रूप से चुंबकीय क्षेत्रों को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। <p>अवश्य पढ़ें: सिंथेटिक बायोलॉजी</p>
<p>हार्पून मिसाइल</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी क्योंकि ताइवान 400 हार्पून मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है।</p> <p>हार्पून मिसाइल के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • हार्पून मिसाइलें टॉरपीडो लाइटवेट मिसाइलें और हारपून हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें हैं। • हार्पून अमेरिका द्वारा डिजाइन की गई सबसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। • यह 1977 से सेवा में उपलब्ध है। • इसकी स्थापना के बाद से कई रूपों का उत्पादन किया गया है, जिनमें वायु-, जहाज- और उप-लॉन्च किए गए संस्करण शामिल हैं। <p>मुख्य विशेषताएं:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • पेलोड: 224 कि.ग्रा • प्रणोदन: टर्बोजेट, ठोस प्रणोदक

	<ul style="list-style-type: none"> • रेंज: 90 - 240 कि.मी • स्पीड: 0.85 मैक (हाई सबसोनिक), 291.55 मी/से • संचालक देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चिली, डेनमार्क, मिस्र, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, भारत, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, पाकिस्तान, पोलैंड, पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और वेनेजुएला। <p>अवश्य पढ़ें: वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल</p>
<p>ओल्किलुओटो 3 रिएक्टर</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर, ओल्किलुओटो 3 रिएक्टर ने फिनलैंड में अपना परीक्षण चरण पूरा कर लिया है।</p> <p>ओल्किलुओटो 3 रिएक्टर के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • ओल्किलुओटो 3 रिएक्टर एक ईपीआर (यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर) है। • यह यूरोप में ऑनलाइन होने वाला पहला नई पीढ़ी का ईपीआर या यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर प्लांट है। • यह फिनलैंड में स्थित है। • यह फ्रांस के नेतृत्व वाले अरेवा-सीमेंस कंसोर्टियम द्वारा बनाया गया है। • यह यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर है। • इसकी क्षमता 1,600 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। • ओल्किलुओटो 3 का निर्माण 2005 में शुरू हुआ था। • यह फिनलैंड की बिजली की मांग का लगभग 14% कवर करता है। • ओल्किलुओटो-3 15 से अधिक वर्षों में पश्चिमी यूरोप का पहला नया रिएक्टर है। • यह फिनलैंड को अपने कार्बन तटस्थता लक्ष्यों को प्राप्त करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा। <p>अवश्य पढ़ें: भारत की परमाणु ऊर्जा</p>
<p>ज्यूपिटर आइसी मूनस एक्सप्लोरर (जूस)</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्यूपिटर आइसी मूनस एक्सप्लोरर (जूस) लॉन्च किया।</p> <p>ज्यूपिटर आइसी मूनस एक्सप्लोरर (जूस) के बारे में:-</p> <div data-bbox="331 1290 884 1688" data-label="Image"> </div> <p>IMAGE SOURCE: Future Planetary Exploration: Good News Times Three! (futureplanets.blogspot.com)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESA द्वारा प्रदान किए गए मापदंडों के आधार पर JUICE का निर्माण एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के नेतृत्व में एक औद्योगिक संघ द्वारा किया गया है। • मिशन के 2031 में बृहस्पति तक पहुंचने की योजना है। • केवल दो अन्य अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति का परीक्षण किया है:- <ul style="list-style-type: none"> ○ गैलिलियो परीक्षण: जिसने 1995 और 2003 के बीच गैस विशाल की परिक्रमा की, और जूनो, जो 2016 से ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। ○ नासा का यूरोपा क्लिपर: अक्टूबर 2023 में लॉन्च होने वाला है और जब जूस ग्रह पर पहुंचेगा तो यह पहले से ही बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा होगा।

- यूरोपा क्लिपर का उद्देश्य यूरोपा चंद्रमा का अध्ययन करना है।

जूस (JUICE) का लक्ष्य:-

- यह वैज्ञानिकों को बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं की उत्पत्ति, इतिहास और विकास को समझने में मदद करेगा।
- मिशन से पता चलेगा कि अन्य तारों के आसपास बृहस्पति जैसी प्रणालियों में संभवतः रहने योग्य वातावरण कैसे उत्पन्न हो सकता है।
- जूस बृहस्पति के केमिस्ट्री, संरचना, गतिकी, मौसम और जलवायु और इसके निरंतर बदलते वातावरण का विश्लेषण करेगा।

अवश्य पढ़ें: नासा का लुसी मिशन

भारत का पहला 3डी-मुद्रित डाकघर

संदर्भ: हाल की घोषणाओं के अनुसार, बेंगलुरु में जल्द ही 3डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके भारत का पहला डाकघर बनाया जाएगा।

भारत के पहले 3डी-प्रिंटेड डाकघर के बारे में:-

- भारत का पहला 3डी-प्रिंटेड डाकघर उल्सूर, बंगलौर में केंब्रिज लेआउट में स्थित होगा।
- यह परियोजना लार्सन एंड टुब्रो द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसके पास 3डी-प्रिंटेड डाकघर भवनों के निर्माण का अनुभव है।

3डी प्रिंटिंग के बारे में:-

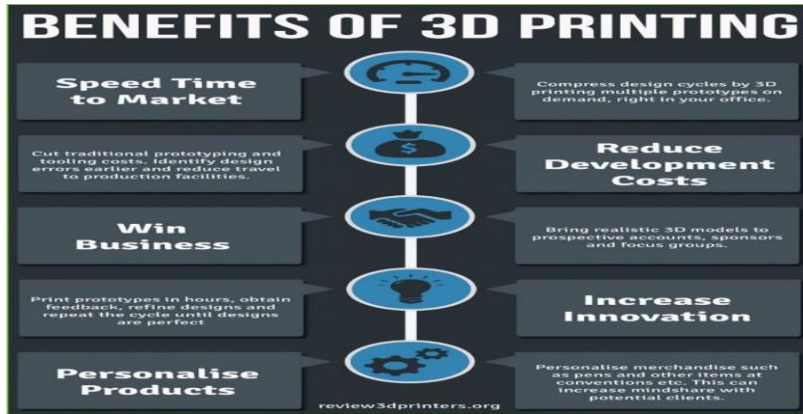


IMAGE SOURCE: [Benefits of 3d printers | Visual.ly](https://www.visual.ly)

- 3डी प्रिंटिंग एक डिजिटल फाइल से त्रि-आयामी ठोस वस्तु बनाने की एक प्रक्रिया है।
- यह योगात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है।
 - एक योगात्मक प्रक्रिया में, वस्तु के बनने तक सामग्री की लगातार परतों को बिछाकर एक वस्तु बनाई जाती है।
 - इनमें से प्रत्येक परत को वस्तु के पतले कटे हुए अनुप्रस्थ काट के रूप में देखा जा सकता है।
- 3डी प्रिंटिंग आपको पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में कम सामग्री का उपयोग करके जटिल आकार बनाने में सक्षम बनाती है।

अवश्य पढ़ें: 3डी प्रिंटिंग

विस्तारित रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ER-ASR)

संदर्भ: हाल ही में, विस्तारित रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ER-ASR) का पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

विस्तारित रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट के बारे में:-

- ईआर-एसआर को पुणे स्थित आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (एआरडीई) और डीआरडीओ की उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एचईएमआरएल) द्वारा डिजाइन किया गया था।
- इसे विशिष्ट गहराई पर पनडुब्बियों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसकी रॉकेट प्रणाली को पनडुब्बी रोधी अभियानों में तैनात किया जाएगा।
 - इसे विभिन्न भारतीय नौसैनिक जहाजों पर लगे एक स्वदेशी रॉकेट लांचर से दागा जाएगा।
- सामरिक मिशन आवश्यकताओं के आधार पर ईआर-एसआर को एकल या सैल्वो मोड में दागा जा सकता है।
- जहाज से पहला सफल परीक्षण पनडुब्बी रोधी युद्ध में भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने और रक्षा में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने की दिशा में एक कदम है।
- ईआर-एसआर को मौजूदा रूसी मूल के रॉकेट गाइडेड बम (आरजीबी) को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है।

	<p>जो पहले से ही जहाजों में लगे हुए हैं</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ RGB की रेंज पांच किलोमीटर है, जबकि ER-ASR आठ किलोमीटर से अधिक की रेंज हासिल कर सकता है। <p>अवश्य पढ़ें: पिनाका और स्मर्च रॉकेट सिस्टम</p>
<p>टेम्पो यानी ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, स्पेसएक्स ने नासा का टेम्पो वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण लॉन्च किया।</p> <p>क्षोभमंडलीय उत्सर्जन के बारे में: प्रदूषण की निगरानी (टेम्पो) उपकरण:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रदूषण की क्षोभमंडलीय उत्सर्जन निगरानी (टेम्पो) उपकरण उत्तरी अमेरिका में प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी करेगा। ● यह भूस्थैतिक कक्षा में होगा। <ul style="list-style-type: none"> ○ भूस्थैतिक कक्षा: भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊपर, जहाँ परिक्रमा करने वाला उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन से मेल खाएगा। ● इसे नासा द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ● टेम्पो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवलोकन करेगा, जिसमें ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फॉर्मलडिहाइड स्तर शामिल हैं। ● यह Intelsat 40E उपग्रह पर एक पेलोड है। <p>अनुप्रयोग:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● विभिन्न प्रदूषकों के स्तरों को मापना ● वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रदान करना ● उत्सर्जन-नियंत्रण रणनीतियों के विकास में मदद करना <p>महत्व:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● टेम्पो डेटा का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिक भीड़ के घंटे के प्रदूषण, बेहतर वायु गुणवत्ता अलर्ट की संभावना, ओजोन परत पर बिजली के प्रभाव, जंगल की आग और ज्वालामुखियों से प्रदूषण की गति और यहां तक कि उर्वरक आवेदन के प्रभावों का अध्ययन करने में सक्षम होंगे। ● टेम्पो दक्षिण कोरिया के जियोस्टेशनरी एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग स्पेक्ट्रोमीटर और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सेंटिनल-4 उपग्रह से जुड़कर एक वायु गुणवत्ता निगरानी उपग्रह समूह बन जाएगा जो उत्तरी गोलार्ध में प्रदूषण को ट्रैक करेगा। ● यह पहला अंतरिक्ष-आधारित उपकरण होगा जो कई वर्ग मील के रिजॉल्यूशन के साथ दिन के समय उत्तरी अमेरिका में हवा की गुणवत्ता को मापने में सक्षम है। <ul style="list-style-type: none"> ○ वर्तमान सीमा लगभग 100 वर्ग मील या लगभग 258 वर्ग किलोमीटर है। <p>अवश्य पढ़ें: NavIC</p>



रक्षा



SLINEX-23

संदर्भ: हाल ही में, IN-SLN द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX-23 का 10वां संस्करण कोलंबो में होने वाला है।
स्लिनैक्स-23 के बारे में:-

- यह भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
- यह अभ्यास का 10वां संस्करण है।
- यह कोलंबो, श्रीलंका में होने वाला है।
- भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस किल्टन द्वारा किया जा रहा है।
 - आईएनएस किल्टन (INS Kiltan): यह एक स्वदेशी कर्मोटा श्रेणी का एसडब्ल्यू कार्वेट (ASW Corvette) है और
 - आईएनएस सावित्री (INS Savitri): एक अपतटीय गश्ती पोत है।
- श्रीलंका नौसेना का प्रतिनिधित्व एसएलएनएस गजबाहु (SLNS Gajabahu) और एसएलएनएस सागर (SLNS Sagara) द्वारा किया जाता है।

अवश्य पढ़ें: भारत-श्रीलंका संबंध



विविध



डेडनेमिंग

संदर्भ: हाल ही में, ट्विटर ने डेडनेमिंग के विरुद्ध सुरक्षा हटा दी।
डेडनेमिंग के बारे में:-

- एक डेडनाम अनिवार्य रूप से वह नाम है जिसे एक ट्रांस, नॉन-बाइनरी और/या जेंडर-एक्सपेंसिव व्यक्ति को एक अधिक आत्म-पुष्टि नाम अपनाने से पहले बुलाया गया था।
- किसी ट्रांस, नॉन-बाइनरी, और/या जेंडर-एक्सपेंसिव व्यक्ति को डेडनेम से कॉल करने की क्रिया, जानबूझकर या नहीं, डेडनेमिंग के रूप में जानी जाती है, जिसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।
- डेडनेमिंग हानिकारक है क्योंकि किसी व्यक्ति के चुने हुए नाम या सर्वनाम का उपयोग करने से इनकार करना ट्रांसफ़ोबिया या सिसेक्सिज़्म का एक रूप है।
- सिसेक्सिज़्म मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में योगदान कर सकता है, जैसे कि अवसाद और आत्महत्या।
- इससे शारीरिक और मौखिक हमला (verbal assault) और दुर्यवहार भी हो सकता है।
- इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को परेशान किया जा सकता है, उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है या उस पर हमला किया जा सकता है।
- डेडनामिंग न केवल किसी की असली पहचान को अमान्य कर देता है बल्कि जन्म के समय उन्हें सौंपे गए लिंग के बारे में जानकारी भी प्रकट कर सकता है जो संबंधित व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी को पता चले।

अवश्य पढ़ें: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

डिजास्टर
रेजिलिएंट
इन्फ्रास्ट्रक्चर 2023
पर अंतर्राष्ट्रीय
सम्मेलन

संदर्भ: हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदाओं के लिए एक एकीकृत प्रतिक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित किया।
डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में:-

- यह गठबंधन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (CDRI) और उसके भागीदारों का वार्षिक सम्मेलन है।
- आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है।
- डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन (CDRI):-
 - यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र) एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और

	<p>वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र और ज्ञान संस्थानों की एक बहु-हितधारक वैश्विक साझेदारी है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ वर्ष 2019 में भारत के प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान सीडीआरआई का शुभारंभ किया। ○ इसका उद्देश्य सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है। ○ सदस्य: 30 देश और 8 संगठन है। ○ CDRI सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। <ul style="list-style-type: none"> ● ICDRI 2023 इन समाधानों को तैयार करने और लचीले बुनियादी ढांचे को आकार देने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ● इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए जोखिम-सूचित प्रणाली, लचीली बुनियादी ढांचा संपत्ति और अभिनव वित्तपोषण बनाने की प्रथाओं में तल्लीन करना है। <p>विषयगत फोकस: -</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्तंभ 1: लचीली अवसंरचना प्रदान करना <ul style="list-style-type: none"> ○ समावेशी और जोखिम-सूचित प्रणालियाँ ● स्तंभ 2: लचीली अवसंरचना प्रदान करना <ul style="list-style-type: none"> ○ लचीली अवसंरचना संपत्तियों के माध्यम से विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करना ● स्तंभ 3: लचीली अवसंरचना प्रदान करना <ul style="list-style-type: none"> ○ इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस के लिए वित्त और निवेश को साकार करना <p>अवश्य पढ़ें: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)</p>
<p>सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार</p>	<p>संदर्भ: हाल ही में, भारतीय-अमेरिकी सांख्यिकीविद् कैलियामपुडी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।</p> <p>सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● यह वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। ● यह हर दो साल में एक बार किसी व्यक्ति या समूह को दिया जाता है। ● यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण में सुधार के लिए सांख्यिकी का उपयोग करने वाली महत्वपूर्ण सफलताओं के लिए सम्मानित किया जाता है। ● यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, फील्ड मेडल और ट्यूरिंग पुरस्कार के बाद तैयार किया गया है। ● इसमें \$80,000 का मौद्रिक पुरस्कार है। ● सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और COPSS अध्यक्षों का पुरस्कार सांख्यिकी में दो शीर्ष सम्मान हैं। <p>अवश्य पढ़ें: Porter prize</p>

IAS BABA



★ **Most Trusted** ★

Integrated Learning Program (ILP) – 2024

The Most Comprehensive Self-Study Program

**VAN (Comprehensive
Notes for entire UPSC Syllabus)**



ADMISSION OPEN

Scan Here



to Know More

MAINS



राजव्यवस्था और शासन



भारत में न्यायिक पेंडेंसी

संदर्भ: IJR के अनुसार, दिसंबर 2022 तक, उच्च न्यायालय 1,108 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में केवल 778 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहे थे, जिससे न्यायपालिका में मामलों की बड़ी संख्या लंबित थी।

भारतीय न्यायपालिका में पेंडेंसी से संबंधित आंकड़े:

Court	Pendency in 2019	Pendency in 2020	Pendency in 2021	Pendency in 2022
Supreme Court	59,535 (as on December 2019)	64,426 (as on December 2020)	69,855 (as on December 2021)	70,154 (as on March 2022)
High Courts	46,84,354 (as on December 2019)	56,42,567 (as on December 2020)	56,49,068 (as on December 2021)	58,90,726 (as on March 2022)
District & Subordinate Courts	3,22,96,224 (as on December 2019)	3,66,39,436 (as on December 2020)	4,05,79,062 (as on December 2020)	4,09,85,490 (as on March 2022)

Source: National Judicial Data Grid

न्यायिक पेंडेंसी के कारण:

- सरकार - सबसे बड़ी वादी: केंद्र और राज्य सरकारें 46% लंबित मामलों में पक्षकार हैं।
 - इस प्रकार, एक साधारण नकारात्मक सूची जो उन उदाहरणों की पहचान करती है जिनमें सरकार और उसकी एजेंसियों को अदालत में जाने से रोक दिया जाता है, व्यर्थ मुकदमेबाजी से बचने में सहायक होगी।
- न्यायाधीशों की संख्या:** 2021 तक, भारत में प्रति मिलियन लोगों पर 21.03 न्यायाधीश थे, जबकि ब्रिटेन में 51 और अमेरिका में प्रति मिलियन 107 न्यायाधीश थे। इसलिए भारत को शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है।
 - भारत के 120वें विधि आयोग की रिपोर्ट में न्यायाधीश शक्ति निर्धारण सूत्र का सुझाव दिया गया है।
 - भारत को अपने सबसे अनुभवी न्यायाधीशों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 62 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 65, यूके या कनाडा में 75 की तुलना में) निर्धारित की गई थी जब जीवन प्रत्याशा कम थी।
- न्यायिक नियुक्तियां:** न्यायिक नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच चल रहे विवाद को युद्ध स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए।
 - अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले न्यायाधीशों की कॉलेजियम प्रणाली को एक अधिक व्यवहार्य योजना से बदला जाना चाहिए।
 - अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का संविधान भी भारत को एक बेहतर न्यायिक प्रणाली स्थापित करने में मदद कर सकता है।
- प्रशासनिक बोझ:** विकसित देशों के विपरीत जहां अदालतों के प्रशासनिक कार्यों को एक बाहरी एजेंसी द्वारा समर्थित किया जाता है, भारतीय न्यायाधीश अधिकांश समय सुनवाई निर्धारित करने, प्रवेश तय करने आदि में खर्च करते हैं।
 - भारत प्रशासनिक विशेषज्ञता, विशेषज्ञता और आधुनिक प्रबंधन प्रथाओं तथा प्रौद्योगिकियों के साथ एक अलग पेशेवर एजेंसी के साथ इसका अनुकरण कर सकता है।
 - केंद्र सरकार ने इंडियन कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज (ICTS) का सुझाव दिया था - अदालतों की प्रशासनिक आवश्यकताओं की देखरेख और उन्हें पूरा करने वाला एक प्राधिकरण है।
- तुच्छ मुकदमेबाजी:** कुछ श्रेणियों के मामले जैसे चेक का अनादरण या मकान मालिक-किराएदार के विवाद बहुत बड़े होते हैं और सिस्टम को रोकते हैं।
 - इस प्रकार, हारने वाली पार्टी पर अत्यधिक भारी लागत लगाकर ऐसे मुकदमों को हतोत्साहित करने के लिए नियम स्थापित किए जाने चाहिए।
 - इससे कई तुच्छ विवाद अदालत के बाहर सुलझा लिए जाएंगे।
- खराब न्यायिक ढांचा:** उदाहरण के लिए, कई अदालत परिसर किराए के परिसर से संचालित होते हैं।

- पूर्व CJI एन वी रमना ने टिप्पणी की है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे के मानकीकरण और सुधार के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम (NJIC) बनाया जाना चाहिए।
- **तकनीकी बाधाएं:** कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन सुनवाई के समान, कुछ श्रेणियों के मामलों को स्थायी रूप से एक ऑनलाइन निपटान प्रणाली में ले जाया जा सकता है।
 - कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग रोस्टर को प्रबंधित करने के लिए भी किया जा सकता है, इस प्रकार पूर्वाग्रह को समाप्त किया जा सकता है।
 - विचाराधीन कैदियों का मुद्दा: भारतीय जेलों में लगभग 76% कैदी अंडरट्रायल हैं, यानी चार में से तीन कैदी दोषी भी नहीं हैं।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकार को निर्देश दिया कि वह जमानत प्रदान करने को कारगर बनाने के लिए भारतीय जमानत अधिनियम की शुरुआत पर विचार करे, जैसा कि यूके जैसे विभिन्न अन्य देशों में किया गया है।
- **बार-बार स्थगन:** एक मानदंड बनाने की आवश्यकता है कि एक बार तारीख तय हो जाने के बाद कोई स्थगन तब तक संभव नहीं होना चाहिए जब तक कि अनुरोध करने वाला पक्ष पर्याप्त दंड के साथ दूसरे पक्ष की कानूनी लागत का भुगतान करने को तैयार न हो।
- **खराब प्रबंधन प्रथाएं:** अदालतों के लिए लंबी छुट्टियों की प्रणाली एक औपनिवेशिक प्रथा है जिसे आज अदालतों में उच्च लंबितता के कारण इष्टतम न्याय वितरण के लिए दूर किया जाना चाहिए।
 - पूर्व मुख्य न्यायाधीश लोढ़ा ने सिफारिश की है कि सभी न्यायाधीशों को एक बार में छुट्टी पर जाने के बजाय, व्यक्तिगत न्यायाधीशों को वर्ष के दौरान अलग-अलग समय पर छुट्टी लेनी चाहिए।
 - यह सुनिश्चित करेगा कि अदालतें लगातार खुली रहें और मामलों की सुनवाई के लिए हमेशा बेंच मौजूद रहें।
- **विशेष अदालतों की कम संख्या:** विशेष क्षेत्रों पर विशेष अदालतें स्थापित की जा सकती हैं जैसे वाणिज्यिक मामलों को उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में स्थानांतरित किया जा सकता है।
 - इसी प्रकार, मुख्य अदालतों पर बोझ कम करने के लिए, भूमि, अपराध, यातायात चालान आदि से संबंधित मुकदमों को चिन्हित करने के लिए उच्च न्यायालयों के भीतर विशेष न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है।
- **कम बजटीय आवंटन:** न्यायपालिका को आवंटित बजट जीडीपी के 0.08 और 0.09 प्रतिशत के बीच है। केवल चार देशों- जापान, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और आइसलैंड- का बजट आवंटन कम है और उन्हें भारत की तरह पेंडेंसी की समस्या नहीं है।

सुझावात्मक उपाय:

- **न्यायाधीशों की शीघ्र नियुक्ति:** न्यायाधीशों की नियुक्ति न करके सरकार आम लोगों को न्याय से वंचित कर रही है। देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है।
 - न्यायाधीशों के कार्यभार को कम करने के लिए न्यायाधीश-से-जनसंख्या अनुपात में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है।
- **केंद्र सरकार द्वारा दिशानिर्देश:** केंद्र ने अदालतों के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने, फास्ट ट्रैक अदालतों और भारतीय न्यायालयों और न्यायाधिकरण सेवाओं (आईसीटी) की स्थापना जैसे उपायों का सुझाव दिया था ताकि अदालत प्रणाली की उत्पादकता बढ़ाई जा सके।
- **ई-प्लेटफॉर्म:** ई-प्लेटफॉर्म के उपयोग और अधिक अदालतों की स्थापना के माध्यम से न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार।
 - भारत ने ई-न्यायालय परियोजना का ई-कोर्ट राष्ट्रीय पोर्टल ecourts.gov.in लॉन्च किया है।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को मजबूत करना :** यह मध्यस्थता, और सुलह जैसे तरीकों का इस्तेमाल करता है।
 - यह एक तटस्थ तीसरे पक्ष का उपयोग करता है जो पक्षों को संवाद करने, मतभेदों पर चर्चा करने और विवाद को हल करने में मदद करता है।
 - यह नागरिक विवादों से संबंधित सभी प्रकार के मामलों को हल करने की पेशकश करता है, जैसा कि कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।
- **परामर्श:** विवादों को पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में परामर्श के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।
- **लोक अदालत:** लोक अदालतों (लोगों की अदालतें) जैसी स्वैच्छिक एजेंसियां भारतीय कानूनी प्रणाली की एक दिलचस्प विशेषता हैं।
 - यह वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है।

केशवानंद भारती केस के 50 साल

संदर्भ: केशवानंद भारती में मौलिक निर्णय, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति की सीमा पर "मूल संरचना" सिद्धांत निर्धारित किया, ने हाल ही में 50 वर्ष पूरे किए।

- केशवानंद भारती मामले, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने "मूल संरचना के सिद्धांत" को स्पष्ट किया।
- इस सिद्धांत के अनुसार, संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग भारतीय संविधान की मूल संरचना जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक स्वतंत्रता आदि को नष्ट करने के लिए नहीं कर सकती है।

- मूल संरचना सिद्धांत एक न्यायिक सिद्धांत है जो संविधान में संशोधन करने के लिए भारत की संसद की शक्ति को सीमित करता है।

इस मामले का महत्व:

- **संविधान की सर्वोच्चता स्थापित किया:** इसने संसद और कार्यपालिका पर संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की और संविधान की बुनियादी विशेषताओं को प्रभावित किए बिना संविधान में संशोधन करने की उनकी शक्ति को सीमित कर दिया।
- **संरक्षित मौलिक अधिकार:** इसने संविधान की लोकतांत्रिक और संघीय प्रकृति को संरक्षित किया और मनमाने या सत्तावादी संशोधनों से नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की।
- **न्यायिक समीक्षा:** इसने किसी भी संवैधानिक संशोधन की वैधता की जांच करने और मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करने पर इसे रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति पर बल दिया।
- **DPSPs पर मौलिक अधिकारों की प्रधानता:** इसने मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष को हल किया, और बाद वाले की तुलना में पूर्व को प्रधानता देकर उनमें सामंजस्य स्थापित किया।
- **"मूल संरचना सिद्धांत" को परिभाषित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति:** इसने बाद के निर्णयों का मार्ग प्रशस्त किया जिसने मूल संरचना सिद्धांत को विस्तारित और समृद्ध किया, जैसे कि मिनर्वा मिल्स मामले (1980), जिसने धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक स्वतंत्रता को बुनियादी विशेषताओं के रूप में जोड़ा, और इंदिरा गांधी केस (1975), जिसने 39वें संशोधन को अमान्य कर दिया, जिसमें प्रधान मंत्री के चुनाव को न्यायिक जांच से बचाने की मांग की गई थी।

आगे की राह :

मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान की आधारशिला है, जो लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के संरक्षण और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में सहायक रहा है। केशवानंद भारती मामले में इसकी स्थापना भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती और लचीलेपन तथा संविधान को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है।



अर्थव्यवस्था



UPI लेनदेन शुल्क में परिवर्तन: आपके वॉलेट पर प्रभाव

संदर्भ: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई) को इंटरऑपरेबल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनने की अनुमति दी है।

- एनपीसीआई ने हाल ही में 1 अप्रैल, 2023 से प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई) का उपयोग करके किए गए मर्चेट यूपीआई लेनदेन पर 1.1 प्रतिशत तक का इंटरचेंज शुल्क पेश किया है।

परिवर्तनों की मुख्य विशेषताएं:

प्रयोज्यता (Applicability):

- वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी पर एनपीसीआई के नए दिशानिर्देश वॉलेट उपयोग के लिए इंटरचेंज शुल्क स्थापित करते हैं, जिसका भुगतान पेटीएम, फोनपे और गूगल पे जैसे वॉलेट जारी करने वालों को किया जाएगा।
- इनमें यूपीआई-वॉलेट-लोडिंग के शुल्क भी शामिल हैं जिनका भुगतान वॉलेट जारीकर्ता द्वारा प्रेषक बैंकों या उन बैंक खातों को किया जाएगा जिनसे राशि डेबिट की जा रही है।

वॉलेट खिलाड़ियों के लिए लाभ:

- इंटर-ऑपरेबिलिटी मानदंड सभी यूपीआई क्यूआर कोड और उपकरणों में वॉलेट की सार्वभौमिक स्वीकृति को सक्षम करेंगे, इस प्रकार वॉलेट की प्रमुखता या प्रासंगिकता में वृद्धि होगी।
- यह वॉलेट जारीकर्ताओं और भुगतान प्लेटफार्मों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के मौजूदा अभ्यास के विपरीत वॉलेट भुगतानों पर इंटरचेंज शुल्क को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके एकरूपता और समानता सुनिश्चित करेगा।

इंटरचेंज फीस:

- इंटरचेंज दरें मर्चेट श्रेणी कोड के अनुसार 0.5 प्रतिशत से 1.1 प्रतिशत की सीमा में भिन्न होती हैं।
- ईंधन, शिक्षा, कृषि और उपयोगिता भुगतान जैसी श्रेणियां 0.5-0.7 प्रतिशत के निम्न इंटरचेंज को आकर्षित करती हैं; खाद्य दुकानों, विशेष खुदरा दुकानों और ठेकेदारों के सुविधा स्टोरों पर सबसे अधिक 1.1 प्रतिशत शुल्क लगता है।

वॉलेट लेनदेन:

- इंटरचेंज शुल्क का भुगतान व्यापारियों द्वारा वॉलेट या कार्ड जारीकर्ता को किया जाता है और आमतौर पर व्यापारियों द्वारा अब्सॉर्ब (absorbed) कर लिया जाता है।
- छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के प्रभावित होने की संभावना नहीं है क्योंकि यह केवल 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर लागू होता है।
- एमडीआर या मर्चेट डिस्काउंट रेट कुछ मामलों में वॉलेट-ऑन-यूपीआई पर लागू होता है और इस कदम से मर्चेट्स पर अधिक एमडीआर लगाया जा सकता है, जो भुगतान कंपनियों की क्षमता और इंटरचेंज पर पास करने की इच्छा पर निर्भर करता है।

ग्राहकों पर प्रभाव:

- मानदंडों से वॉलेट की अपील, गुंजाइश, भूमिका और उपयोगिता में वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि अब उनका उपयोग क्यूआर कोड और उपकरणों पर यूपीआई भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, जिससे ग्राहकों के लिए भुगतान विकल्प बढ़ सकते हैं।
- उपभोक्ता क्रेडिट या डेबिट कार्ड, BNPL (Buy Now Pay Later) और नेट बैंकिंग सहित कहीं से भी अपना वॉलेट लोड करने में सक्षम होंगे, इस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूपीआई लेनदेन के लिए किसी भी उपकरण का उपयोग करने के लिए एक तंत्र का निर्माण होगा।
- वर्तमान में, बैंक-टू-बैंक यूपीआई लेनदेन के लिए एमडीआर शून्य है।

प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट्स (पीपीआई) के बारे में:

- पीपीआई ऐसे उपकरण हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवाओं के संचालन, प्रेषण सुविधाओं को सक्षम करने आदि में संग्रहीत मूल्य के विरुद्ध सुविधा प्रदान करते हैं।
- प्रीपेड भुगतान साधनों के उदाहरणों में स्मार्ट कार्ड, ऑनलाइन खाते, ऑनलाइन वॉलेट, स्ट्राइप कार्ड, पेपर वाउचर आदि शामिल हैं।
- इन उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य पहले से प्रीपेड राशि तक पहुंच प्राप्त करना है।
 - इसलिए, कोई भी व्यक्ति नकद या कार्ड के भौतिक आदान-प्रदान के बिना आवश्यक सामान खरीद सकता है।

आगे की राह

भारत में डिजिटल भुगतान परिदृश्य बदल गया है और भारत डिजिटल संपत्ति के निर्माण में अग्रणी के रूप में उभरा है, जो कई अन्य देशों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम कर सकता है। भारत सरकार को भारत को दुनिया के सबसे कुशल भुगतान बाजारों में से एक का दर्जा दिलाने में मदद करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

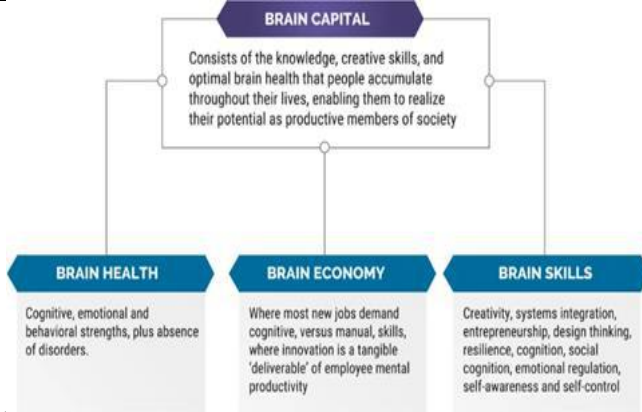
डिजिटल वॉलेट और UPI जैसे वैकल्पिक भुगतान विधियों का पता लगाने के लिए विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जो कम लेनदेन शुल्क प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर, डिजिटल लेन-देन के लाभ चुनौतियों से अधिक हैं, और जैसे-जैसे तकनीक का विकास जारी है, हम भुगतान परिदृश्य में और नवीनता देखने की उम्मीद कर सकते हैं।

ब्रेन इकोनॉमी

संदर्भ: हाल के दिनों में ब्रेन इकोनॉमी का उदय, यानी प्रौद्योगिकी संचालित ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, जो श्रम, पूंजी और कौशल को देखने के हमारे तरीके को बदल देगी।

इसके बारे में:

Source: <https://www.nature.com>



- ब्रेन इकोनॉमी एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को संदर्भित करती है जहां आर्थिक विकास का प्राथमिक स्रोत नवाचार और रचनात्मकता द्वारा संचालित होता है, और ज्ञान को प्रभावी ढंग से उत्पन्न करने, संसाधित करने और उपयोग करने की क्षमता होती है।

ब्रेन इकोनॉमी के लाभ

- **उच्च उत्पादकता:** प्रौद्योगिकी और स्वचालन में प्रगति के साथ, ब्रेन इकोनॉमी में उत्पादकता और दक्षता में काफी वृद्धि करने की क्षमता है।
- **जीवन की बेहतर गुणवत्ता:** मस्तिष्क-आधारित कार्य ऐसे रोजगार सृजित कर सकता है जो शारीरिक रूप से कम मांग वाले और बौद्धिक रूप से अधिक उत्तेजक हों।
 - इससे उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है जो ब्रेन इकोनॉमी में काम करते हैं।
- **बढ़ा हुआ नवाचार:** मस्तिष्क-आधारित कार्य प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित तेजी से नवाचार और निर्माण के बारे में है।
 - इससे नए उत्पाद, सेवाएं और प्रौद्योगिकियां उत्पन्न हो सकती हैं जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती हैं।
 - उदाहरण के लिए, अमेज़न के पास ब्रेन है जो नई पेशकशें बनाता है, कौशल से विशाल डेटा केंद्रों और निकायों को बनाए रखता है जो घरों में पैकेज वितरित करते हैं।
- **बढ़ा हुआ सहयोग:** ब्रेन इकोनॉमी को विभिन्न क्षेत्रों, विषयों और संस्कृतियों में सहयोग की आवश्यकता होती है।
 - इससे विविध पृष्ठभूमियों के लोगों के बीच सहयोग और समझ में वृद्धि हो सकती है।
- **सामाजिक प्रगति में निरंतरता:** गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी और मस्तिष्क शक्ति का उपयोग किया जा सकता है।
- **अधिक लचीलापन:** प्रौद्योगिकी के साथ, मस्तिष्क-आधारित कार्य कहीं से भी, किसी भी समय किया जा सकता है, यह श्रमिकों और व्यवसायों के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
- **सूचना तक आसान पहुंच:** प्रौद्योगिकी ने सूचना और ज्ञान तक पहुंच को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है, जो एक अधिक सूचित और शिक्षित समाज बनाने में मदद कर सकता है।
- **व्यक्तिगत विकास:** मस्तिष्क आधारित कार्य के लिए निरंतर सीखने और व्यक्तिगत विकास की आवश्यकता होती है, जिससे आत्म-जागरूकता, रचनात्मकता और अनुकूलन क्षमता में वृद्धि हो सकती है।

ब्रेन इकोनॉमी के लिए चुनौतियां:

- **असमानता:** ब्रेन इकोनॉमी में शरीर, कौशल और मस्तिष्क को घातांकी रूप से भिन्न मान निर्दिष्ट करके असमानता को बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए।
 - यह उन्नत प्रौद्योगिकी में शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच रखने वालों और न पाने वालों के बीच एक व्यापक अंतर पैदा कर सकता है।
- **नैतिक दुविधाएं:** जैसे-जैसे तकनीक विकसित होती जा रही है और ब्रेन इकोनॉमी में अधिक एकीकृत होती जा रही है, गोपनीयता, समावेशिता, निष्पक्षता और लैंगिक समानता और संपत्ति के बंटवारे जैसे सामाजिक मुद्दों पर प्रभाव के बारे में नैतिक दुविधाएं पैदा हो रही हैं।
- **विनियामक चुनौतियाँ:** ब्रेन इकोनॉमी में प्रौद्योगिकी विकास की तेज़-तरार प्रकृति नीति निर्माताओं और नियामकों के लिए विनियामक चुनौतियाँ खड़ी कर रही है।
 - तकनीकी विकास के साथ गति बनाए रखने के लिए अधिक चुस्त और उत्तरदायी नियामक ढांचे की आवश्यकता हो सकती है।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुंच:** ब्रेन इकोनॉमी में भाग लेने के लिए आवश्यक तकनीक तक हर किसी की पहुंच नहीं हो सकती है, जिससे

डिजिटल विभाजन होता है और असमानता और बढ़ जाती है।

- **जॉब का विस्थापन:** ब्रेन इकोनॉमी के उदय के परिणामस्वरूप उन नौकरियों का विस्थापन हो सकता है जिनके लिए शारीरिक श्रम या कौशल के निचले स्तर की आवश्यकता होती है, जिससे कुछ क्षेत्रों में नौकरी छूट जाती है।
 - इसके लिए अर्थव्यवस्था की नई मांगों के अनुकूल होने के लिए श्रमिकों के महत्वपूर्ण पुनर्प्रशिक्षण और कौशल विकास की भी आवश्यकता हो सकती है।
- **सामाजिक प्रभाव:** ब्रेन इकोनॉमी में प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाने से महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कार्य की प्रकृति, सामाजिक संबंधों और मानव व्यवहार में परिवर्तन।
 - इन प्रभावों की निगरानी करना और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण होगा।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** ब्रेन इकोनॉमी के विकास से ऊर्जा की खपत और पर्यावरणीय प्रभाव में वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी नई प्रौद्योगिकियां अधिक प्रचलित हो जाती हैं।
 - इन तकनीकों के पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करना और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण होगा।

आगे की राह :

खराब निगमों, पापपूर्ण लाभ और अमानवीय तकनीक की पुरानी रूढ़िवादिता को त्यागने की आवश्यकता है। मानव बनाम मशीन के मिथक को खत्म करने की जरूरत है।

प्रौद्योगिकी नौकरियों को नष्ट नहीं करती है, बल्कि यह नौकरियां पैदा करती है, लोगों को स्वतंत्र करती है और सामाजिक प्रगति को गति देती है। देश के शिक्षा ढांचे को बदलने की जरूरत है।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में छात्रों और शिक्षकों को प्रौद्योगिकी से लैस करने की आवश्यकता है। स्कूलों में प्रयोग और निर्माण में विफलताओं का सेलेब्रेट करना चाहिए।



अंतरराष्ट्रीय संबंध



विदेश व्यापार नीति 2023

संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री ने विदेश व्यापार नीति 2023 लॉन्च की है।

विदेश व्यापार नीति का मुख्य दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है:

- छूट के लिए प्रोत्साहन,
- सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन - निर्यातक, राज्य, जिले, भारतीय मिशन,
- व्यापार करने में आसानी, लेन-देन की लागत में कमी और ई-पहल और
- उभरते क्षेत्र - ई-कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना और स्कोमेट नीति को सुव्यवस्थित करना।

विदेश व्यापार नीति 2023 की मुख्य विशेषताएं

Policy overhauled

Key highlights from India's updated Foreign Trade Policy:



- It focuses on lowering costs for smaller firms and offering swifter clearances
- It aims at tripling exports to \$2 trillion by 2030 from \$760 billion in 2022-23
- Policy allows for adjustments based on world trade and industry feedback
- Export promotion initiatives include encouraging international trade settlement in Indian currency

Source: The Hindu

- नई नीति की कोई समाप्ति तिथि (समाप्ति तिथि) नहीं होगी और उभरते विश्व व्यापार परिदृश्य और उद्योग प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें बदलाव किया जाएगा। जबकि नीति ओपन-एंडेड होगी, इसके तहत स्वीकृत योजनाएं समयबद्ध होंगी।
- मौजूदा एडवांस ऑथराइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) योजनाओं के तहत वन टाइम एमनेस्टी (one-time amnesty) को छोड़कर कोई बड़ी नई योजना नहीं है, जो निर्दिष्ट निर्यात दायित्वों के अधीन पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देती है।
- नीति ने "मर्चेण्टिंग ट्रेड" नामक संभावित निर्यात का एक नया क्षेत्र खोल दिया था।
- मर्चेण्टिंग ट्रेड भारतीय बंदरगाहों को छुए बिना एक विदेशी देश से दूसरे विदेशी देश में माल की शिपमेंट को संदर्भित करता है, जिसमें एक भारतीय मध्यस्थ शामिल होता है। इससे प्रतिबंधित वस्तुओं का निर्यात भी हो सकेगा।
- उत्तर प्रदेश के चार शहरों - फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी - को क्रमशः परिधान, हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित कालीन और हथकरघा में उनके प्रदर्शन के लिए निर्यात उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में घोषित किया गया।
- नीति में कपड़े और परिधान क्षेत्र के लिए एक विशेष अग्रिम प्राधिकरण योजना शुरू करने की भी योजना है ताकि वे बाजार की मांग और फैशन के रुझान पर तेजी से प्रतिक्रिया कर सकें।
- यह स्टार रेटिंग के लिए योग्यता सीमा को कम करने पर भी विचार कर रहा है जो निर्यात प्रदर्शन के आधार पर निर्यातकों को मान्यता देता है।
- SCOMET (विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण, और प्रौद्योगिकी) लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने का महत्व जिसका उद्देश्य दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात को सुव्यवस्थित करना है।
- निर्यात दायित्वों में चूक के लिए विशेष एकमुश्त क्षमादान कार्यक्रम शामिल है।
- नई विदेश व्यापार नीति के तहत डेयरी उद्योग को औसत निर्यात दायित्वों को बनाए रखने से छूट दी जाएगी, और एक विशेष अग्रिम प्राधिकरण प्रक्रिया को कपड़ा और कपड़ों के लिए बढ़ा दिया गया है।

चुनौतियां:

- **कम ऋण पहुंच:** भारतीय निर्यातकों की व्यापार वित्त और निर्यात ऋण तक बहुत कम पहुंच है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों

(एमएसएमई) के लिए विशेष रूप से सच है, भले ही वे भारत के कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा हैं।

- भारतीय निर्यातकों को मिलने वाली वित्तीय सहायता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।
- निर्यात ऋण एजेंसियों ने भारत में 7.6 बिलियन डॉलर की धनराशि दी, जबकि चीन के लिए यह आंकड़ा 39.1 बिलियन डॉलर था।
- **अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर:** इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की सबसे कमजोर कड़ी है। डेटा फर्म स्टेटिस्टा की 2019 में उनके बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के आधार पर 100 देशों की रैंकिंग में भारत का स्कोर 68.1 था।
 - इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, शीर्ष क्रम वाले सिंगापुर ने 95.4 स्कोर किया, जबकि नीचे का स्थान बोलीविया 57.1 पर भारत से 10 अंक पीछे था।
- **नौकरशाही:** उच्च दस्तावेजीकरण आवश्यकता के कारण भारत में निर्यात प्रक्रिया कई अन्य देशों की तुलना में अधिक समय लेने वाली है।
 - भारतीय निर्यातकों को शिपिंग प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए दस्तावेजों का एक बड़ा सेट तैयार करना चाहिए।
 - आगे की योजना बनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय बंदरगाहों पर प्रमाणन प्राधिकरण चौबीसों घंटे या सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध नहीं होते हैं।
- **लंबित:** पूर्व-आयात शर्तों के कारण अग्रिम प्राधिकरण योजना के संबंध में मोचन के लंबित मामलों की लंबी सूची है।
 - पूर्वव्यापी प्रभाव से पूर्व-आयात शर्त को हटाकर इसे तुरंत हल करने की आवश्यकता है।

निर्यात में सुधार के लिए सरकार की पहल:

- **निर्यात उत्पाद पर शुल्क या करों की छूट (आरओडीटीईपी):** यह भारत में निर्यात बढ़ाने में मदद करने के लिए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लिए पूरी तरह से स्वचालित मार्ग है।
 - ITC कच्चे माल, उपभोग्य सामग्रियों, वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर चुकाए गए कर को समायोजित करने के लिए प्रदान किया जाता है जिनका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के निर्माण में किया गया था।
 - यह दोहरे कराधान और करों के व्यापक प्रभाव से बचने में मदद करता है।
- **मर्चेडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम:** एमईआईएस को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 में पेश किया गया था, एमईआईएस के तहत सरकार उत्पाद और देश के आधार पर शुल्क लाभ प्रदान करती है।
 - इस योजना के तहत पुरस्कार वास्तविक फ्री-ऑन-बोर्ड मूल्य (2%, 3% और 5%) के प्रतिशत के रूप में देय हैं और एमईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को मूल सीमा शुल्क सहित कई शुल्कों के भुगतान के लिए स्थानांतरित या उपयोग किया जा सकता है।
- **राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट:** यह योजना एम्बेडेड राज्य और केंद्रीय शुल्कों और करों के लिए पेश की गई थी, जो वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के माध्यम से वापस नहीं किए जाते हैं।
 - यह केवल कपड़ों के लिए उपलब्ध था।
 - इसे कपड़ा मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था।
- **व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उत्पत्ति के प्रमाण पत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।**



DM








आकस्मिक सूखा (Flash drought)

संदर्भ: हाल के एक अध्ययन के अनुसार, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, उप-सहारा अफ्रीका और अमेज़ॉन बेसिन जैसे उष्णकटिबंधीय स्थानों में पारंपरिक 'धीमे' सूखे की तुलना में आकस्मिक सूखा (Flash drought) अधिक बार आया।

आकस्मिक सूखे के बारे में:

- मानसून के दौरान काफी कम वर्षा वाली विसंगतियों के साथ काफी लंबे शुष्क दौर के परिणामस्वरूप हवा के तापमान में वृद्धि होती है। हवा के तापमान में वृद्धि और वर्षा की कमी मिलकर मिट्टी की नमी में तेजी से कमी का कारण बनते हैं जिससे आकस्मिक सूखा पड़ता है।
- दीर्घकालिक सूखे पर उपलब्ध शोध की तुलना में आकस्मिक सूखे या 'छिपे हुए खतरों' के बारे में बहुत कम जानकारी होती है।
- अचानक सूखा मानसून के मौसम में भी हो सकता है, जो मुख्य रूप से मानसून के टूटने के कारण होता है और ये गर्मी के देरी से शुरू होने के कारण भी हो सकता है।
- वायुमंडलीय विसंगतियों (विविधताओं), मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और चल रहे जलवायु परिवर्तन से अचानक सूखा पड़ सकता है।
- पूर्व-चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस), जो जलवायु और पानी के स्रोतों में प्रवृत्तियों की पहचान कर सकती है, का उपयोग आकस्मिक सूखे की घटना के उद्भव या संभावना का पता लगाने के लिए किया जाता है।

FIVE TYPES OF DROUGHT	
1	METEOROLOGICAL drought refers to an extended period of dry weather patterns. 
2	HYDROLOGICAL drought refers to low water supply in our rivers, lakes, aquifers, and other reservoirs that often follows meteorological drought. 
3	AGRICULTURAL drought occurs when a water shortage significantly damages or destroys agricultural crops. 
4	ECOLOGICAL drought is the most recently defined type of drought and refers to widespread ecological damage caused by the lack of soil moisture. 
5	SOCIOECONOMIC drought refers to when a water shortage affects the supply and demand of drought commodities, such as water, food grains, and fish. 

सूखे के बारे में:

- सूखा असामान्य रूप से लगातार शुष्क मौसम की अवधि है जो लंबे समय तक बनी रहती है जिससे फसल क्षति और/या पानी की आपूर्ति की कमी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।
- सूखे की गंभीरता नमी की कमी की मात्रा, अवधि और प्रभावित क्षेत्र के आकार पर निर्भर करती है।

सूखे के कारण:

मौसम संबंधी सूखे के कारण: कमजोर मानसून और औसत से कम वर्षा, मानसून की देर से शुरुआत या जल्दी वापसी और मानसून में लंबे समय तक विराम।

हाइड्रोलॉजिकल सूखे के कारण: बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, पारिस्थितिक रूप से खतरनाक खनन और भूजल का अत्यधिक पंपिंग।

कृषि सूखे के कारण:

- HYV (उच्च उपज वाली किस्मों) के बीजों का अत्यधिक उपयोग
- फसल पद्धति में परिवर्तन उदा. हरित क्रांति की शुरुआत के साथ

प्रभाव:

- सूखा आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का कारण बनता है।
 - कृषि और जल संसाधनों पर पहले दौर के प्रभावों में सूखे के प्रभावों का महत्वपूर्ण अनुपात है।
 - अन्य सूखे से प्रभावित आबादी पर अनुवर्ती प्रभाव हैं, जैसे कि किसान आय और सूखा प्रभावित आबादी के स्वास्थ्य, पोषण

और शिक्षा की स्थिति।

- तीसरा स्तर अनुप्रवाह गतिविधियों पर है, जैसे कि कृषि और पानी पर निर्भर उद्योग।
- अंत में, विकास, व्यापार, विदेशी मुद्रा, राजकोषीय संतुलन, और इसी तरह की अन्य चीजों पर दूरगामी और दीर्घकालीन प्रभाव हैं।
- **क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजी)**, एक अंतर-मंत्रालयी तंत्र, आईएमडी और अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी निकायों द्वारा प्रस्तुत सूचना और डेटा का मूल्यांकन करता है ताकि कृषि पर मौसम संबंधी घटनाओं और अन्य पर्यावरणीय मापदंडों के संभावित प्रभाव का निर्धारण किया जा सके।



भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र

- भारत में, देश का लगभग 68% हिस्सा अलग-अलग डिग्री के सूखे की चपेट में है।
- 750 मिमी और 1125 मिमी के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले 35% क्षेत्र को सूखा प्रवण माना जाता है, जबकि 750 मिमी से कम प्राप्त करने वाले 33% क्षेत्र को दीर्घकालिक सूखा प्रवण माना जाता है।

वैश्विक स्तर पर उठाए जा रहे कदम:

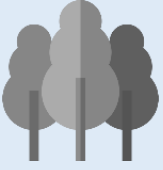
- **2019 की दिल्ली घोषणा, यूएनसीसीडी के 14वें सीओपी द्वारा हस्ताक्षरित (बॉन चैलेंज, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव:** आदि के लिए इस लिंक को देखें), भूमि पर बेहतर पहुंच और नेतृत्व का आह्वान किया, और लिंग-संवेदनशील परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर जोर दिया।
- **बॉन चुनौती:** 2020 तक दुनिया की 150 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई और बंजर भूमि को बहाली में लाने के लिए, और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर को बहाल करने के लिए।
- **ग्रेट ग्रीन वॉल:** वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा पहल, जहां सहल-सहारा अफ्रीका के ग्यारह देशों ने भूमि क्षरण के खिलाफ लड़ने और प्राकृतिक पौधों के जीवन को परिदृश्य में पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है।
- **शांति वन पहल:** यह शांति निर्माण प्रक्रिया के रूप में पारिस्थितिक बहाली का उपयोग करने के लिए दक्षिण कोरिया की एक पहल है और इसका उद्देश्य संघर्षग्रस्त सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि क्षरण के मुद्दे को संबोधित करना है।
- **रेत और धूल के तूफानों पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (एसडीएस):** इन तूफानों की निगरानी और प्रतिक्रिया में सुधार के लक्ष्य के साथ एसडीएस स्रोत आधार मानचित्र विकसित किया जाएगा।

आगे की राह : सूखा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशानिर्देश

- एनडीएमए के दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण जानकारी संकलित करने के लिए क्षेत्रों, समुदायों, जनसंख्या समूहों और अन्य लोगों के लिए भेद्यता प्रोफाइल विकसित करना शामिल है, जो विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने और प्राथमिकता देने की प्रक्रिया के परिणाम को बढ़ा सकते हैं।
- एसडीएमए के तहत राज्य स्तर पर विशिष्ट सूखा प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाए जाने चाहिए।
 - ये डीएमसी अपने संबंधित राज्यों के लिए भेद्यता मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

○ शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां सूखा अलग-अलग परिमाण के साथ होने वाली एक आवर्ती विशेषता है।

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश और ऑनलाइन बातचीत के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की भूमिका और सूखे से संबंधित वास्तविक समय की जानकारी की उपलब्धता जो मूल्यांकन और प्रारंभिक चेतावनी में मदद करेगी।
- अपेक्षित नुकसान के आकलन में कृषि उत्पादन, जल संसाधनों की कमी, पशुधन आबादी, भूमि क्षरण, और वनों की कटाई के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य भी शामिल होगा।



पर्यावरण

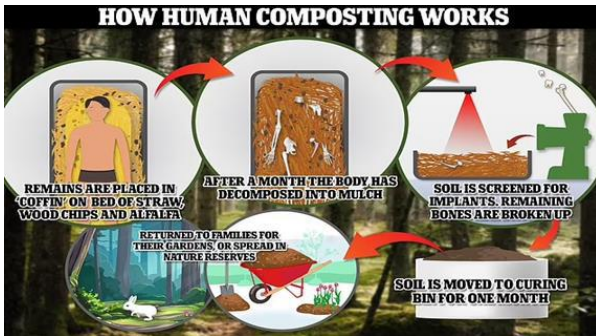


ह्यूमन कम्पोस्टिंग: ए ग्रीनर वे टू डाई

संदर्भ: कोलोराडो, ओरेगन, वर्मोंट और कैलिफोर्निया के बाद न्यूयॉर्क अमेरिका में छठा ऐसा राज्य बन गया है जहां मृत शरीर को खाद में बदलने को कानूनी मंजूरी दे दी गई है।

- वाशिंगटन 2019 में ऐसा करने वाला पहला देश था।

मानव खाद के बारे में:



Source: [dailymail.co.uk](https://www.dailymail.co.uk)

- मानव खाद, जिसे प्राकृतिक जैविक कमी के रूप में भी जाना जाता है, मानव शरीर को पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में बदलने की एक प्रक्रिया है जो पारंपरिक दफनाने या दाह संस्कार के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में उभरी है।
- लाश के निपटान के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प होने के कारण, विशेष रूप से युवा रूप से युवा पीढ़ी के बीच इसने लोकप्रियता हासिल की है।

मानव खाद बनाने की प्रक्रिया:

- शरीर को पहले धोया जाता है और बायोडिग्रेडेबल उगाए जाने वाले कपड़े पहनाए जाते हैं।
- इसके बाद इसे अल्फाल्फा(alfalfa), पुआल और चूरा जैसी चयनित सामग्री के साथ आमतौर पर 8 फीट x 4 फीट के एक बंद बर्तन में रखा जाता है।
- शव को अगले 30 दिनों के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है।
- क्षय को तेज करने के लिए, पोट में ऑक्सीजन जोड़ा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप "एरोबिक पाचन" नामक एक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें रोगाणु कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करना शुरू कर देते हैं।
- संदूषण को खत्म करने के लिए कंटेनर के अंदर का तापमान 130 डिग्री फ़ारेनहाइट या 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है।
- जब तक एरोबिक पाचन समाप्त हो जाता है, तब तक शरीर मिट्टी जैसी सामग्री में बदल जाता है, जिसमें पोषक तत्व, हड्डियां और कुछ चिकित्सा उपकरण होते हैं - इन्हें खाद के ढेर से निकाल लिया जाता है और पुनर्नवीनीकरण किया जाता है।
- जैसे ही माइक्रोबियल गतिविधि समाप्त होती है, पाइल के अंदर का तापमान गिर जाता है, एक सक्रिय समग्र पाइल से मिट्टी में परिवर्तन को चिह्नित करता है।

चिंता:

- इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा विरोधी कैथोलिक चर्च रहा है और इसे "मृतक से आध्यात्मिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दूरी दुर्भाग्यपूर्ण" कहा।
- यह माना जाता है कि अवशेषों का 'रूपांतरण' अवशेषों के प्रति सम्मान के बजाय एक भावनात्मक दूरी पैदा करेगा।
- यहां तक कि दाह संस्कार मानव शरीर में निहित गरिमा और अमर आत्मा के साथ इसके संबंध के अनुरूप सांप्रदायिक स्थान पर रहना चाहिए।

महत्व: मानव खाद को दफनाने और दाह संस्कार के विकल्प के रूप में देखा जाता है:

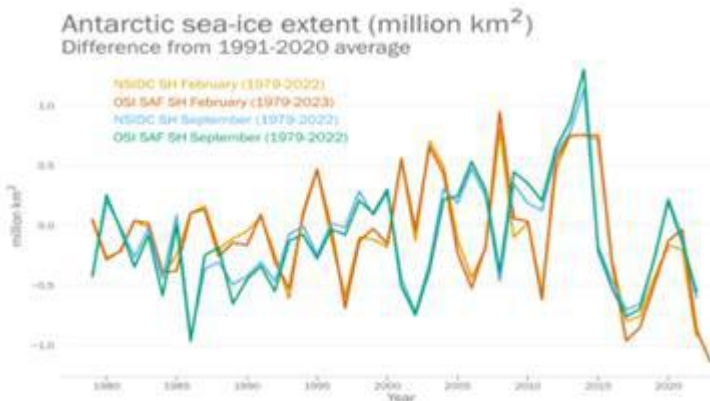
- दफनाने और दाह संस्कार जैसे तरीकों को तेजी से कार्बन उत्सर्जन में योगदान देने वाले के रूप में देखा जा रहा है।
 - एक शव का दाह संस्कार करने से हवा में अनुमानित 190 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो एक कार में 756 किमी ड्राइव करने के बराबर है।

- दफ़नाने के अपने खतरे भी हैं - भूमि के अनिश्चितकालीन उपयोग के अलावा, इसमें एक लाश को जहरीले घोल में लेप करना शामिल है, जो मिट्टी के लिए हानिकारक हो सकता है।
- अंत्येष्टि और दाह संस्कार महंगे हैं, और बहुत से लोग उन्हें वहन नहीं कर सकते।
 - यूएस में, औसतन पारंपरिक अंत्येष्टि में \$7,000 से \$10,000 का खर्च आता है।
- इसलिए, मानव खाद बनाने की लागत लगभग \$5,500 है, जिसमें लेइंग-इन समारोह भी शामिल है, और दाह संस्कार की तुलना में बहुत कम ऊर्जा का उपयोग एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरा है।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित मिट्टी का उपयोग बागवानी के लिए किया जा सकता है या नामित स्मारक मैदानों या वन संरक्षण क्षेत्रों में फैलाया जा सकता है।

ग्लेशियल रिट्रीट: कारण और प्रभाव

संदर्भ: वैश्विक जलवायु 2022 की स्थिति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा जारी की गई थी।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:



Record low breaking of the Antarctica sea ice in February 2022

- पिघलते ग्लेशियर और गर्म होते महासागरों ने वैश्विक समुद्र स्तर को 2022 में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया।
- 1993 से 2002 तक उपग्रह रिकॉर्ड के पहले दशक में वैश्विक समुद्र के स्तर में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है।
- समुद्र के ताप स्तर ने रिकॉर्ड तोड़ा, लगभग 60% लोगों ने कम से कम एक समुद्री ऊष्मा लहर का अनुभव किया।
- 2013 से 2022 तक पिघलते ग्लेशियर और समुद्र के उच्च तापमान के कारण समुद्र के स्तर में औसतन 4.62 मिमी प्रति वर्ष की वृद्धि हुई।

ग्लेशियल रिट्रीट के बारे में:

- ग्लेशियल रिट्रीट बर्फ संचय में कमी या बर्फ के पिघलने में वृद्धि के कारण समय के साथ ग्लेशियर के सिकुड़ने या आकार में कमी की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- **ग्लेशियरों के पिघलने के उदाहरण:**
 - ग्रीनलैंड आइस शीट - प्रति वर्ष लगभग 280 बिलियन टन बर्फ का नुकसान;
 - हिमालय के ग्लेशियर 2100 शताब्दी तक पूरी तरह से गायब हो सकते हैं।
 - यूरोपीय आल्प्स में ग्लेशियर 19वीं शताब्दी के मध्य से पीछे हट रहे हैं,
 - 0 दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में ग्लेशियर 1970 के दशक से अपने द्रव्यमान का 80% तक खो चुके हैं।

ग्लेशियरों के पिघलने के कारण:

- **जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग:** बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, क्योंकि वे नई बर्फ जमा करते हैं।
- **वर्षण (precipitation) में परिवर्तन:** वर्षण की मात्रा, समय और रूप में परिवर्तन भी हिमनदों की सीमा और मोटाई को प्रभावित कर सकता है।
- **मानवीय गतिविधियाँ:** वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन को जलाना, और औद्योगिक प्रक्रियाएँ आदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान करती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख चालक हैं, जो बदले में ग्लेशियरों के पिघलने का कारण बनते हैं।
- **सौर विकिरण:** इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा की वह मात्रा है जो बर्फ को छूती है, जिसका प्रभाव ग्लेशियर के पिघलने और घटने पर पड़ता है। विकिरण-प्रेरित पिघलने में वृद्धि के परिणामस्वरूप ग्लेशियर द्रव्यमान खो देते हैं।
- **ग्लेशियल टिल:** हिमनद के रूप में जाना जाने वाला सामग्री का अनसुलझा द्रव्यमान हिलते हुए ग्लेशियरों द्वारा इकट्ठा किया जाता है।

और इसमें गाद से लेकर बड़े बोल्टर तक शामिल होता है।

- बर्फ को शिलाखंडों द्वारा संरक्षित किया जाता है जबकि इसके आसपास की कमजोर बर्फ पिघल जाती है।

ग्लेशियरों के पिघलने का प्रभाव:

- एक ग्लेशियर के पीछे हटने के कारण, यह कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों को जन्म दे सकता है, जिसमें पानी की उपलब्धता में परिवर्तन, स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन और बाढ़ तथा भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम बढ़ जाना शामिल है।
- समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय क्षरण: जब ग्लेशियरों के पिघलने के कारण समुद्र का स्तर बढ़ता है, तो हरिकेन और टाइफून जैसे शक्तिशाली तटीय तूफान उत्पन्न होते हैं।
 - विशेष रूप से अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरें दुनिया भर में समुद्र के स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण हैं।
- **पानी की कमी:** ग्लेशियर दुनिया भर के कई समुदायों के लिए मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
 - जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते और पीछे हटते हैं, इससे पानी की कमी हो सकती है और कृषि और अन्य उद्योग प्रभावित हो सकते हैं।
- **मौसम के मिजाज में बदलाव:** पिघलते ग्लेशियर मौसम के मिजाज को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे तापमान, वर्षा और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं में बदलाव हो सकता है।
 - जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो परिणामस्वरूप ताजा पानी समुद्र में जाता है, जो उत्तरी अटलांटिक के लवणता संतुलन को अस्थिर कर सकता है और AMOC को कमजोर कर सकता है।
 - यह कमजोर पड़ने से क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि यूरोप में ठंडा तापमान और उत्तरी अटलांटिक में तूफान की गतिविधि में वृद्धि।
- **अल्बेडो प्रभाव में कमी:** जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, वे सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करने की पृथ्वी की क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे सौर विकिरण और गर्म तापमान का अवशोषण बढ़ जाता है।
- **मछली पकड़ने के उद्योग:** जीवंत मछली पालन पर फलने-फूलने वाले उद्योग प्रभावित होंगे क्योंकि गर्म पानी मछली के अंडे देने के स्थान और समय को बदल देता है।
 - तटीय समुदायों को अरबों डॉलर के आपदा रिकवरी बिलों का सामना करना जारी रहेगा क्योंकि बाढ़ लगातार आती जाती है और तूफान अधिक तीव्र होते रहते हैं।
- **वन्यजीव:** आर्कटिक में, जैसे-जैसे समुद्री बर्फ पिघल रही है, वालरस जैसे वन्यजीव अपना घर खो रहे हैं और ध्रुवीय भालू भूमि पर अधिक समय बिता रहे हैं, जिससे लोगों और भालुओं के बीच संघर्ष की दर बढ़ रही है।
- **प्रवाल भित्तियों का खतरा:** प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से फलने-फूलने के लिए प्रवाल भित्तियों को धूप की आवश्यकता होती है।
 - ग्लेशियरों के पिघलने या पीछे हटने के कारण, समुद्र का बढ़ता स्तर प्रवाल को पर्याप्त धूप प्राप्त करने से रोकता है।

आगे की राह : सुझावात्मक उपाय

- **कार्बन उत्सर्जन कम करना:** यह पवन और सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाकर और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए नीतियों को लागू करके किया जा सकता है। उदा. शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करना।
- **ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना:** इसमें भवन इन्सुलेशन में सुधार और ऊर्जा कुशल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल हैं। उदा. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा हरित आवास योजना।
- **सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना:** इससे निजी कारों के उपयोग को कम किया जा सकता है और परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। उदा. हांगकांग में सार्वजनिक परिवहन किराया सब्सिडी योजना।
- **वनीकरण और वनों की कटाई को कम करना:** पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसलिए अधिक पेड़ लगाने से हवा में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **अपशिष्ट और पुनर्चक्रण को कम करना:** यह लैंडफिल और अन्य अपशिष्ट निपटान विधियों के माध्यम से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को कम कर सकता है।
- **टिकाऊ कृषि पद्धतियों को लागू करना:** ये प्रथाएं कृषि गतिविधियों से उत्सर्जन को कम करने और जल संसाधनों को संरक्षित करने में मदद कर सकती हैं। उदा. संरक्षण जुताई।
- **अंतरराष्ट्रीय समझौते:** कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए सरकारें अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर मिलकर काम कर सकती हैं। उदा. पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आदि।



इतिहास, कला और संस्कृति



वैकोम सत्याग्रह

संदर्भ: हाल ही में, केरल के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से जाति-विरोधी संघर्ष वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया।

वैकोम सत्याग्रह के बारे में

- वैकोम सत्याग्रह देश में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक ऐतिहासिक अहिंसक आंदोलन था।
- सत्याग्रह 30 मार्च, 1924 और 23 नवंबर, 1925 के बीच हुआ और पूरे भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों की शुरुआत भी हुई।
- इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस नेता टी.के. माधवन, सामाजिक अन्याय के विरोध के रूप में।
- माधवन के अलावा, के.पी. केशव मेनन (केरल कांग्रेस के तत्कालीन सचिव) और कांग्रेस नेता और शिक्षाविद के. केलप्पन को वैकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है।
- वैकोम भारत के केरल राज्य के कोट्टायम जिले के पश्चिमी छोर पर स्थित है।
 - यह वेम्बनाड झील के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
- सत्याग्रह का उद्देश्य वैकोम में श्री महादेव मंदिर की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़कों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था।

वैकोम सत्याग्रह से पहले की स्थिति

- त्रावणकोर साम्राज्य में कठोर और दमनकारी जाति व्यवस्था थी।
- उत्पीड़ित वर्ग के लोगों, विशेषकर एझावाओं को वैकोम महादेव मंदिर के आसपास की चार सड़कों पर चलने का कोई अधिकार नहीं था।
- दलित वर्गों के साथ हुए अन्याय को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की काकीनाडा बैठक में एक प्रस्ताव के रूप में ध्यान में लाया गया।
- जनवरी 1924 में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित कांग्रेस अस्पृश्यता समिति ने इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया।
- के.केलप्पन (केरल गांधी), टी.के.माधवन, वेलायुधा मेनन, के.नीलकांतन नंबूदरी और टी.आर.कृष्णास्वामी अय्यर समिति के सदस्य थे।
- समिति ने मंदिर में प्रवेश का आग्रह करने और जाति या पंथ की परवाह किए बिना सभी के लिए सभी सार्वजनिक सड़कों को खोलने की वकालत करने के लिए एक 'केरल पर्यटनम' शुरू करने का फैसला किया।

पेरियार की भूमिका:

- पेरियार ने नीलकंदन नामपूथिरी और जॉर्ज जोसेफ जैसे नेताओं के अनुरोध को स्वीकार किया और विरोध को सफल बनाने के लिए विरोध का नेतृत्व किया।
- वि. कल्याणसुंदरम (थिरु.वि.का.) ने पेरियार को वैकोम वीरार (वैकोम के नायक) की उपाधि प्रदान की।
- वैकोम सत्याग्रह में तमिलनाडु ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अछूतों के संघर्ष का प्रतीक था।
- एम्पेरुमल नायडू और शिवतनु पिल्लई नागरकोइल, तमिलनाडु में प्रमुख नेता थे।

आंदोलन की पहुंच

- आंदोलन को गांधीजी, चतमपी स्वामीकल और श्री नारायण गुरु का समर्थन प्राप्त था।
- केरल के प्रमुख नेता जैसे माधवन, के.पी. केशव मेनन और जॉर्ज जोसेफ ने आंदोलन चलाया।
- तमिलनाडु के पेरियार और कोवई अय्यामुथु ने दमनकारी कार्रवाई का सामना करने के बावजूद केरल में नेताओं के साथ मिलकर काम किया।
- अभियान ने पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल की, और देश भर से समर्थक पहुंचे।
- पंजाब के अकालियों ने सत्याग्रहियों के भोजन के लिए रसोइयों की स्थापना कर मदद की।
- मुस्लिम और ईसाई अधिकारियों ने भी इस पहल का समर्थन किया।

वैकोम सत्याग्रह के प्रभाव

- वैकोम सत्याग्रह सत्याग्रह के गांधीवादी सिद्धांतों के लिए एक परीक्षण स्थल था।
- 1925 में, गांधीजी ने चल रहे मामले को सुलझाने के लिए त्रावणकोर के तत्कालीन पुलिस आयुक्त एच. पिट को लिखा।
 - इस प्रकार, पिट ने हस्तक्षेप किया और सरकार और गांधीजी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- 1925 में, फरवरी 1924 में पारित प्रतिबंधात्मक आदेशों को रद्द करने के लिए सरकार सहमत हो गई और गांधीजी ने सत्याग्रह वापस लेने

के लिए अपनी सहमति दे दी।

- सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वैकोम (उत्तर, दक्षिण और पश्चिम) के शिव मंदिर या महादेव मंदिर के तीन तरफ की सड़कें (रास्ते) सभी जनता के लिए खुली रहेंगी लेकिन पूर्वी तरफ की सड़क यानी उस ओर जाने वाली सड़कें पूर्वी मार्ग सवर्णों के लिए ही आरक्षित रहेगा।
- कई इतिहासकारों का मानना था कि वैकोम सत्याग्रह ने वांछित परिणाम नहीं दिया था, जबकि माना जाता था कि समझौता क्रांतिकारी कारण की पहली की तुलना में अपमानजनक था।
- हालाँकि, इस आंदोलन ने वह नींव रखी जिसने अंततः रूढ़िवादी उपनिवेशवाद को समाप्त करने का परिणाम दिया।
- वैकोम सत्याग्रह ने लगभग एक दशक बाद अपने महत्व की घोषणा की जब नवंबर 1936 में, ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश उद्घोषणा पारित की गई, जिसने त्रावणकोर के मंदिरों में वंचित दलित जातियों के प्रवेश पर सदियों पुराने रूढ़िवादी प्रतिबंध को हटा दिया।
- यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए केरल में बढ़ने का एक बड़ा अवसर भी था।
 - यह भारत में मानवाधिकारों के लिए पहला संघर्ष बना।
- वैकोम सत्याग्रह का भारतीय समाज और राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
 - इसने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम (SNDP) के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, जो एक सामाजिक सुधार संगठन है, जिसने केरल में निचली जातियों के उत्थान के लिए काम किया।

वैकोम सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने जाति व्यवस्था के अन्याय और सामाजिक सुधार की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया। विरोध ने अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की और सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करने में अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को इतिहास में जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ सबसे अहिंसक संघर्षों में से एक के रूप में दर्ज किया गया है।



सामाजिक मुद्दे



मानसिक बीमारी: भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय

संदर्भ: हाल ही में जर्नल ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट द्वारा मानसिक बीमारी के बोझ पर किए गए एक नए अध्ययन में मानसिक बीमारी के इलाज पर खर्च पर प्रकाश डाला गया, जो 20% भारतीय परिवारों को गरीबी में धकेल देता है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- मानसिक बीमारियों के इलाज पर पैसा खर्च करने के कारण 20% भारतीय परिवार गरीब हो जाते हैं
 - मानसिक बीमारी के कारण भारत का राष्ट्रीय औसत स्वास्थ्य देखभाल बोझ 10.4% है।
- अधिक बोझ वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश: दमन और दीव (19.4%), हिमाचल प्रदेश (18.0%), सिक्किम (17.4%), लक्षद्वीप (14.6%), महाराष्ट्र (13.7%), तेलंगाना (13.3%), पंजाब (12.7%) और उत्तराखंड (12.5%)।
- कम बोझ वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश: मिजोरम (0.5%), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1.2%), पुडुचेरी (1.7%), दादरा और नगर हवेली (2.0%), अरुणाचल प्रदेश (3.0%) और नागालैंड (3.5%)।
- मानसिक बीमारी वाले निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अधिकांश लोगों को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है, जिससे जीर्णता (chronicity), पीड़ा और देखभाल की लागत में वृद्धि होती है।

मानसिक स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में

- मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है जो लोगों को जीवन के तनावों का सामना करने, अपनी क्षमताओं का एहसास करने, अच्छी तरह से सीखने और अच्छी तरह से काम करने और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है।
- यह स्वास्थ्य और कल्याण का एक अभिन्न अंग है जो निर्णय लेने, संबंध बनाने और हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार देने के लिए हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं को आधार प्रदान करता है।
- मानसिक स्वास्थ्य एक बुनियादी मानव अधिकार है।
- यह व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।
- 'मानसिक विकार' शब्द का प्रयोग मानसिक, व्यवहार संबंधी विकारों और मनोसामाजिक अक्षमताओं की एक श्रृंखला को दर्शाने के लिए किया जाता है।
 - वे आम तौर पर असामान्य विचारों, धारणाओं, भावनाओं, व्यवहार और दूसरों के साथ संबंधों के संयोजन द्वारा पहचाने जाते हैं।
 - मानसिक विकारों में अवसाद, द्विध्रुवी विकार, सिज़ोफ्रेनिया और अन्य मनोविकृति, मनोभ्रंश, और आत्मकेंद्रित सहित विकास संबंधी विकार शामिल हैं।

मानसिक स्वास्थ्य के निर्धारक:

- कई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक कारक किसी भी समय किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के स्तर को निर्धारित करते हैं।
- उदाहरण के लिए, हिंसा और लगातार सामाजिक-आर्थिक दबाव मानसिक स्वास्थ्य के लिए पहचाने गए जोखिम हैं। सबसे स्पष्ट प्रमाण यौन हिंसा से जुड़ा है।
- तेजी से सामाजिक परिवर्तन, तनावपूर्ण काम की स्थिति, लिंग भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, अस्वास्थ्यकर जीवनशैली, शारीरिक अस्वस्थता और मानवाधिकारों का उल्लंघन यह सब खराब मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ है।
- विशिष्ट मनोवैज्ञानिक और व्यक्तित्व कारक हैं जो लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। जैविक जोखिमों में आनुवंशिक कारक शामिल हैं।

मुद्दे और चिंताएं:

- पिछले कुछ दशकों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं।
- 2015 में, भारत सरकार ने देश में मानसिक स्वास्थ्य के प्रसार का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 2015-16 किया।
 - रिपोर्ट में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में 10.6 प्रतिशत, 30-49 वर्ष के उत्पादक आयु वर्ग के बीच 16 प्रतिशत - और आजीवन रणता 150 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है, जिसमें एक प्रतिशत उच्च आत्मघाती जोखिम की रिपोर्ट करता

है।

- मानव संसाधन और उपचार सुविधाएं बहुत कम हैं।
- नीति निर्माताओं के लिए, मानसिक स्वास्थ्य एक निम्न प्राथमिकता है।
 - इस तरह के खराब नीतिगत ध्यान को अक्सर नौकरशाहों और राजनेताओं के बीच उदासीनता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
- नीति तैयार करना नीति-निर्माण का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है।

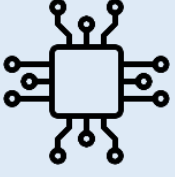
भारत सरकार की पहल:

- **संवैधानिक प्रावधान:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सेवा को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना है।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी):** मानसिक विकारों के भारी बोझ और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू कर रही है।
 - दो योजनाओं को शामिल करने के लिए 2003 में कार्यक्रम की फिर से रणनीति बनाई गई थी। राज्य मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण और मेडिकल कॉलेजों/सामान्य अस्पतालों के मनोरोग विंगों का उन्नयन किया।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017:** यह सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित सेवाओं से प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुंच की गारंटी देता है।
 - इसने आईपीसी की धारा 309 के उपयोग के दायरे को काफी कम कर दिया है और आत्महत्या करने के प्रयास को केवल एक अपवाद के रूप में दंडनीय बना दिया है।
- **किरण हेल्पलाइन:** 2020 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन 'किरण' शुरू की।
- **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2017:** अधिनियम मानसिक बीमारी को विकलांगता के रूप में स्वीकार करता है और विकलांगों के अधिकारों और अधिकारों को बढ़ाने का प्रयास करता है और समाज में उनके सशक्तिकरण और समावेश को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र प्रदान करता है।
- **मनो दर्पण पहल:** आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता प्रदान करना है।

आगे की राह

मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ऐसी रहने की स्थिति और वातावरण बनाने की आवश्यकता है जो मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करे और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और बनाए रखने की अनुमति दे। एक ऐसा समाज जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी, नागरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान और उनकी रक्षा करता है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीतियों को केवल मानसिक विकारों से संबंधित नहीं होना चाहिए, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले व्यापक मुद्दों को पहचानना और उनका समाधान करना चाहिए। इसमें शिक्षा, श्रम, न्याय, परिवहन, पर्यावरण, आवास और स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल हैं।



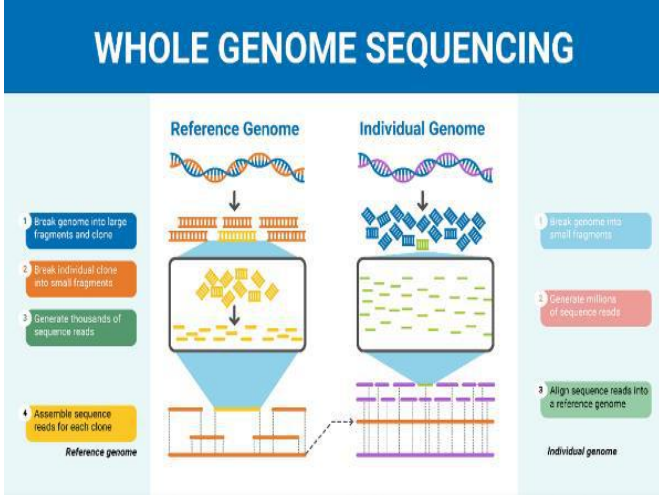
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी



जीनोम सीक्वेंसिंग और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट

संदर्भ: जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2023 के अंत तक 10,000 जीनोम के पूरी तरह से अनुक्रमित होने की उम्मीद है।

जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में:



- एक जीनोम आनुवंशिक निर्देशों का एक पूरा सेट है जो एक जीव में उसके डीएनए में मौजूद होता है।
- सीक्वेंसिंग चार न्यूक्लियोटाइड बेस यानी एडेनाइन (A), साइटोसिन (C), गुआनिन (G), और थाइमिन (T) की घटनाओं का क्रम है।
- मानव जीनोम इन आनुवंशिक अक्षरों के 3 बिलियन से अधिक से बना है।
- पूरे जीनोम को एक साथ अनुक्रमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि डीएनए अनुक्रमण के उपलब्ध तरीके एक समय में केवल डीएनए के छोटे हिस्सों को ही संभाल सकते हैं।
- जबकि मानव जीनोम डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) से बने होते हैं, एक वायरस जीनोम या तो डीएनए या आरएनए (राइबोन्यूक्लिक एसिड) से बना हो सकता है।
- कोरोना वायरस आरएनए से बना है। प्रत्येक जीव का एक अद्वितीय जीनोम अनुक्रम होता है।
- जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जो डीएनए या आरएनए में पाई जाने वाली आनुवंशिक जानकारी को रीड और उसकी व्याख्या करती है।

जीनोम सीक्वेंसिंग का महत्व

- **वायरस को समझना :** जीनोम सीक्वेंसिंग का उद्देश्य वायरस की संक्रामकता को बढ़ाने में कुछ म्यूटेशन की भूमिका को समझना है।
 - कुछ म्यूटेशन प्रतिरक्षा पलायन या एंटीबॉडी से बचने की वायरस की क्षमता की व्याख्या करते हैं जिसका टीकों के लिए परिणाम होता है।
- **प्रभावकारिता का अध्ययन:** यह अध्ययन करने में मदद करता है कि क्या अब तक विकसित टीके वायरस के ऐसे उत्परिवर्ती तनावों के खिलाफ प्रभावी हैं और क्या पुनः संक्रमण और संचरण को रोक सकते हैं।
- **म्यूटेशन का पता लगाना:** वायरल स्ट्रेन के जीनोम की सीक्वेंसिंग "अपने-दुश्मन को जानने" के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि म्यूटेशन का पता लगाना आसान हो जाता है।
 - वैज्ञानिक बहुत अधिक आसानी से और शीघ्रता से उत्परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं।
- **टीकों का विकास:** महत्वपूर्ण अनुसंधान के माध्यम से उत्पन्न ज्ञान अभी और भविष्य में संभावित बीमारियों के निदान और संभावित चिकित्सीय और टीकों के विकास में सहायता करता है।
- **महत्वपूर्ण जानकारी:** महत्वपूर्ण जानकारी और निष्कर्ष उन लोगों के जीनोम अनुक्रमण से प्राप्त किए जा सकते हैं जिन्होंने COVID या चिंता के किसी अन्य वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था।

भारत में जीनोम अनुक्रमण में चुनौतियाँ

- **अति उच्च लक्ष्य:** इसका उद्देश्य कम से कम 5% नमूनों का अनुक्रम करना था, जो वायरस के प्रकारों पर नज़र रखने के लिए न्यूनतम

आवश्यक है।

- यह अब तक केवल 1% के आसपास रहा है, मुख्य रूप से अपर्याप्त अभिकर्मकों और प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरणों के कारण।

- **कम क्षमता:** दस प्रयोगशालाएं एक साथ एक महीने में लगभग 30,000 या एक दिन में 1,000 नमूनों का अनुक्रम कर सकती हैं, जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक से छह गुना कम है।
- **नमूना संग्रह:** स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पहले से ही चरमरा गई है और अनुक्रम सूचना को उपयोगी बनाने के लिए व्यापक मेटाडेटा रिकॉर्ड करने के साथ-साथ कोल्ड चेन में शिपिंग के लिए नमूनों और आरएनए की तैयारी को क्रमबद्ध और पैकेज करना उनके लिए एक अतिरिक्त कार्य है।

जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में:

- यह तीन वर्षों में 10,000 भारतीय मानव जीनोम अनुक्रमित करने और डेटाबेस बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की एक केंद्र समर्थित पहल है।
- **प्रगति और लक्ष्य:** परियोजना ने लगभग 7,000 जीनोम का अनुक्रम किया है और इनमें से 3,000 पहले से ही शोधकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।
- **हितधारक:** पूरे भारत में लगभग 20 संस्थान इस परियोजना में शामिल हैं, हालांकि विश्लेषण और समन्वय सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी), बेंगलोर द्वारा किया जाता है।
- **डेटा संग्रह:** परियोजना के संचालन के लिए, अस्पतालों में जांचकर्ता प्रतिभागियों से एक साधारण रक्त परीक्षण के माध्यम से डेटा संग्रह का नेतृत्व करेंगे और बायोबैंक में जानकारी जोड़ी जाएगी।
- **प्राथमिकता वाले क्षेत्र:** प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सटीक स्वास्थ्य, दुर्लभ आनुवंशिक विकार, भारतीय आबादी में आनुवंशिक और जटिल रोगों के उत्परिवर्तन स्पेक्ट्रम, बहुक्रियाशील जीवन शैली रोगों की आनुवंशिक महामारी विज्ञान और ट्रांसलेशनल रिसर्च शामिल हैं।

परियोजना का महत्व:

- **रोग-आधारित मानव आनुवंशिकी:** 1.3 अरब की भारतीय आबादी में 4,600 से अधिक जनसंख्या समूह शामिल हैं, और उनमें से कई अंतर्विवाही हैं।
 - इन कारकों ने वर्तमान जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता में योगदान दिया है।
 - इस प्रकार, भारतीय आबादी में विभिन्न विविधताएँ हैं और अक्सर इनमें से कुछ समूहों के भीतर कई रोग पैदा करने वाले उत्परिवर्तन बढ़ जाते हैं।
 - इसलिए, दुनिया की अन्य आबादी से जनसंख्या-आधारित या रोग-आधारित मानव आनुवंशिकी अनुसंधान के निष्कर्षों को भारतीयों पर लागू नहीं किया जा सकता है।
- दवाओं और उपचारों को अनुकूलित करने में सहायता: भारतीय जीनोम का एक डेटाबेस बनाने का मतलब है कि कहीं भी शोधकर्ता आनुवंशिक रूपों के बारे में सीख सकते हैं जो भारत के जनसंख्या समूहों के लिए अद्वितीय हैं और दवाओं तथा उपचारों को अनुकूलित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
- यूनाइटेड किंगडम, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों में से हैं जिनके पास अपने जीनोम के कम से कम 1,00,000 अनुक्रमों के लिए कार्यक्रम हैं।
- जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा: यह भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विस्तार करने और अधिक मूल्यवान कंपनियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए भी बढ़ावा देगा।
- **जीनोम-वाइड एसोसिएशन चिप्स की डिजाइनिंग:** यह जीनोम-वाइड एसोसिएशन चिप्स की डिजाइनिंग में सहायता करेगा जो लागत प्रभावी तरीके से बड़े पैमाने पर आनुवंशिक अध्ययन की सुविधा प्रदान करेगा।

आगे की राह :

यह परियोजना ऐतिहासिक रूप से बड़े प्रवासन की श्रृंखला को देखते हुए, भारत को अपनी जबरदस्त आनुवंशिक विविधता पर आकर्षित करने की अनुमति देती है, और इस प्रकार, मानव प्रजातियों के बारे में वर्तमान जानकारी में बहुत कुछ जोड़ती है। यह पहल जीन थेरेपी और सटीक दवा में भारत की प्रगति को दर्शाती है, और अगली पीढ़ी की उभरती हुई दवा की दिशा में इसकी गति को दर्शाती है जो अधिक अनुकूलन, सुरक्षा और पहले पता लगाने की संभावनाएं पैदा करती है।



PRACTICE QUESTIONS



Q.1) भारत के संदर्भ में हंगामे की सूचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
2. यह तब जारी किया जाता है जब इसे लापता व्यक्तियों का पता लगाने, लावारिस शवों की पहचान करने और संदिग्ध की तलाश करने जैसे मामलों में जनता की मदद की आवश्यकता होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

Q.2) महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए एकमुश्त लघु बचत योजना है।
2. यह वित्त मंत्रालय के अधीन होगा।
3. स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट पर दो साल के लिए 7.5 फीसदी की निश्चित ब्याज दर होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

Q.3) निम्नलिखित पर विचार करें:

1. टी.के. माधवन
2. के.पी. केशव मेनन
3. जॉर्ज जोसेफ

उपर्युक्त व्यक्तित्वों में से कौन वैकोम सत्याग्रह से जुड़ा है?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

Q.4) कृषि उड़ान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस योजना का उद्देश्य देश में सभी कृषि उत्पादों के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी, समयबद्ध हवाई परिवहन और संबद्ध रसद सुनिश्चित करना है।
2. यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

Q.5) एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है

- (A) तमिलनाडु
- (B) केरल
- (C) गोवा
- (D) ओडिशा

Q.6) निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

1. ऑस्ट्रेलिया
2. कनाडा
3. यूएसए
4. मलेशिया
5. रूस

उपरोक्त में से कौन सा ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का हिस्सा है?

- (A) केवल 1, 3 और 5
- (B) केवल 2, 3 और 4
- (C) केवल 1, 2 और 4
- (D) 1, 2, 3, 4 और 5

Q.7) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और टाइगर रिजर्व की पहचान करें:

1. इसकी स्थापना 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी।
2. यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रि-जंक्शन क्षेत्र में स्थित है।
3. यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) मुदमलाई टाइगर रिजर्व
- (B) बांदीपुर टाइगर रिजर्व
- (C) कवल टाइगर रिजर्व
- (D) सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व

Q.8) भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें:

1. आयकर
2. सेवा कर
3. न्यूनतम वैकल्पिक कर
4. कैपिटल गेन टैक्स

उपरोक्त में से कौन प्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं?

- (A) केवल 1, 2 और 4
- (B) केवल 2, 3 और 4
- (C) केवल 1, 3 और 4
- (D) 1, 2, 3 और 4

Q.9) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

जीआई टैग आइटम और राज्य

1. बसोहली पेंटिंग - बिहार
2. नागरी दुबराज चावल - ओडिशा
3. लंगड़ा आम- उत्तर प्रदेश

ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित है/हैं?

- (A) केवल एक जोड़ी
- (B) केवल दो जोड़े
- (C) तीनों जोड़े
- (D) कोई नहीं

Q.10) बाबू जगजीवन राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

- (A) उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- (B) ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें 1940 के दशक की शुरुआत में दो बार जेल भेजा गया था।
- (C) वह भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कैबिनेट मंत्री थे।
- (D) सभी कथन सही हैं।

Q.11) निम्नलिखित पास पर विचार करें:

1. जलेप ला (Jalep La)
2. खारदुंग ला
3. नाथू ला
4. बनिहाल दर्रा

उपरोक्त में से कौन सिक्किम में स्थित हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) केवल 2 और 4

Q.12) नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य (Netravali Wildlife Sanctuary) में स्थित समाचारों में अक्सर उल्लेख किया जाता है-

- (A) गोवा
- (B) पश्चिम बंगाल
- (C) ओडिशा
- (D) कर्नाटक

Q.13) संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है जो दुनिया भर के सदस्य राज्यों के मुख्य सांख्यिकीविदों को एक साथ लाता है।
2. इसका मुख्यालय लंदन में है।
3. भारत आयोग का सदस्य है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

Q.14) निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

1. यूनाइटेड किंगडम
2. रूस
3. यूक्रेन
4. फ्रांस
5. फिनलैंड

उपरोक्त में से कौन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के सदस्य हैं?

- (A) केवल 1, 3 और 4
- (B) केवल 1, 4 और 5
- (C) केवल 2, 3 और 5
- (D) केवल 1, 2 और 5

Q.15) परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है-

- (A) कर्नाटक
- (B) तमिलनाडु
- (C) गोवा
- (D) केरल

Q.16) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और आय बढ़ाने के लिए 2015 में यह योजना शुरू की गई थी।
2. इस योजना के तहत ऋण संपार्श्विक-मुक्त ऋण हैं।
3. यह एमएसएमई मंत्रालय के अधीन है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

Q.17) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करें:

1. वह कौशांबी की एक स्वतंत्रता सेनानी थीं।
2. उन्होंने अपनी बचत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी कार्यों पर खर्च किया था।
3. उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आश्रय दिया और बाद में उन्हें लाहौर से बाहर निकाला।
4. वह नौजवान भारत सभा की सक्रिय सदस्या थीं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कूट का चयन करें:

- (A) लक्ष्मी सहगल
- (B) उषा मेहता
- (C) दुर्गा भाभी
- (D) रानी गाइदिन्ल्यू

Q.18) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

महाजनपद	राजधानी
1. वत्स	कौशाम्बी
2. मगध	श्रावस्ती
3. अवन्ति	उज्जैनी या महिष्मती
4. कोशल	राजगृह

ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित है/हैं?

- (A) केवल एक जोड़ी
(B) केवल दो जोड़े
(C) केवल तीन जोड़े
(D) चारों जोड़े

Q.19) राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे 2017 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
2. इसमें डेटा मैपिंग, जनसांख्यिकी निर्माण, प्रक्रियाओं को औपचारिक बनाना और सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को एक में लाना शामिल है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

Q.20) लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी, या LIGO-India परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. LIGO-India भारतीय अनुसंधान संस्थानों के एक संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में LIGO प्रयोगशाला के बीच एक सहयोगी परियोजना है।
2. यह कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित होगा।
3. इसे परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बनाया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

Q.21) राधुनी या जंगली अजवाइन (ट्रेकिस्पर्मम रॉक्सबर्गियानम) अक्सर समाचारों में उल्लिखित होती है, यह है-

- (A) भारत में लोकप्रिय मसाला किस्म
(B) कैंसर के इलाज के लिए औषधीय पौधा
(C) पौधे का कवक रोग गर्मी पैदा करता है
(D) इनमें से कोई भी नहीं

Q.22) रामकृष्ण मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी।

2. मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने, अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई और शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए काम किया।

3. यह सभी धर्मों की एकता और समानता में विश्वास करता था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

Q.23) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

ट्रेड यूनियन और संबंधित व्यक्ति

1. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस - आचार्य जेबी कृपलानी
2. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस - लाला लाजपत राय
3. भारतीय मजदूर संघ - दत्तोपंत ठेंगड़ी

ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित है/हैं?

- (A) कोई नहीं
(B) केवल एक जोड़ी
(C) केवल दो जोड़े
(D) तीनों जोड़े

Q.24) ताइवान जलडमरूमध्य निम्नलिखित में से किस जल निकाय को जोड़ता है?

- (A) दक्षिण चीन सागर और उत्तरी चीन सागर
(B) दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर
(C) थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर
(D) दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर

Q.25) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा योजना है जिसका उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना और पूर्ण बीमा राशि के लिए फसल बीमा दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है।

2. इसे कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है

3. इस योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलें और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

Q.26) सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है

- (A) उत्तराखंड
(B) उत्तर प्रदेश
(C) झारखंड
(D) आंध्र प्रदेश

Q.27) राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2021-22 हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है?

- (A) ऊर्जा मंत्रालय
- (B) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- (C) नीति आयोग
- (D) भारतीय मानक ब्यूरो

Q.28) राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एसडीएल राज्यों द्वारा उनकी बाजार उधार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियां हैं।
2. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ई-कुबेर के माध्यम से एसडीएल की नीलामी की जाती है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

Q.29) भारत की जैव विविधता के संदर्भ में, अमोलॉप्स सिजू, अमोलॉप्स चाणक्य, अमोलॉप्स टेराओर्चिस और अमोलॉप्स तवांग हैं-

- (A) पक्षियों
- (B) नरवानर
- (C) सरीसृप
- (D) उभयचर

Q.30) लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. CII एक सूचकांक है जिसका उपयोग भूमि, भवन, घर, सोने के आभूषण आदि सहित संपत्ति के मूल्य में मुद्रास्फीति-समायोजित वृद्धि की गणना के लिए किया जाता है।
2. CII नंबर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन को निर्धारित करने में सहायता करेगा, जिस पर अगले साल अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय कर का भुगतान करना आवश्यक होता है।
3. इक्विटी म्युचुअल फंड पर LTCG/LTCL की गणना के लिए CII मूल्य का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

Q.31) केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह केंद्र सरकार का एक संगठन है जो नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और प्रीकर्सर केमिकल्स के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है।

2. यह देश के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा विनियमित है।

3. इसका मुख्यालय ग्वालियर में है।

4. यह गृह मंत्रालय से संबद्ध है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 4
- (C) केवल 1 और 3
- (D) केवल 3 और 4

Q.32) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करता है।
2. भारत में कंपनी सचिवों के पेशे को विकसित और विनियमित करने के लिए यह भारत में एकमात्र मान्यता प्राप्त पेशेवर निकाय है।
3. इसका मुख्यालय मुंबई में है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2
- (C) केवल 3
- (D) केवल 1 और 3

Q.33) वह पंजाब के पूर्व सांसद और क्रांतिकारी नेता थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, वह गुरुद्वारों को पतित महंतों (degenerate mahants) से मुक्त कराने के आंदोलन में भाग लेने के लिए अकाली दल में शामिल हो गए। वह एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने PEPSU मुजारा आंदोलन (PEPSU Muzara movement) का नेतृत्व किया था जो 1930 के दशक में शुरू हुआ था और बिस्वेदरी व्यवस्था के खिलाफ 1952 तक चला था। उन्होंने विभाजन के दौरान सैकड़ों मुसलमानों को सांप्रदायिक दंगों से बचाया। किसान सभा के एक प्रमुख नेता होने के नाते, सरकार और जमींदारों के खिलाफ कई किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया।

उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसने वर्णित किया है?

- (A) लाला लाजपत राय
- (B) भगत सिंह
- (C) तेजा सिंह सुतंतार
- (D) इनमें से कोई भी नहीं

Q.34) न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग से संबंधित समाचारों में अक्सर उल्लेख किया जाता है

- (A) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक
- (B) आर्थिक कमजोर वर्ग
- (C) अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान
- (D) अनुसूचित जनजातियों की स्थिति का अध्ययन करना

Q.35) निम्नलिखित में से कौन सा देश ओरियन अभ्यास का भागीदार नहीं है?

- (A) नीदरलैंड
(B) स्पेन
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका
(D) चीन

Q.36) उत्तरमेरु शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना पल्लव राजा नंदिवर्मन द्वितीय ने की थी।
2. शिलालेख वार्डों के गठन, चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवारों की योग्यता, अयोग्यता मानदंड, चुनाव के तरीके के बारे में आश्चर्यजनक विवरण देता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

Q.37) अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आईसीएओ को 200 राष्ट्रीय सरकारों द्वारा हवाई परिवहन में उनकी कूटनीति और सहयोग का समर्थन करने के लिए वित्त पोषित और निर्देशित किया जाता है।
2. शिकागो कन्वेंशन ने हवाई मार्ग से अंतरराष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले मूल सिद्धांतों की स्थापना की और आईसीएओ के निर्माण का नेतृत्व किया।
3. भारत शिकागो कन्वेंशन का हिस्सा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 3

Q.38) जायंट मैग्नेटोरेसिस्टेंस (GMR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक बाहरी रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र में अपने विद्युत प्रतिरोध के मान को बदलने के लिए एक सामग्री (अक्सर फेरोमैग्नेटिक) की प्रवृत्ति है।
2. इसका उपयोग हार्ड डिस्क ड्राइव, कंप्यूटर, बायोसेंसर, ऑटोमोटिव सेंसर, माइक्रोइलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और मेडिकल इमेजर्स में किया जाता है।
3. जीएमआर-आधारित उपकरण विशेष रूप से चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

Q.39) डॉ बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस घटना/संगठन से जुड़े हैं?

1. बहिष्कृत हितकारिणी सभा
2. महाड सत्याग्रह
3. पूना पैक्ट

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) 1 2 और 3
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 1 और 3

Q.40) बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है

- (A) झारखंड
(B) छत्तीसगढ़
(C) महाराष्ट्र
(D) ओडिशा

Q.41) निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. जापान
3. भारत
4. चीन
5. फ्रांस

उपरोक्त में से कौन G7 समूह के सदस्य हैं?

- (A) केवल 1, 3 और 4
(B) केवल 1, 4 और 5
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) केवल 1, 2 और 5

Q.42) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- (A) PMJJBY स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक बीमा योजना है।
(B) योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
(C) यह योजना जीवन बीमा निगम द्वारा ही दी जा रही है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 3
(D) केवल 1 और 3

Q.43) प्रसिद्ध आई आर कोएल्हो (I R Coelho) बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला किससे संबंधित है

- (A) नौवीं अनुसूची
(B) दलबदल विरोधी
(C) छठी अनुसूची
(D) अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण

Q.44) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

बौद्ध परिषद और बैठक का स्थान

1. प्रथम बौद्ध संगीति - वैशाली
2. द्वितीय बौद्ध संगीति- राजगृह
3. तृतीय बौद्ध संगीति - पाटलिपुत्र
4. चतुर्थ बौद्ध संगीति- कुंडलवन

ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित हैं/हैं?

- (A) केवल एक जोड़ी
- (B) केवल दो जोड़े
- (C) केवल तीन जोड़े
- (D) चारों जोड़े

Q.45) सुपरक्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सुपरक्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) CO₂ की एक द्रव अवस्था है जहाँ इसे गर्म किया जाता है और इसके महत्वपूर्ण तापमान (31°C) और दबाव (73 atm) पर या उससे ऊपर रखा जाता है।
 2. इसका उपयोग तेल और गैस उद्योग में बढ़ी हुई तेल रिकवरी (ईओआर) तकनीकों के दौरान गैस इंजेक्शन के लिए किया जाता है।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

Q.46) कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में स्थित समाचारों में प्रायः उल्लेख किया जाता है

- (A) राजस्थान
- (B) पश्चिम बंगाल
- (C) कर्नाटक
- (D) ओडिशा

Q.47) ब्लास्टोमाइकोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह ब्लास्टोमाइकोसिस के कारण होने वाला एक कवक रोग है
 2. कवक वातावरण में रहता है, विशेष रूप से नम मिट्टी में और सड़ने वाले पदार्थ जैसे लकड़ी और पत्तियों में।
 3. यह वायुजनित रोग है
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 1 और 3
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2 और 3

Q.48) सीमित प्रयोजन समाशोधन निगम (LPCC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एलपीसीसी आरबीआई द्वारा स्थापित एक इकाई है।
2. यह रेपो दर लेनदेन के समाशोधन और निपटान की गतिविधि करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

Q.49) विश्व जनसंख्या की स्थिति (SOWP) 2022 रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई

- (A) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
- (B) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
- (C) नीति आयोग
- (D) विश्व आर्थिक मंच

Q.50) 'E-2025 इनिशिएटिव' और हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट (HBHI) को खत्म करने के लिए शुरू की गई WHO की पहल हैं-

- (A) यक्ष्मा
- (B) मलेरिया
- (C) डेंगू
- (D) पोलियो

Q.51) राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है।
 2. इसका गठन 1985 में बीरबल नाथ समिति की सिफारिश पर प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

Q.52) वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है

- (A) संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन
- (B) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
- (C) अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान
- (D) इनमें से कोई भी नहीं

Q.53) कामाख्या मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह असम में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है।
 2. इसे भारत के सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक माना जाता है।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2

Q.54) ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है।
2. यह पांच चरणों वाला प्रक्षेपण यान है।
3. यह लिक्विड स्टेज से लैस होने वाला पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 1
- (C) केवल 3
- (D) केवल 1 और 3

Q.55) गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है-

- (A) राजस्थान
- (B) मध्य प्रदेश
- (C) हरियाणा
- (D) पश्चिम बंगाल

Q.56) निम्नलिखित में से कौन से देश कैरेबियन समुदाय और कॉमन मार्केट (CARICOM) के सदस्य हैं:

1. एंटीगुआ और बारबुडा
2. बहामास
3. बेलीज
4. गुयाना
5. जमैका

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) केवल 1, 2 और 4
- (B) केवल 2, 3 और 5
- (C) केवल 1, 4 और 5
- (D) ऊपर के सभी

Q.57) लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है।

- (A) विश्व व्यापार संगठन
- (B) विश्व आर्थिक मंच
- (C) विश्व बैंक
- (D) UNCTAD

Q.58) क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) कानून में बाजार का अक्सर द्वारा अनुमोदित समाचारों में उल्लेख किया जाता है-

- (A) विश्व बैंक
- (B) यूरोपीय संघ
- (C) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- (D) BRICS

Q.59) आम और अन्य फलों के लिए अक्सर कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग पकाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है?

1. पॉलीविनाइल क्लोराइड
2. एसिटिलीन
3. कैल्शियम साइनामाइड
4. कार्बाइड लैंप

5. बाँस की तोपें (Bamboo cannons)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (A) केवल 1, 3 और 4
- (B) केवल 2, 4 और 5
- (C) केवल 1, 3 और 5
- (D) ऊपर के सभी

Q.60) व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (SVEEP) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. स्वीप भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है।
 2. यह मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता फैलाने और भारत में मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए है।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल 1
 - (B) केवल 2
 - (C) 1 और 2 दोनों
 - (D) न तो 1 और न ही 2

Q.61) स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी (SWAGAT) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गुजरात सरकार की स्वागत पहल 2003 में शुरू की गई थी।
 2. यह एक अभिनव अवधारणा है जो नागरिकों और मुख्यमंत्री के बीच सीधे संवाद को सक्षम बनाती है।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल 1
 - (B) केवल 2
 - (C) 1 और 2 दोनों
 - (D) न तो 1 और न ही 2

Q.62) हाल ही में, राज्य वित्त: 2022-23 रिपोर्ट के बजट का एक अध्ययन किसके द्वारा शुरू किया गया था?

- (A) भारतीय रिजर्व बैंक
- (B) वित्त मंत्रित्व
- (C) नीति आयोग
- (D) इनमें से कोई भी नहीं

Q.63) मिसइंफॉर्मेशन कॉम्बैट एलायंस (MCA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एमसीए मार्च 2022 में स्थापित मीडिया कंपनियों का गठबंधन है।
2. इसकी स्थापना गलत सूचनाओं से निपटने और तथ्य-जांच में सहायता के लिए उपकरण बनाने के लिए की गई थी।
3. एमसीए में सदस्यता लागू होने वाले किसी भी संगठन के लिए खुली है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

Q.64) थिरुनेली मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह तीन नदियों के संगम पर स्थित है - पापनासिनी, कुदामुरुट्टी और कूथपुडुआ।
2. यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भक्त जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद के जीवन से संबंधित सभी अनुष्ठान कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

Q.65) नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच (UNPFII) के संबंध में सही नहीं है?

- (A) यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है।
(B) इसे आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से संबंधित स्वदेशी मुद्दों से निपटने का अधिकार है।
(C) यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फ़ोरम ऑन इंडीजिनस इश्यूज (UNPFII) का 22वां सत्र 17 से 28 अप्रैल 2023 तक न्यूयॉर्क में आयोजित होगा।
(D) इसका विषय है "' स्वदेशी लोग, व्यवसाय, स्वायत्तता और स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति सहित उचित परिश्रम के मानवाधिकार सिद्धांत"।

Q.66) मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है

- (A) केरल
(B) ओडिशा
(C) तमिलनाडु
(D) तेलंगाना

Q.67) निम्नलिखित देशों पर विचार करें:

1. बेल्जियम
2. स्वीडन
3. फ्रांस
4. फिनलैंड
5. यूनाइटेड किंगडम

उपरोक्त में से किस देश की सीमा उत्तरी सागर से लगती है?

- (A) केवल 1 3 और 4
(B) केवल 2 4 और 5
(C) केवल 1 3 और 5
(D) ऊपर के सभी

Q.68) अपग्रेडेशन प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट (SUPREME) पहल के लिए समर्थन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह मौजूदा विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मरम्मत, उन्नयन, रखरखाव, रेट्रोफिटिंग या अतिरिक्त संलग्नक प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2. यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

Q.69) भारत की परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

- (A) भारत पूरक मुआवजे (Supplementary Compensation) पर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है जो यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों को परमाणु घटना या आपदा के कारण हुई परमाणु क्षति के लिए मुआवजा उपलब्ध है।
(B) भारत के पास अभी 25 परमाणु रिएक्टर हैं।
(C) सभी मौजूदा रिएक्टर राज्य के स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा संचालित हैं।
(D) एनपीसीआईएल भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई) के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

Q.70) सूचनाओं का स्वचालित आदान-प्रदान (AEOI) ढांचा और क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF) अक्सर समाचारों में उल्लिखित पहल हैं-

- (A) विश्व बैंक
(B) विश्व आर्थिक मंच
(C) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
(D) यूरोपीय संघ

Q.71) रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत में कुश्ती की शासी निकाय है।
2. इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।
3. यह यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) से संबद्धता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

Q.72) सुखना वन्यजीव अभयारण्य स्थित है-

- (A) उत्तर प्रदेश
(B) हरयाणा
(C) गुजरात
(D) ओडिशा

Key Answers

1	b	16	A	31	a	46	c	61	c
2	c	17	C	32	b	47	d	62	a
3	d	18	B	33	c	48	b	63	d
4	a	19	B	34	a	49	a	64	c
5	b	20	C	35	d	50	b	65	d
6	c	21	A	36	c	51	a	66	c
7	b	22	D	37	c	52	c	67	c
8	c	23	B	38	d	53	c	68	a
9	a	24	D	39	a	54	d	69	b
10	d	25	C	40	b	55	b	70	c
11	c	26	B	41	d	56	d	71	c
12	a	27	A	42	b	57	d	72	b
13	c	28	A	43	a	58	b		
14	b	29	D	44	b	59	d		
15	d	30	C	45	c	60	c		

IAS BABA



Extended Portal
access upto
2025 Prelims

babā's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....



& Much more.....

ADMISSION OPEN

📍 **Bangalore** 📍 **Delhi** 📍 **Online**

Scan Here



to Know More



www.iasbaba.com



support@iasbaba.com



91691 91888